हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 मार्च, सोमवार, 2010

खण्ड-1, अंक-7

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

विषय सूची

सोमवार, 15 मार्च, 2010

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	(7) 7
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(7) 7
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(7) 22
अनुपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना	(7) 33
श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के विरुद्ध अभिकथित विशेषाधिकार भंग का प्रश्न	(7) 33
वाक आउट	(7) 36
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं	(7) 36
वर्ष 2010-2011 के लिए बजट पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(7) 37
बैठक का स्थगन	(7) 64
वर्ष 2010-2011 के लिए बजट पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(7) 66

मूल्य : 167

बैठक का समय बढ़ाना	(7) 79
वर्ष 2010-2011 के लिए बजट पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(7) 79
बैठक का समय बढ़ाना	(7) 88
वर्ष 2010-2011 के लिए बजट पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(7) 88
बजट 2010-2011 के अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(7) 92
बैठक का समय बढ़ाना	(7) 104
बजट 2010-2011 के अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(7) 104
बैठक का समय बढ़ाना	(7) 112
वित्त मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य	(7) 112

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 15 मार्च, 2010

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 2.00 बजे मध्याह्न पश्चात हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Chief Minister will make the obituary references.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, इस सत्र के दौरान हमारे एक पूर्व सदस्य और एक स्वतंत्रता सेनानी हमें छोड़कर चले गये। इस बारे में मैं एक शोक प्रस्ताव सदन के समक्ष रखना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य चौधरी अब्दुर्रज़ाक के 8 मार्च, 2010 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 10 अक्तूबर, 1928 को हुआ। वह 1968 तथा 1972 में हरियाणा विधान सभा के लिए चुने गये। वह एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, यह सदन जिला फरीदाबाद के स्वतन्त्रता सेनानी, श्री मूलचन्द वर्मा के 7 मार्च, 2010 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

इनके निधन से देश एक महान् स्वतन्त्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा (थानेसर) : स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने जो शोक प्रस्ताव रखा है मैं भी उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। चौधरी अब्दुर्रज़ाक जो भूतपूर्व विधायक थे उनके साथ मुझे भी काम करने का काफी लम्बे समय तक मौका मिला। वे एक नेक इन्सान थे। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। इसी प्रकार से स्वतन्त्रता सेनानी श्री मूलचन्द वर्मा के निधन पर भी मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे साथी श्री शेर सिंह जी के भतीजे श्री जरनैल सिंह जी का भी निधन हो गया है। उनका नाम भी इन शोक-प्रस्तावों की सूची में जोड़ लिया जाए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी आपसे अनुरोध है कि हमारे साथी श्री शेर सिंह जी के भतीजे श्री जरनैल सिंह जी का भी निधन हो गया है। इसलिए उनका नाम भी इन शोक-प्रस्तावों की सूची में जोड़ लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, उनका नाम भी शोक प्रस्ताव की सूची में जोड़ लिया जाएगा।

Hon'ble Members, I associate myself with the Obituary References made by Hon'ble Chief Minister and the feelings expressed by other Members of the House. I feel sorrow on the sad demise of Chaudhary Abdur Razzaque who was elected to the House from Firozepur Zhirka Assembly Constituency twice. He served his constituency at the root level and made untiring efforts for the development of his area. He was a great social worker and in his death the State and particularly the Mewat area has lost a great social worker.

I also feel sorrow on the sad demise of Shri Mool Chand Verma, Freedom Fighter of District Faridabad. He was a great freedom fighter. I pray to Almighty to give peace to the departed souls. I will convey the feelings of this House to the bereaved families.

Mr. Speaker : Now, I request all of you to kindly stand up to pay homage to the departed souls for two minutes.

(At this stage the House stood in silence for two minutes as a mark of respect to the memory of deceased).

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Question Hour starts.

To Open a Medical Institute

*** 183 Shri Devender Kumar Bansal :** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Medical Institute like Apollo, Fortis or PGI at Panchkula to provide better medical facilities to the residents of Panchkula and its surroundings ?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : No, Sir.

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं कि पंचकूला एक मैट्रोपोलिटन सिटी है। पिछले चार पांच सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पंचकूला के विकास के लिए 300 करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं। पंचकूला में बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं। पंचकूला में प्रोसीक्यूशन की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का उद्घाटन अभी पीछे मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। पूरे भारत वर्ष में पंचकूला में बनी प्रोसीक्यूशन की यह बिल्डिंग सबसे बड़ी पहली बिल्डिंग है। पंचकूला में 5 लाख छोटे - बड़े अधिकारी, कर्मचारी, एम.एल.एज. और मंत्री रहते हैं। पंचकूला के लोगों को मैडीकल एड के लिए बाहर चंडीगढ़ और मोहाली में जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में पंचकूला में कोई बड़ा मैडीकल इंस्टीच्यूट बनाने की सरकार की कोई योजना है ?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukal Matanhail) : Speaker Sir, health is the priority agenda of our State Government. Though, my Hon'ble

Member has asked about the proposal to establish Medical Institute like Apollo, Fortis or PGI. There is no proposal to establish a medical institute like Apollo, Fortis or PGI, yet. The Government has decided to strengthen the secondary care facilities at Panchkula by upgrading the General Hospital Panchkula to a 200 bedded hospital as per Indian Public Health Standards defining the level of the services, manpower and infrastructure. It has largest number of doctors posted and is providing very good standard of health care as is evident from the number of surgeries and OPD. Speaker Sir, in General Hospital Panchkula, we are having specialists in OPD services like Physician, Surgeon, Orthopedician, Gynecologist, Anesthetist, Pediatrician, Dermatologist, Ophthalmologist, ENT specialist, Psychiatrist, Radiologist, Physiotherapist, Dental Surgeon, Pathologist, Microbiologist, Indoor services and 24 X 7 Emergency services are being provided by specialists (physician, Surgeon, Orthopedician, Gynecologist, Pediatrician, Radiologist). Special Evening OPD Services are there at General Hospital Panchkula. Around 200-300 patients visit daily in the evening OPD. CT Scan facility is also available there. Intensive Care Unit is there. Speaker Sir, AYUSH is also there like Homoeopathy, Yoga and Ayurveda.

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, पंचकूला का सिविल अस्पताल बहुत अच्छा है परन्तु मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि इस अस्पताल को और ज्यादा स्ट्रैंग्थन करने के लिए कितना बजट रखा गया है ?

Smt. Geeta Bhukal Matanhail : Mr. Speaker Sir, I would like to tell my Hon'ble Member that it was decided to upgrade the General Hospital Panchkula to match the Indian Public Health Standards. National Building Construction Corporation (NBCC), New Delhi was asked to submit the detailed project report. The estimated cost as submitted by NBCC is Rs. 12.48 crores for the existing block and Rs. 14.00/- crores for the left over work in the new block i.e. total of Rs. 26.48/- crores.

चौ. अफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि हमारे पिछड़े क्षेत्र मेवात के लिए हैल्थ के क्षेत्र में सरकार क्या क्या कार्य कर रही है ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल: अध्यक्ष महोदय, मेवात हैल्थ सर्विसिज के मामले में बहुत ही पिछड़े क्षेत्रों में से है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को और माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि इस समय First phase of 100 seats and 500 bedded hospital at an estimated cost of Rs. 389.43 crores at Nalhar (Mewat) is under consideration. इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहती हूं कि हमारे लीडर आफ दि अपोजिशन ने बजट स्पीच में कहा है कि हरियाणा सरकार ने 5 साल के दौरान कोई भी नया अस्पताल हरियाणा स्टेट के लिए नहीं बनाया। Speaker Sir, our Government is committed and our Chief Minister wants to do as much as for good health services, and infrastructure development. Health sector has been major focus of the State Government for the last five years. Many unprecedented steps have been taken in this regard. The State Government has taken historic steps for setting up three Medical Colleges, one at Khanpur Kalon, Distt. Sonepat 100 seats with 500 - bedded hospital and other at Nalhar (Mewat) 100 seats with 500 bedded hospital at an estimated cost of

[श्रीमती गीता भुक्कल]

Rs. 389.43 crores. As, I have said earlier one is Kalpana Chawla Medical College at Karnal with 50 seats and 300 bedded hospital within a cost of Rs. 200/- crores. This is the first time after the establishment of PGI at Rohtak that three Medical Colleges alongwith hospitals are being set up by the Government and these colleges will create 200 additional seats for M.B.B.S. courses.

Further one medical college with the hospital is being setup by the ESI at Faridabad also. Speaker Sir, one more information was also given in the Budget. Around 150 crores of Rupees we are getting from Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojna for PGI, Rohtak and there is a second extension of AIMS in Jhajjar also.

श्री प्रदीप चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि पंचकुला के अंदर रायपुर रानी में सी.एच.सी. है। जिस पर करीबन 1.20 लाख की आबादी निर्भर करती है और वहां पर आपरेशन की कोई सुविधा नहीं है। यदि किसी मरीज को सफेद मोतिया के लिए आंख का आपरेशन, हड्डियों का आपरेशन या सीजेरियन आपरेशन करवाना होता है तो उसके लिए डाक्टर मरीज को पंचकुला लेकर आते हैं जो कि 35-40 कि.मी. की दूरी पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त वहां की एक्सरे मशीन भी खराब है, केवल छाती के एक्सरे के अलावा दूसरा एक्सरा नहीं होता। क्या मंत्री महोदया के पास रायपुर रानी की सी.एच.सी. में सुधार के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगी कि रायपुर रानी की सी.एच.सी. के नार्म्ज एग्जामिन करवा रहे हैं और अति शीघ्र ही इनकी समस्या का समाधान किया जायेगा।

Smt Kiran Choudhary : Speaker Sir, I am very happy and thankful to the Hon'ble Chief Minister that so much of money has been allocated to our health and health is the priority sector of the Government. I would like to ask the Hon'ble Minister apart from the Kalpna Chawla Medical College at Karnal and AIIMS Phase II at Jhajjar, is there any other proposal they have sent to the Government of India for more AIIMS hospitals to be brought into Haryana or not? Speaker Sir, we have time to again ask for a medical college to be established at Bhiwani because Bhiwani is a backward place and it is very important आज जो भिवानी के अंदर चौधरी बंसी लाल जी के नाम से हॉस्पिटल चल रहा है वह काफी पुराना हो गया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मैडम, आप तो भाषण दे रही हैं। प्लीज आप बैठें। आपका सवाल हो गया है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं भाषण नहीं दे रही, सप्लीमैंटरी ही पूछ रही हूं।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने चौधरी बंसी लाल हॉस्पिटल, भिवानी के बारे में चर्चा की है। इस बारे में मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगी कि वहां पर 300 बैड का हॉस्पिटल बहुत अच्छी कंडीशन में चल रहा है। उसमें सारी की सारी वैकेंसिज भरी हुई हैं। इसके अलावा हमारा जो अंडर स्टेट स्टीमूल्स पैकेज है उसके तहत भिवानी को इस बार 2258.68 लाख रूपये दिए गए हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने अपने जवाब में कहा है कि भिवानी का हॉस्पिटल बहुत अच्छी तरह से चल रहा है इस बारे में मैं बताना चाहूँगी कि वहां पर एक्सरे मशीन खराब है और न ही वहां पर दवाईयां मिल रही हैं। वहां पर आयोडीन भी नहीं है।

Mr. Speaker: Kiran ji, this is not the way. ऐसे नहीं होता।

श्री जगदीश नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, हमारा एरिया यू.पी. के साथ लगता है। वहां पर हसनपुर की सी.एच.सी. की हालत बहुत खराब है। वहां पर किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। क्या मंत्री महोदया बतायेंगी कि हसनपुर की सी.एच.सी. में नई सुविधाएं देने के लिए मामला विचाराधीन है ?

Smt. Geeta Bhukal Matanhail : Speaker Sir, this is a separate question. इसके लिए माननीय सदस्य लिखकर भिजवा दें इनको जवाब दे दिया जायेगा।

New Building for Civil Hospital, Ambala Cantt

***29 Shri Anil Vij :** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct new building for Civil Hospital, Ambala Cantt; if so, the time by which the said building is likely to be constructed ?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : No, Sir, However, administrative approval of Rs. 78.98 Lacs has been issued for the special repair of Civil Hospital, Ambala Cantt.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, सबसे पहले तो मैं पूरे सदन को विक्रमी संवत 2067 कल से आरंभ हो रहा है उसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। यह नया साल है इसमें हमारा प्रदेश तरक्की करे इसके लिए सभी को शुभकामनाएं। स्पीकर सर, अब मैं सप्लीमैंटरी पर आता हूं कि अब वर्ष 2010 चल रहा है लेकिन यदि अंबाला छावनी के सिविल हॉस्पिटल में जाकर देखें तो लगता है कि हम 1857 में आ गये हैं।

स्पीकर सर, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हैल्थ मिनिस्टर महोदया ने भी बताया कि कल्पना चावला हॉस्पिटल खोला जा रहा है और इसके अलावा भी प्रदेश में नये हॉस्पिटल्ज बनाये जा रहे हैं। इसके साथ-साथ हॉस्पिटल्ज को अपग्रेड भी किया जा रहा है लेकिन हमारे अम्बाला कैंट का जो हॉस्पिटल है वह जैसा अंग्रेजों ने छावनी बसाने के समय बनाया था अभी भी वैसे का वैसा ही है। कोई भी वहां पर जाकर उसकी हालत को देख सकता है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी रिकवैस्ट करूंगा कि वे कम से कम एक बार अम्बाला छावनी के हॉस्पिटल की विजिट अवश्य करें। पिछली सरकार के समय में अम्बाला छावनी के हॉस्पिटल के लिए मास्टर प्लान बनी थी जिसके तहत पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही नये सिरे से बनाने का प्रावधान था। इस काम के लिए सारी बिल्डिंग के नक्शे भी बने थे। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि जो इस काम के लिए 78.98 लाख रूपये स्वीकृत किये गये हैं क्या उन्हें पूर्व में बने मास्टर प्लान के अनुसार कार्य आरम्भ करके खर्च किया जायेगा या इन्हें भी पीस-मील में लगाते जायेंगे ? अगर ऐसा होता है तो यह सारी धनराशि भी बेकार चली जायेगी। अम्बाला छावनी के हॉस्पिटल में कहीं पर लेबोरेट्री बनी हुई है और कहीं पर एमरजैंसी वार्ड बना हुआ है। कुल मिलाकर मैं यही पूछना चाहता हूं कि जो मास्टर प्लान बना था क्या उसी के

[श्री अनिल विज]
ऊपर कार्य आरम्भ किया जायेगा या कि इस पैसे को भी पहले की तरह ऐसे ही यूज कर लिया जायेगा और बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाली बात हो जायेगी ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, माननीय सदस्य की चिंता बिल्कुल वाजिब है। अम्बाला कैंट के हॉस्पिटल की बिल्डिंग वाकई काफी पुरानी है क्योंकि खैराती हॉस्पिटल की बिल्डिंग सन् 1944 में बनी थी। इसकी हालत काफी खराब है। मैं जनरल हॉस्पिटल अम्बाला कैंट के सभी रिपेयर वर्क के बारे में बताना चाहूंगी कि इसमें हम एक ओ.पी.डी. ब्लॉक, प्राईवेट वार्ड, मैटरनिटी वार्ड, आपरेशन थिएटर, मैंटल वार्ड, एमरजैंसी ब्लॉक, रेजिंग ऑफ दी फ्लोरिंग आदि बनवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसमें री-टाईलिंग, टैरेसिंग, बाऊंडरी वॉल और एप्रोच रोड भी बना रहे हैं। स्पीकर सर, जनरल हॉस्पिटल, अम्बाला कैंट के तमाम रिपेयर वर्क्स की एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल हो चुकी है। इसके अलावा भी अगर कुछ काम रह गया होगा तो उसको हम एक कमेटी बनाकर एग्जामिन करवा लेंगे। माननीय सदस्य ने यह भी ठीक कहा है कि इसके जो ब्लॉक्स हैं वे अलग-अलग जगह पर बने हुए हैं जैसे ऑपरेशन थिएटर कहीं पर है और वार्डज कहीं पर हैं। विशेष तौर पर यहां हमें बाढ़ के समय में बहुत ज्यादा समस्यायें पेश आती हैं। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यही आश्वासन देना चाहूंगी कि हम जनरल हॉस्पिटल, अम्बाला कैंट की जो समस्यायें हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र एग्जामिन करवाकर दूर करेंगे।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मंत्री महोदया ने जो जवाब दिया वह बहुत अच्छा है। मैं इसके लिए इनकी सराहना करता हूं और हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने कहे को जल्दी ही पूरा कर देंगी। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पुन: रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि वे उसको एक बार जाकर जरूर देखें। मेरा दूसरा सप्लीमैंट्री यह है कि हमारी पिछली सरकार के समय में अम्बाला कैंट में एक ट्रामा सैंटर बनाने की मंजूरी सरकार द्वारा प्रदान की गई थी लेकिन जब सरकार बदल गई तो उस ट्रामा सैंटर को अम्बाला कैंट के बजाय अम्बाला शहर में बना दिया गया। स्पीकर सर, मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा कारण हो गया था कि सरकार को इस ट्रामा सैंटर को अम्बाला छावनी के बदले अम्बाला शहर में बनाना पड़ा ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगी कि जैसा हमारे अम्बाला कैंट के हॉस्पिटल में काफी समस्यायें हैं जो कि माननीय सदस्य ने भी माना है। वहां पर हमारी बैड ऑक्यूपैंसी भी काफी कम है जो कि वर्ष 2007 में 42 प्रतिशत, वर्ष 2008 में 36 प्रतिशत और वर्ष 2009 में 41 प्रतिशत रही है। जो इन्होंने ट्रामा सैंटर की बात पूछी है, इस बारे में मैं इनको बताना चाहूंगी कि इस समय जिला अम्बाला में हैल्थ इंस्टीच्युशंज को लेकर हम काफी सजग हैं। मैं माननीय साथी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि एक जनरल हॉस्पिटल, अम्बाला शहर में है और एक 75 बैडिड जनरल हॉस्पिटल अम्बाला कैंट में है, जिसका हम अतिशीघ्र सुधार करने वाले हैं। इसी तरह से एक 50 बैडिड जनरल हॉस्पिटल नारायणगढ़ में है और वहां एक टी.बी. हॉस्पिटल भी है जिसका भी सुधार किया जायेगा। जहां तक ट्रामा सैंटर की बात है यह ठीक है कि यह ट्रामा सैंटर वाकई अम्बाला शहर में बन गया है। इसके अलावा जिला अम्बाला में हमारी 18 पी.एच.सीज. चल रही हैं और क्रमश: चौड़मस्तपुर, मुलाना, शहजादपुर और बराड़ा में चार सी.एच.सीज. चल रही हैं। इसके साथ-साथ एक सिविल डिस्पैंसरी बलदेव नगर में भी चल रही है और इसी प्रकार से हमारे लगभग 100 हैल्थ सब-सैंटर चल रहे हैं।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मेरे सवाल का सही जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप दो सप्लीमैंट्री पूछ चुके हैं इसलिए अब आप कृपा बैठ जाईये।

श्री आनंद सिंह दांगी : स्पीकर सर, सी.एच.सी., मदीना की बिल्डिंग काफी जर्जर हो चुकी है जिसे पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा भी कंडम घोषित किया जा चुका है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास दोबारा से सी.एच.सी., मदीना की बिल्डिंग बनाने की कोई प्रपोज़ल है ? मेरा दूसरा सप्लीमैंट्री यह है कि जनरल हॉस्पिटल, महम की बिल्डिंग सरकार द्वारा जनरल हॉस्पिटल्ज़ की बिल्डिंग्स के लिए निर्धारित किए गए नॉर्म्ज़ के अनुसार नहीं है। इसलिए मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि क्या जनरल हॉस्पिटल, महम की बिल्डिंग को एक्सटैंड करके निर्धारित नॉर्म्ज़ के मुताबिक बनाने का कोई प्रावधान सरकार के पास है ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि जो हमारी सी.एच.सी. मदीना की बिल्डिंग है, उसको कंडम घोषित कर दिया गया है और हम बहुत शीघ्र उसको नया बनवा देंगे। इसके अलावा महम का जो सी.एच.सी. से 50 बैड का जनरल हॉस्पीटल बना है उसमें जो कमियाँ हैं उनको भी पूरा करवा दिया जायेगा।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने दादरी में पहली बार 50 बैड के हॉस्पिटल को 100 बैड तक अपग्रेड कर दिया है। दादरी में दो हॉस्पिटल हैं एक तो पुराना हॉस्पिटल था जो फ्लड के समय डैमेज हो गया था। दूसरा हॉस्पिटल बाहर बना हुआ है जिसकी जमीन का कोई विवाद है जिसको कि 15 बीघा या 15 एकड़ बताया जा रहा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो 100 बैड का हॉस्पिटल बनाया जायेगा वह कौन सी जगह बनाया जायेगा ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि माननीय मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने दादरी में 100 बैड के हॉस्पिटल को बनाने के लिए बजट में पैसों का प्रावधान रखा गया है। माननीय सदस्य की समस्या जायज है। दादरी में जो पुराना हॉस्पिटल था उसकी हालत काफी खराब थी इसलिए उस 50 बैडिड हॉस्पिटल को उधम सिंह जैन हॉस्पिटल जो कि उधम सिंह जैन ट्रस्ट का हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। अभी तक वह बिल्डिंग हैल्थ डिपार्टमैंट को ट्रांसफर नहीं हुई है। माननीय सदस्य से हमने बात भी की है और यह प्रयास किया जायेगा कि जैसे ही हैल्थ विभाग को वह बिल्डिंग ट्रांसफर हो जायेगी उसी समय वहीं पर हम ये 100 बैड का हॉस्पिटल बनायेंगे क्योंकि पुरानी जगह पर जगह बहुत कम है।

श्री विनोद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ट्रॉमा सैन्टर अम्बाला शहर को दिया है और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य श्री अनिल विज को भी आक्षेप नहीं है, उनको कोई ऐतराज नहीं है कि वहाँ क्यों बना है बल्कि इनको भी खुशी है कि इनके पास एक ट्रॉमा सैन्टर बना है।

श्री अनिल विज : एक ट्रामा सैन्टर हमारे लिये बनना था वह भी शर्मा जी छीन ले गये।

श्री विनोद शर्मा : विज साहब मैं आपकी बात से सहमत हूँ लेकिन मैं आपको अन्तर बताना चाहता हूँ कि पिछली सरकार घोषणाएं करती थी लेकिन इस सरकार में काम करने का नाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि ट्रामा सैन्टर एक अच्छा अदायरा बना है और वहाँ पर क्या डायलासिस का प्रावधान किया जायेगा ? दूसरी बात यह है कि क्या वहाँ पर ब्लड बैंक की सुविधा भी प्रदान की जायेगी क्योंकि ट्रामा सैन्टर में एक्सीडैंटल केसिज ज्यादा आते हैं जिन में ब्लड की जरूरत पड़ती है।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि जनरल हॉस्पिटल अम्बाला शहर में हमने हर सुविधायें देने का प्रयास किया है। बाकी जो डायलासिस और ब्लड बैंक की सुविधाओं की बात है तो मैं माननीय सदस्य को कनफर्म करके बता दूंगी।

श्री अनिल धंतौड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि साढे तीन महीने पूर्व हमारी सरकार ने हरियाणा में 102 नम्बर ऐम्बूलैंस बस सर्विस शुरू की है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या इसमें एस.सी./बी.सी. व बी.पी.एल. धारकों के लिए कोई विशेष सुविधा प्रदान की गई है ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह पृथक प्रश्न है लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि 102 रेफरल वैन सिस्टम हमारी सरकार का एक बहुत अच्छा प्रयास है जिसमें कि 102 नम्बर डायल करने पर विशेष तौर से हमारी गर्भवती महिलाओं के लिए और एक्सीडैंटल केस में वैन तुरन्त उपलब्ध हो जाती है। इसमें एस.सी./बी.सी. और बी.पी.एल. धारकों के लिए यह सुविधा मुफ्त उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे भूतपूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी यह सुविधा मुफ्त है। हर जिले में 15 से 18 तक 102 रैफरल वैन हमने मुहैया करवाई हैं। यह सुविधा इस समय हरियाणा में बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। जी.पी.एस. सिस्टम फिट होने के कारण बहुत जल्दी वैन की लोकेशन भी आसानी से पता चल जाती है और आपातकाल में एक ही कॉल पर वैन उपलब्ध हो जाती है।

श्री नरेन्द्र सांगवान : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री महोदया जी से कहना चाहूंगा कि हमारे बरोंडा में 25 बैड का हास्पिटल है उसकी हालत बहुत ही खराब है और वहां पर जो एस.एम.ओ. बैठता है वह वहीं पर बैठकर दारू पीता रहता है। वहां पर जितने भी गरीब लोग ईलाज करवाने के लिए आते हैं उनको उस एस.एम.ओ की आदत की वजह से दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। क्या मंत्री जी उस हास्पिटल का दायरा बढ़ाने के बारे में विचार करेंगी और उस एस.एम.ओ. को वहां से ट्रांसफर करके वहां के लोगों को उससे निजात दिलवाने का कष्ट करेंगी ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहूंगा कि माननीय विधायक ने जो बात कही है यह एक बहुत ही गम्भीर आरोप है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अच्छा होता कि ये उसी समय बताते जब वह दारू पी रहा था। ये वहां के विधायक हैं और एक विधायक की जिम्मेवारी बनती है कि अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो उसके खिलाफ उसी वक्त शिकायत करते, उसको पकड़वाते, हम उसके खिलाफ जरूर सख्त ऐक्शन लेते और भविष्य में भी लेंगे।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसराना के अन्दर सी.एच.सी. सैंक्शन हुई थी और उसका वर्क आर्डर भी हो गया था। अध्यक्ष महोदय, वह काम हैल्डअप हो गया है, मंत्री जी यह बताएं कि उसका काम कब तक चालू कर देंगे ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगी कि अगर वहां पर वर्क अलाट हुआ है तो हम उस केस को एग्जामिन करवा लेंगे। अगर वर्क अलाट हो गया होगा तो हम उस काम को जल्दी ही शुरू करवा देंगे।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि लोशाम हास्पिटल 50 बैड का है और आज उसकी हालत बहुत ही जर्जर स्थिति में है। मंत्री जी, उसकी अपग्रेडेशन के बारे में क्या आपके पास कोई प्लान है ?

Mr. Speaker : It is not possible to reply about all hospitals of the State.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या जी से कहना चाहूंगी कि अगर उस हास्पिटल की जर्जर हालत के बारे में हमें लिखकर वे अवगत करवा देतीं तो अब तक हम उसकी हालत ठीक कर देते क्योंकि सरकार के पास बहुत फंड हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Survey for Old Age Pension

***Sri Ram Pal Majra :** Will the Social Justice & Empowerment Minister be pleased to state whether any survey for old age pension has been conducted in the State during the year 2009-10; if so, the number of persons found eligible ?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukal) Matanhail : Yes Sir. The number of persons found eligible is 2,29,380.

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पिछले से पिछले हाउस के सैशन में ओल्ड एज पैंशन धारकों के लिए ओल्ड एज होम और डे-केयर सैंटर तथा इन्स्टीथ्युशन बनाने के बारे में कहा था। सर, डे-कल्ब गांवों में बनाए जाएंगे। 1000 गांव जिनमें भुड्डे देने का टारगेट रखा गया था। उन 1000 गांवों में 15,000 रूपए प्रति गांव के हिसाब से ओल्ड एज क्लब कितने बने हैं और अब तक कितना टारगैट पूरा हुआ है ? दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि शहरों में डे-केयर सैंटर प्रति जिले के हिसाब से एक एक बनाना था, कितने जिलों में अब तक ये कार्यान्वित हो सके हैं।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : सर, हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और इस समय बुजुर्गों के मान-सम्मान में पैंशन का बंटवारा किया जा रहा है। उसके अलावा बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए हमने 1000 क्लब बनाने का फैसला लिया है, इनके लिए फंड सैंक्शन कर दिए हैं और 1000 का कार्यरूप चल रहा है।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया जी से जानना चाहता हूं कि 1000 ओल्ड एज क्लब कब तक खोल देंगे और अबतक कितने जिलों के गांवों में

[श्री राम पाल माजरा]
इनको खोला गया है। इन 1000 गांवों में से कितने अब तक कवर किए गए हैं। मेरी दूसरी सप्लीमैंटरी भी है लेकिन मेरी पहली सप्लीमैंटरी का जवाब दे दें।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, यह पृथक प्रश्न है क्योंकि इन्होंने ओल्ड एज पैंशन को लेकर अपना प्रश्न किया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, आप बैठिए। नैक्स्ट प्रश्न पूछें।

Requirement of City Scan Machine

***130 Smt. Sumita Singh :** Will the Health Minister be pleased to state —

(a) Whether there is any requirement for a CT Scan Machine in the Trauma Centre, Civil Hospital, Karnal ; and

(b) If so, whether there is any proposal under consideration of the Government to purchase the CT Scan Machine together-with the time by which the above stated machine is likely to be purchased ?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal) Matanhail :

(a) Yes, Sir, there is requirement for a CT Scan Machine in the Trauma Centre, Civil Hospital, Karnal.

(b) Yes Sir, State Government is in the process of purchase of a CT Scan Machine for Trauma Centre, Civil Hospital, Karnal and orders are likely to be placed in March-April 2010.

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रोसैस काफी समय से चल रहा है क्योंकि पिछले कई वर्षों से मैं इस बारे में प्रश्न लगा रही हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि कब तक यह प्रोसैस खत्म हो जाएगा और वहां कब तक सी.टी.स्कैन की मशीन आ जाएगी ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनेहल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को कहना चाहूंगी कि उनकी चिन्ता बिल्कुल वाजिब है। हमारे हैल्थ डिपार्टमैंट ने मोर्डन मशीन परचेज करने के लिए डायरैक्टर, सप्लाई एंड डिस्पोजल के थ्रू-ओपन टैंडर कॉल किए हैं। Speaker Sir, in 2007-2008 to purchase the CT Scan Machine, we have given order to M/s Siemens India Ltd. इसमें भी आर्डर करने के बाद स्पैशल फंडज अलौट किए गए लेकिन किन्हीं कारणों से सी.टी.स्कैन की मशीन टाईम पर अलॉट नहीं हो सकी है। इसके बाद दोबारा से 18 जनवरी, 2010 को टैंडर कॉल हुए हैं। उसके बाद 17.2.2010 को टैक्नीकल कमेटी की मीटिंग हुई है जिसमें Working demonstration of the Machine has also been taken by the team of the senior Radiologists headed by senior Professors and head of the departments. इसके लिए आलरेडी स्पैशल अमाउंट का प्रोविजन एडवांस में कर लिया गया है जैसे ही हाई पावरज़ परचेज कमेटी की मीटिंग होगी तो उसके बाद इनकी यह समस्या दूर

हो जाएगी। माननीय सदस्या के करनाल के अस्पताल में काफी समय से सी.टी. स्कैन की मशीन नहीं लग पा रही है मैं इनको आश्वासन देना चाहूंगी कि अति शीघ्र इसी महीने इनकी यह समस्या दूर हो जाएगी।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मंत्री जी ने बता ही दिया है लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी करनाल को लेकर बहुत सजग हैं। वहां पर पहले ही एक मैडीकल कालेज खुल रहा है और इसके लिए भी 18 जनवरी, 2010 को टैंडर खुल चुके हैं ।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगी और साथ ही आपके माध्यम से मंत्री जी से एक और सप्लीमैंट्री भी पूछना चाहूंगी। मैंने कुछ सुजैशंज इनको लिखकर दिए थे और कहा था कि करनाल या कहीं और का भी यदि ट्रामा सैंटर है तो उसको एक आटोनोमस बॉडी बना दिया जाना चाहिए, उसको सिविल होस्पिटल के अंदर नहीं रखना चाहिए।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपके माध्यम से सदन में बताया कि हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ज्यादा सजग है। चाहे मेडीकल कालेज बनाना हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल को अपग्रेड करना हो, चाहे मल्टी स्पेशेलिएटी होस्पिटल बनाए गए हों, इंडियन पब्लिक हैल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से हर जगह पर स्वास्थ्य सेवा देने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय सदस्या ने जो ट्रामा सैंटर के बारे में चिंता व्यक्त की है आलरेडी हम यह प्रयास कर रहे हैं कि समय पर हर तरह की सुविधा सभी लोगों को मिले।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सुविधा देने की बात नहीं कर रही हूं सुविधाएं तो वहां पर सभी हैं। चूंकि वह ट्रामा सैंटर वहां पर होस्पिटल के साथ अटैच्ड है तो वही डाक्टर कभी होस्पिटल के लिए चले जाते हैं और कभी ट्रामा सैंटर के लिए चले जाते हैं। ट्रामा सैंटर के लिए डाक्टर्ज को अलग से ट्रेनिंग दी गयी है लेकिन वहां पर दूसरे डाक्टर्ज भी चले जाते हैं इसलिए मैं चाहूंगी कि इनको सैपरेट कर दिया जाए।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ समय से हमारे पास डाक्टर्ज की या स्पेशलिस्टस डाक्टर्ज की जरूर कमी थी। इस कमी को पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हर महीने की दस तारीख को आन लाईन भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही यह डाक्टर्ज की कमी पूरी हो जाएगी, उसके बाद विशेष तौर से ट्रामा सैंटर को अपडेट करने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपडेट करने की बात नहीं कर रही हूं। वहां पर सारी फैसेलिटीज हैं लेकिन जो डाक्टर्ज वहां पर हैं मैं उन्हीं को सैपरेट करने की बात कर रही हूं ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहूंगी कि सी.टी.स्कैन की मशीन जहां जहां खराब है क्या उनके बारे में इनको मालूम है और यदि हां तो वे कब तक ठीक हो जाएंगी ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे स्वयं जानना चाहूंगी कि कहां कहां पर सी.टी.स्कैन की मशीन हैं ? यदि माननीय सदस्या को लगता है कि ये मशीनें कहीं पर

[श्रीमती गीता भुक्कल]

खराब हैं तो ये हमको बता दें। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि एक सी.टी.स्कैन करनाल के अस्पताल के लिए है, एक सी.टी.स्कैन रिवाड़ी के अस्पताल के लिए परपोज्ड है। सिरसा के अस्पताल में भी और पंचकुला में भी सी.टी.स्कैन मशीन है और गुड़गांव में एम.आर.आई की मशीन है। अध्यक्ष महोदय, रेडियोलोजिस्टस की काफी ज्यादा कमी हरियाणा में है। 12 रेडियोलोजिस्टस हमारे पास हैं। अगर सी.टी.स्कैन मशीन खराब होने की कोई भी शिकायत आएगी तो जरूर इसको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा।

Solar Energy Plant

***134 Shri Pradeep Chaudhary :** Will the Power Minister be pleased to state —

(a) whether the Solar Energy Plant in Kohlan (Morni) is lying closed; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to supply the electricity in various Dhanis of Bhoj Naggal i.e. Kohlan, Thadant, Salyon, Dudhla, Kardi, Dhata, Sherta etc.; if so, the time by which the electricity is likely to be supplied in the aforesaid Dhanis ?

Power Minister (Shri Mohendra Partap Singh) :

(a) No Sir. The plant was installed by HAREDA and commissioned in July, 2006. The plant has been working successfully since July, 2006 upto December, 2009. There was some defect in the electronic card of the plant in the month of December, 2009. Now the card has been replaced and the plant has been made functional.

(b) Under the Remote Village Electrification Programme (RVEP) of Ministry of New & Renewable Energy, Govt. of India, Haryana Renewable Energy Development Agency (HAREDA) is implementing the project to provide basic lighting needs with Renewable Energy Technologies in the un-electrified hamlets which are not feasible to electrify with conventional grid electricity. The seven dhanis of Bhoj Naggal i.e., Kohlan, Thandaut, Salyon, Dudhla, Kamradi, Ghata, Sherta have already been covered under the RVEP scheme.

श्री प्रदीप चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पंचकूला जिले के कालका विधान सभा क्षेत्र का अधिकतर एरिया अर्द्ध पर्वतीय क्षेत्र है। वहां जमीनें ऊबड़ खाबड़ हैं और रात में वहां जंगली जानवरों व अन्य जहरीले जीव जंतुओं का भय बना रहता है तो मैं जानना चाहूंगा कि मेरे हल्के के जो छोटे छोटे किसान ढाणियों में रहते हैं, उन्हें रात में बिजली न देकर प्रताड़ित किया जा रहा है उनके पास अपने ट्यूबवैल नहीं हैं वे किसान जिन लोगों के पास अपने ट्यूबवैल हैं उनसे पानी किराए पर लेकर अपनी फसल में रात को पानी लगाने का काम करते हैं जिससे उन्हें जहरीले जीव जंतुओं का डर भी बना रहता है, क्या उनको दिन में बिजली देने का सरकार का कोई विचार है, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा ?

श्री महेन्द्र प्रताप : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय सदस्य ने जिन लोगों को सोलर ऐनर्जी के माध्यम से ढाणियों में बिजली प्राप्त नहीं हो रही है उसका जिक्र अपने सवाल में किया है अध्यक्ष महोदय, आपको तो पता है कि प्रदेश में बिजली का एक बहुत बड़ा नैटवर्क है। बिजली के क्षेत्र में जितना प्रयास माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की रहनुमाई में किया गया है, उससे पूर्व उतना कभी नहीं हुआ। जब पिछली बार वर्ष 2005 में हमारी सरकार आई तो उस समय बिजली की क्षमता 1500 मैगावाट थी आज हमारी क्षमता लगभग उससे डबल है। वर्ष 2005 में हमारी सरकार आने के कुछ समय बाद ही बिजली की क्षमता बढ़कर 4700 मैगावाट हो गई थी आज वह बढ़ते - बढ़ते 5 हजार मैगावाट हो गई है और वर्ष 2011-12 में बिजली की प्रदेश में कोई कमी नहीं होगी। पहले सरकार ने जो स्कीम्ज शुरु की थी उनके तहत गांव और शहरों को एक ही फीडर से बिजली दी जाती थी जिससे शहर की आबादी को 5-6 घंटे बिजली मिलती थी और गांव की आबादी को भी 5-6 घंटे बिजली दी जाती थी। इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम अब सैग्रीगेशन के लिए करोड़ों रुपये की राशि खर्च कर रहे हैं, सैग्रीगेशन का काम तकरीबन कंप्लीट भी हो चुका है, थोड़ा सा ही काम बाकी रह गया है। मैं मानता हूं कि किन्हीं एरियाज में अभी भी थोड़ी सी बिजली की कमी हो सकती है लेकिन उस कमी को भी हम बहुत तेजी से पूरा कर रहे हैं। छह घंटे हम किसान को बिजली दे रहे हैं, हो सकता है कि कहीं थोड़ी बहुत कम भी हो। जहां पर जमीन में पानी बहुत नीचे है वहां हम सात घंटे बिजली दे रहे हैं और जिन गांवों में जहां पर फीडर्ज अलग किए हैं उन गांवों में हम 12 घंटे बिजली दे रहे है और इंडस्ट्रीज व शहरों के लिए 20 घंटे बिजली दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हाउस को और माननीय सदस्य को भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस वक्त हम 670 या इससे भी ज्यादा यूनिट बिजली की सप्लाई कर रहे हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में 60 से 70 फीसदी ज्यादा है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि कहीं कोई टैक्नीकल कमी होगी इसलिए ऐसा हुआ होगा या सैग्रीगेशन न होने की वजह से ऐसा हुआ होगा, उसे हम जल्द पूरा कर देंगे।

हमारी सरकार ने किसानों को पहले भी बिजली की कोई कमी नहीं रहने दी थी और न ही आगे कोई कमी रहने दी जायेगी। उसका रिजल्ट भी हमारे सामने आया है कि पिछले साल से पैदावार कहीं ज्यादा बढ़ी है। (शोर एवं व्यवधान) मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि पिछले साल ड्राउट जैसी स्थिति होने के बावजूद भी बिजली की सप्लाई ज्यादा दी गई है। हालांकि पानी की कमी थी नहरों में पानी भी कम आया था फिर भी किसान की पैदावार बढ़ी है। बिजली की सप्लाई अच्छे ढंग से सुनिश्चित की गई थी इसीलिए तो पैदावार बढ़ी है। इसके लिए हमारी सरकार सजग है और हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को बिजली की कोई कमी नहीं रहने दी जायेगी।

श्री प्रदीप चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह था कि हमारे छोटे-छोटे किसान जो शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे तलहटी में बसे हैं वहां पर उबड़-खाबड़ जमीन है समतल जमीन नहीं है उनको रात को बिजली दी जाती है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनको रात को बिजली देकर प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है ? उनको दिन के समय में बिजली दी जानी चाहिए।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक रात को बिजली देने का सवाल है आप जानते हैं कि सभी जगह बिजली सप्लाई के लिए एक सिस्टम बना रखा है और इस सिस्टम के माध्यम से सभी को दिन में बिजली देना संभव नहीं है। उसी हिसाब से ही ट्रांसमिशन सिस्टम के

[श्री महेन्द्र प्रताप सिंह]
माध्यम से कहीं पर रात को और कहीं पर दिन में बिजली शिफ्ट वाईज दी जाती है। कहीं एक हफ्ते दिन में दी जाती है तो कहीं पर एक हफ्ते रात को बिजली दी जाती है। हम सभी को बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी 5-7 घण्टे किसानों को बिजली देने की बात कह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार के समय में किसानों को कितने घण्टे बिजली मिलती थी और इस समय किसानों को कितने घण्टे बिजली दी जा रही है ? इसके साथ मंत्री जी यह भी बताएं कि पिछले पांच वर्षों में बिजली का उत्पादन कितना बढ़ा है और बिजली की खपत कितनी बढ़ी है यानि उत्पादन और खपत में कितना अन्तर है ?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिजली के उत्पादन के बारे में तो मैं आकड़े पहले ही दे चुका हूं लेकिन जहां तक खपत की बात है, तकरीबन 10, 12 और कई बार 14 प्रतिशत तक बिजली की डिमाण्ड हर साल बढ जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले साल के मुकाबले इस साल दस प्रतिशत ज्यादा हम किसानों को बिजली सप्लाई कर रहे हैं। जहां तक किसानों को कितने घंटे बिजली की सप्लाई की बात है तो तकरीबन 5-6 घण्टे प्रतिदिन हम किसानों को बिजली दे रहे हैं। जहां पर वाटर लेवल नीचा है वहां पर कई बार तो सात घण्टे तक भी किसानों को बिजली की सप्लाई की जाती है। हम कोशिश करके बिजली की सप्लाई तो दे ही रहे हैं।

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि पिछली सरकार के समय में किसानों को कितने घण्टे बिजली दी जाती थी और इस सरकार के समय किसानों को कितने घण्टे बिजली दी जाती है ?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, पुराने जमाने की बात है कि डोमैस्टिक, इण्डस्ट्रीज और किसान इन तीनों में बिजली सप्लाई का सिस्टम विभक्त है। माननीय सदस्य पहले की स्थिति के बारे में जानना चाह रहे हैं। माननीय सदस्य पुराने समय में मंत्री भी रहे हैं और एम.एल.ए. भी रहे हैं। उस समय इण्डस्ट्रीज की हालत यह हो गई थी कि इण्डस्ट्रीज को एक शिफ्ट चलाना मुश्किल हो जाता था। उस समय किसान को दिन में 5-6 घण्टे बिजली दी जाती थी। पूरे फिगर इस समय मेरे पास नहीं है। उस समय शहरों में भी आज के मुकाबले में बिजली कम दी जाती थी लेकिन आज मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार बिजली के क्षेत्र में इतनी सजग है कि प्रान्त की अर्थव्यवस्था के लिए इण्डस्ट्रीज को भी पूरी बिजली सप्लाई की जा रही है। पहले इतनी बिजली नहीं दी जाती थी। आज खपत बढ़ने के बावजूद भी हम बिजली की सप्लाई दे रहे हैं। इण्डस्ट्रीज को भी हम पूरी बिजली दे रहे हैं। आज डॉमैस्टिक सैक्टर को भी बिजली 12 घण्टे तक दी जा रही है। पहले डोमैस्टिक सैक्टर को बिजली ट्यूबवैल्ज के फीडर के माध्यम से 5-6 घण्टे तक दी जाती थी। आज बिजली ज्यादा मिल रही है। ट्यूबवैल्ज को भी उतनी ही बिजली दे रहे हैं इसलिए बिजली की खपत को पूरा किया है।

चौ. मोहम्मद इलियास : स्पीकर सर, माननीय सदस्य श्री प्रदीप चौधरी द्वारा यह बताया गया कि उनका एरिया उबड़-खाबड़ है इसलिए इनके इलाके के लोगों को रात के बजाए दिन में बिजली देने की कोशिश की जानी चाहिए। मेरा मंत्री जी से यह प्रश्न है कि मेवात में जो बिजली न

दिन में आती है और न ही रात को आती है। क्या मंत्री जी मेवात के एरिया में बिजली देने का प्रावधान करने की कोशिश करेंगे ?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, हाउस को चलते इतने दिन हो गये लेकिन मेरे ख्याल से माननीय सदस्य ने अब तक न तो हाउस में और न ही सी.एस. साहब को इस बारे में कहा है कि मेवात में बिजली है या नहीं। अगर कहीं ऐसी कमी है जैसा कि ये बता रहे हैं तो यह सम्भव नहीं है क्योंकि मेवात से हमारे और भी साथी यहां पर हैं। हमारे दो पावर हाउसिज हैं, एक यमुनानगर में है और दूसरा पानीपत में है तथा इनमें पीछे खराबी हो गई थी। इन दोनों पावर प्लांटस में से यमुनानगर का पावर प्लांट आज शुरू हो गया है और पानीपत का पावर प्लांट भी शुरू हो चुका है। इन पावर प्लांटस के खराब हो जाने से हो सकता है कि मेवात वगैरह में कहीं शिड्यूल में कोई कमी आ गई हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को कहना चाहता हूं कि ये इस बारे में लिखकर दे दें हम तुरंत इसकी जांच करवा लेंगे और इनके यहां बिजली की कमी को पूरा कर देंगे।

Removal of High Tension Wires

***152 Smt. Kavita Jain :** Will the Power Minister be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to shift the high tension wires of electricity which are passing over the roofs of the houses in the residential areas of Sonipat city; and

(b) if so, the time by which the abovesaid work of shifting these wires is likely to be started; and if not, the reasons thereof ?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) :

(ए) तथा (बी) : नहीं श्रीमान्, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सोनीपत शहर में बिजली की लाइन बहुत समय पहले बिछाई गई थी तथा भारतीय बिजली नियम - 1956 (रूल-82) के अनुसार इन लाइनों के नीचे किसी प्रकार के निर्माण करने की अनुमति नहीं है। इन लाइनों के नीचे आए आवासीय निर्माण भारतीय बिजली नियम, 1956 का उल्लंघन है।

अध्यक्ष महोदय, यह समस्या सोनीपत के साथ साथ सभी जगह है। ये लाइनें मकान बनाने से बहुत समय पहले की खिंची हुई हैं और इन लाइनों के नीचे मकान बाद में बनाए गए हैं। बिजली विभाग के जो नियम हैं उनके अनुसार इन लाइनों को हटाना असम्भव है। इनको कस्टमर द्वारा अपने खर्चे पर ही हटाया जा सकता है क्योंकि इस पर ज्यादा खर्चे की जरूरत है। उन लाइनों को हटाने के लिए बिजली विभाग की जो स्कीम्ज हैं उनके अनुसार अगर ऐसी लाइनों को कोई हटवाना चाहता है तो वह अपनी कोस्ट पर पैसे जमा करके उनको हटवा सकता है।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि इन लाइनों को हटाना सम्भव नहीं है। जो पुरानी बिछी हुई लाइनें हैं ये लाइनें किसी के घर के ऊपर से जा रही हैं और किसी

[श्री आनन्द सिंह दांगी]

के प्लाट के ऊपर से जा रही हैं। इन लाइनों के मकानों के ऊपर से जाने में लोगों का कोई कसूर नहीं है। अगर कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ है या कोई कमी है तो इसमें बिजली बोर्ड की ही कमी है। आज गरीब आदमी अपना मकान बनाता है तो प्लाट के बीचों बीच ये लाइनें गई हुई हैं तो इनको शिफ्ट करवाने में ही गरीब आदमी अपना पैसा खर्च कर डाले तो यह बात ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से रिक्वैस्ट है कि इस मामले पर थोड़ा विचार करें कि जो लाइनें प्लाट के ऊपर या मकानों के ऊपर जा रही हैं उनको सरकारी खर्चे पर शिफ्ट किया जाए क्योंकि यह बहुत बड़ी समस्या है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी के साथ-साथ मैं समझता हूं कि यह समस्या हर साथी के क्षेत्र की है इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां बड़ी लाइनें हैं उनके नीचे अगर कोई निर्माण करता है तो उसके लिए उसको भी यह देखना चाहिए कि बड़ी लाइनों के नीचे यदि हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो बिजली बोर्ड के लिए समस्या पैदा होगी। (विघ्न) यह समस्या अनअथोराइज्ड कोलोनीज में ज्यादा है। जो सैक्टर्ज पास हैं, अथोराइज्ड हैं वहां यह समस्या नहीं है। लेकिन जितने भी हमारे बिजली विभाग के नियम या स्कीम्स हैं उनके अनुसार हमारे लिए यह समस्या है। फिर भी हम कुछ प्रयास करेंगे और मुख्यमंत्री महोदय से भी रिक्वैस्ट करेंगे कि इस मामले को हम कैसे हल करें। चूंकि इस समय फाइनैंशियल क्राइसिज भी हैं और वे इतना ज्यादा है कि इन यूटीलिटीज को बर्दाशत करने से क्या हालत होगी यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लोगों को भी चाहिए कि हमारे बिजली विभाग के जो नियम हैं उनके अनुसार हाई वोल्टेज लाइनों के नीचे मकान न बनाएं।

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, सोनीपत में इन पुरानी बिछी हुई लाइनों की वजह से काफी दिक्कतें हैं, जिस कारण काफी मौतें हो गई हैं और लोग बहुत परेशान हैं। पिछले 6 महीनों के अंदर-अंदर बन्देपुर गांव में एक युवक की जान चली गई। ऋषि कालोनी में 5 हादसे हो गए जिनमें से 3 की मौत हो गई। इसी तरह एक लड़का और एक औरत की कैलाश कालोनी में मौत हो गई। कई लोग अपंग हो गए। सरकार थोड़े से खर्चे की वजह से इन हाई वोल्टेज तारों को नहीं हटवा रही है जबकि दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि ये तारें बहुत पहले बिछाई गई थी। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Madam, I am sorry, you are not putting the supplementary.

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह बतायें कि हाई वोल्टेज लाईनों को घरों से दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने में सरकार को दिक्कत क्या है ?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या की पीड़ा को समझता हूं। यह समस्या सभी जगह पर है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जहां पर हाई टैंशन लाईनें हैं इनके नीचे खास दूरी तक डबल स्टोरी मकान नहीं बनाये जाने चाहिए। इसके लिए आम नागरिक को भी सोचना पड़ेगा कि वे डबल स्टोरी मकान हाई टैंशन लाईन के नीचे न बनायें। इसके लिए हम सभी सदस्यों को अर्ज करना चाहिए और जनता को जानकारी भी देनी चाहिए। आज के दिन यह एक

बड़ी समस्या बन चुकी है और इसमें फाईनैंशियल कन्सट्रैंट्स भी बहुत ज्यादा हैं। इसका किस प्रकार से निदान किया जाये इस बारे में हम मुख्यमंत्री जी से सलाह लेंगे।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि जहां पर अन एप्रूव्ड कालोनीज हैं उनमें इस तरह की दिक्कत है इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो कालोनीज अन एप्रूव्ड से एप्रूव्ड हो गई हैं और उनमें भी इस तरह की समस्या है क्या वहां पर ये लाईनें हटाने का काम किया जायेगा ?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि जहां अन एप्रूव्ड कालोनीज हैं उनमें यह समस्या ज्यादा है और दूसरी जगहों पर कम है। हम इस समस्या को दूर करने के लिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे।

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, अभी अन एप्रूव्ड और एप्रूव्ड कालोनीज की बात आई है। मैं कहना चाहता हूं कि गांवों में एप्रव्ड और अन एप्रूव्ड की कोई बात नहीं है। गांवों में गरीब लोगों के लिए कंसोलीडेशन द्वारा छोटे-छोटे प्लाट काटे हुए हैं उनके ऊपर से भी बिजली की तारें गुजर रही हैं। गरीब लोगों को ये 100-100 गज के और 200-200 गज के प्लाट दिए हुए हैं। उनके पास रहने के लिए दूसरी जगह भी नहीं है और बहुत सी जगहों पर उनके प्लाट्स के ऊपर से बिजली की तारें गुजर रही हैं। यदि वे लोग शिफ्टिंग के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं तो लम्बा चौड़ा बिल बना दिया जाता है। गरीब लोग इतने पैसे नहीं दे सकते। इसमें उनसे लेवर वगैरा की सहायता लेकर ये लाईनें शिफ्ट करनी चाहिएं। 20-30 हजार रुपये के बिल गरीब लोग नहीं दे सकते। यह समस्या बहुत बड़ी है इस पर विचार करके मंत्री जी इसका समाधान अवश्य करें।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार कह दिया है कि इस पर अवश्य विचार करेंगे और इसमें सुधार भी करेंगे। इसमें जहां तक शहर के निधय का सवाल है उसके बारे में मैंने यह कहा है कि शहरों में जहां अन एप्रूव्ड डवैल्पमैंट्स हैं उनमें इस तरह की समस्या ज्यादा है और उनके मुकाबले शहरों में ही दूसरी जगहों पर कम है। गांवों में भी इस तरह की समस्या है इसमें कोई दो राय नहीं है। इस समस्या को दूर करने के लिए इसको अच्छे तरीके से एग्जामिन करने की आवश्यकता है। इसको हम मुख्यमंत्री जी के लैवल पर एग्जामिन करेंगे क्योंकि यह समुचित प्रति का मामला है।

Stone Crushers

***157 Shri Sampat Singh :** Will the Excise and Taxation Minister be pleased to state the districtwise number of stone crushers in the State of Haryana and districtwise VAT collected from these crushers yearwise in the financial years 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-10 ?

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : The requisite information is laid on Table of the House.

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

INFORMATION

STATEMENT SHOWING THE DISTRICT WISE NUMBER OF STONE CRUSHERS AND TAX COLLECTED FROM THESE STONE CRUSHERS DURING 2005-06 TO 2009-10

Sr. No.	District	No. of Stone Crusher	(Fig. in Crores Rs.) VAT Collect-ion	No. of Stone Crusher	(Fig. in Crores Rs.) VAT Collect-ion	No. of Stone Crusher	(Fig. in Crores Rs.) VAT Collect-ion	No. of Stone Crusher	(Fig. in Crores Rs.) VAT Collect-ion	No. of Stone Crusher	(Fig. in Crores Rs.) VAT Collect-ion
		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	AMBALA	2	0.00	2	0.01	2	0.00	2	0.00	2	0.02
2	BHIWANI	287	1.16	340	0.77	362	1.37	422	1.56	469	2.30
3	FARIDABAD (E)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	FARIDABAD (W)	176	7.93	169	4.70	167	3.72	164	2.81	160	5.68
5	FATEHABAD	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	GURGAON (E)	43	2.20	41	1.78	43	0.88	45	0.48	42	0.48
7	GURGAON (W)	23	0.18	29	0.73	34	0.32	40	0.21	37	0.37
8	HISAR	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	JAGADHARI	115	0.64	126	0.81	160	1.14	208	2.34	231	2.12
10	JHAJJAR	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11	JIND	0	0.00	0	0.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	KAITHAL	2	0.00	2	0.00	2	0.00	2	0.00	2	0.00
13	KARNAL	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14	KURUKSHETRA	2	0.01	2	0.02	2	0.03	2	0.00	2	0.00
15	MEWAT	63	0.74	63	0.97	63	1.22	63	1.46	63	1.32
16	NARNAUL	54	0.34	58	0.57	65	0.58	67	0.62	67	0.95
17	PALWAL	0	0.00	0	0.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	PANCHKULA	44	1.66	48	3.39	48	3.31	53	2.72	54	3.07
19	PANIPAT	0	0.00	0	0.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20	REWARI	0	0.00	0	0.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21	ROHTAK	0	0.00	0	0.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	SIRSA	0	0.00	0	0.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00
23	SONIPAT	0	0.00	0	0.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	TOTAL	811	14.88	880	13.75	948	12.56	1068	12.20	1129	16.31

*Upto Jan., 2010

श्री संपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, टेबल में जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक जो वैट की रिसीप्ट्स हैं उनमें तीन एनोमलीज नजर आ रही हैं। पहली एनोमली यह है कि इस साल को छोड़कर 2005-2006 के दौरान 811 क्रशर थे और 2008-09 में 1068 क्रशर हो गये यानि क्रशर बढ़े हैं और वैट की इनकम 14.88 करोड़ रूपये से कम होकर 12.20 करोड़ रूपये लगातर उपरोक्त तीन साल में घटकर हुई है। इसके क्या कारण हैं। मेरी दूसरी एनोमली यह है कि भिवानी के अंदर 469 स्टोन क्रशर हैं जिनसे 2.30 करोड़ रूपये की आमदनी होती है और पंचकूला के अंदर केवल 54 स्टोन क्रशर हैं जिनसे 3.07 करोड़ रूपये की आमदनी होती है। मेरी तीसरी एनोमली यह है कि पंचकूला में वर्ष 2006-07 के बाद जैसा मैंने कहा आमदनी घट रही है उसी तरह से पंचकूला में भी आमदनी 3.39 करोड़ रूपये से कम होकर 3.07 करोड़ रूपये आ गई। इसके क्या रीजंस हैं, कृपया इस बारे में मंत्री जी बतायें।

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Speaker Sir, this is the factual information. I don't find any anomaly. VAT is always done and it is based on collection on turn over. If my learned friend has a question qua evasion of VAT by specific crusher in a specific district, he should give a separate notice to me. I promise to him and I assure you Speaker Sir, we will get the matter investigated. However, Speaker Sir, I want to point out that in 2004-2005, when this Government took over, the number of crushers were nearly 700 and the VAT collection was nearly Rs. 8.37 crores and as I have pointed out that up to January, 2010, it is Rs. 16.31 crores. There is a 100% jump. However, I completely agree that if my learned friend ever feels that if there is an evasion of tax or VAT by any crusher, he should point it out and give me a specific notice.

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मेरा स्पैसिफिक प्वायंट तो यही है कि मैं कह रहा हूं कि नम्बर ऑफ क्रैशर्ज 811 से बढ़कर 1068 हो गये हैं। ये क्रैशर्ज हर साल बढ़ते ही गये हैं। इसके अलावा इनसे होने वाली इनकम भी बढ़ी है। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार को मुबारकबाद देता हूं। स्पीकर सर, जनवरी, 2010 तक 1631 लाख रूपये की इनकम सरकार को क्रैशर्ज से हुई है। अभी दो महीने इस वर्ष के बाकी हैं इसलिए अभी उनकी इनकम आनी भी शेष है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह पिछली बार से डेढ़ से दो गुणा तक ज्यादा हो सकती है। स्पीकर सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पिछले 3-4 साल से लगातार सरकार की इनकम घटी है। What are the reasons कि हम अकेले क्रैशर्ज की नहीं कह रहे हैं। स्पीकर सर, दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि क्रैशर्ज से हमारी इनकम 150 करोड़ रूपये के करीब हर साल बढ़ी है। इसी प्रकार से माईंस से भी हमारी इनकम मल्टीपलाई हुई है। स्पीकर सर, माईंस से ही क्रैशर्ज चलते हैं तो क्या हम उसका हिसाब देखते हुए अगर उसकी रायल्टी कैलकूलेट करते हैं और उसके बाद जो क्रैशर की वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट करते हैं ? स्पीकर सर, इस सब पर साढ़े 12 प्रतिशत का वैट का स्लैब लागू होता है। उसी तरह से क्रैशर्ज का भी करेंगे मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो वैट लम्प-सम के रूप में जैसा भट्ठों का किया हुआ है ताकि उनसे होने वाली आमदनी इंश्योर हो जाये। स्पीकर सर, जो मैं स्टडी कर पाया उसके मुताबिक मेरी कैलकूलेशन के अनुसार ऐसा करके हम इस इन्कम को 300 से 400 करोड़ रूपये सालाना तक बढ़ा सकते हैं। स्पीकर सर, अगर हम 5-10 क्रैशर्ज को मॉनीटर करके उन पर सालाना लम्प-सम वैट लागू करते हैं तो that will be better. स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे इस प्रकार की किसी स्कीम के बारे में सोचेंगे ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मेरे काबिल दोस्त ने एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। हम इस बात पर जरूर गौर करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार से गवर्नमैंट के रेवेन्यू की लीकेजिज न हो। Speaker Sir, we ensure that we will also use the services of Prof. Sampat Singh, if need be.

श्री आनंद सिंह दांगी : स्पीकर सर, ये जो वैट इत्यादि से सम्बंधित बातें हैं ये तो बहुत ज्यादा समझदार लोगों के बस की बात है। मेरा जो सवाल है वह बहुत जरूरी है कि आज जो कंस्ट्रक्शन मैटीरियल रोड़ी, रेत और बजरी आदि है वह 20 से 25 रूपये प्रति फुट के हिसाब से मिलता है जो कि गरीब आदमी की पहुंच से बाहर की बात है। स्पीकर सर, मैं यह चाहता हूं कि ये क्रेशर मालिक जो इतनी कमाई करने लग रहे हैं क्या इनके ऊपर सरकार के स्तर पर कंट्रोल करने की कोई नीति सरकार के विचाराधीन है जिससे कि ये अपनी मर्जी से कंस्ट्रक्शन मैटीरियल रेत, रोड़ी और बजरी के रेट न बढ़ा सकें ताकि जो हमारा गरीब वर्ग है वह भी अपने मकान ठीक ढंग से कम कीमत में बना सकें ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, वैसे तो यह पृथक प्रश्न है फिर भी मैं बता रहा हूं। स्पीकर सर, अभी दो दिन पहले ही इस बारे में माननीय सदस्य चौधरी सम्पत सिंह जी ने एक सवाल पूछा था उस समय मैंने पूरा मैकेनिज्म देते हुए यह बताया था कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुरूप पूरे हरियाणा में और अब राजस्थान में भी माईनिंग एक्टीविटीज पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह अकेले हरियाणा सरकार के बस की बात नहीं है। इसके बाद सैंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित है, हमने उसको अपने माईनिंग एरियाज की परपोजल भेजी हुई है और हमें उम्मीद है कि वे हमारी बात को जल्दी ही मान लेंगे। स्पीकर सर, जब तक मिनरल की माईनिंग पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाया गया बैन रहेगा तब तक तो इस प्रकार की कठिनाई आयेगी। क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन मैटीरियल है वह भी इसी एरिया से आता है और अगर उस पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा तो यह दिक्कत पेश आयेगी ही। It is not something that we alone control over it. It is now being governed by the Green Bench of the Supreme Court.

श्री राजपाल मुखड़ी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने गरीब आदमियों को 50 हजार रुपये अपना मकान बनाने के लिए दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि गरीब लोगों को हर शीज में रियायतें दी जाती हैं, उनको राशन में छूट दी जाती है इंदिरा आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों के लिए भी पैसा दिया जाता है ताकि वे अपने मकान बना सकें लेकिन उनको बिल्डिंग मैटीरियल महंगा मिलता है। मेरी यह प्रार्थना है कि मकान बनाने के लिए उनको मैटीरियल खरीदने के लिए कोई छूट देने का प्रावधान सरकार की तरफ से किया जाये।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि जैसा कि श्री सम्पत सिंह जी ने कहा कि माइनिंग के ऊपर यह बैन तो अभी लगा है, just a few days before. यह जो एनॉमली इन्होंने प्वाइंट आउट की है, this anomaly, according to his own figure, is very vast. तो यह एनोमली जो आ रही है इसका मतलब यह है कि वहां पर चोरी होने की वजह से इतना जबरदस्त रिवैन्यू लॉस हो रहा है। क्या मंत्री जी उस पर कोई कार्रवाई करेंगे ?

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, I have already answerd the question in reply to question of Ch. Sampat Singh.

Upgradation of P.H.C.

***174 Shri Ganga Ram :** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the very old Primary Health Centre of the village Bhodakalan of Pataudi Constituency into the Community Health Centre for which about five acreage of land was also given.

श्रीमती गीता भुक्कल नातनहेल : जी नहीं, श्रीमान जी।

श्री गंगा राम: अध्यक्ष महोदय, भौड़ाकलां की 2 लाख से भी ज्यादा जनसंख्या है। इसने 5 एकड़ जमीन भी इस स्वास्थ्य केन्द्र के लिए दी हुई है। तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस पर पुनर्विचार किया जाये।

श्रीमती गीता भुक्कल नातनहेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि वहाँ पर 2 लाख की आबादी है लेकिन भौड़ाकलां में इस समय 49553 की जनसंख्या है। अध्यक्ष महोदय, नार्म्स के मुताबिक ही सब सैन्टर या कम्यूनिटी सैन्टर बनाया जाता है। नार्म्स के हिसाब से सब सैन्टर के लिए 5 हजार की आबादी जरूरी है, पी.एच.सी. के लिए 30 हजार की आबादी जरूरी है। कम्यूनिटी हैल्थ सैन्टर के लिए 1 लाख 20 हजार की आबादी होनी जरूरी है। जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि उन्होंने 5 एकड़ जमीन दी हुई है और यह काफी पुरानी सी.एच.सी. है जो कि 1978 से चल रही है। एज पर नार्म्स इसको हम चैक करवायेंगे। इस समय वहाँ पर जो आउट डोर सुविधायें चल रही हैं उनमें डिलिवरी रूम, ईम्यूनाईजेशन, फैमिली प्लानिंग, डैन्टल, टी.बी. लैबोरेट्री, हैल्थ ऐजूकेशन इत्यादि सभी प्रकार की सुविधायें दी गई हैं। वहाँ पर हमारी ओ.पी.डी. भी ठीक तरह से चल रही है। हमारी पटौदी कंस्टीच्यूंशी में इस समय हमारा 50 बैड का हॉस्पीटल चल रहा है।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now question hour is over.

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Supply of Irrigation Water

***54 Smt. Kiran Choudhry :** Will the Irrigation Minister be pleased to state —

(a) whether supply of Irrigation Water is being made un-interruptedly in the State according to sanction and demand capacity of the area and

(b) if so, the details thereof for Bhiwani district ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) तथा (ख) : पानी की कमी के कारण, सिंचाई पानी की आपूर्ति क्रम के आधार पर की जा रही है। पानी की आपूर्ति जिलावार नहीं की जाती है। भिवानी जिला चार संसाधनों द्वारा आपूर्ति प्राप्त करता है, वे हैं सुन्दर सब ब्रांच, भिवानी सब ब्रांच, सिवानी नहर प्रणाली तथा लोहारू नहर जो कि अपनी क्रम प्रणाली के अनुसार चलते हैं। वर्ष 2001 से 2009 तक प्रणालीवार की गई जल आपूर्ति की विवरणी सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरणी

भिवानी जिले में वर्ष 2001 से वर्ष 2009 तक प्रणालीवार प्राप्त की गई आपूर्ति का ब्यौरा निम्नानुसार है :--

आपूर्ति क्युसिक दिनों में

वर्ष	सुन्दर प्रणाली	भिवानी सब-ब्रांच	सिवानी नहर प्रणाली	लोहारू प्रणाली
2001	169286	69607	29077	59818
2002	197433	102557	52737	84226
2003	394866	61951	43092	77202
2004	168265	66042	36246	81763
2005	220223	83725	66132	75631
2006	195280	72232	55660	85463
2007	226401	91872	55046	89936
2008	181152	56911	49438	63716
2009	187245	49642	59857	83148

To increase the capacity of Sub-stations

***68 Col. Raghubir Singh :** Will the Power Minister be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration to increase the capacity of 33 KV Sub-stations at Makrana, Mandiheriya, Berla, Kadma, Nandha, Mandola. Shishwala, Pichopakalan, Kheri Batar and Ruddol falling in Badhra Vidhan Sabha Constituency;

(b) if so, details thereof ; and

(c) if not, reason/constraints thereof ?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : (क), (ख) तथा (ग) श्रीमान्, प्रत्येक उपकेन्द्र की विस्तृत स्थिति का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

प्रत्येक उपकेन्द्र की विस्तृत स्थिति

क्र.सं.	33 के.वी. उपकेन्द्र का नाम	स्थिति
1.	मकराना, मांडीहेरिया, बरेला	इन 3 उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान की जायेगी।
2.	कादमा	10 एमवीए की स्थापित क्षमता सहित नारेंगवास में एक नये 33 केवी उपकेन्द्र का प्रस्ताव है। इस उपकेन्द्र के बनने पर 33 केवी इस उपकेन्द्र कादमा का कुछ भार शिफ्ट कर दिया जायेगा। इस उपकेन्द्र से कादमा उपकेन्द्र को राहत मिलेगी।
3.	नांधा, पिचोपाकलां	क्षमता क्रमश: दिनांक 24-10-2008 तथा 31-8-2009 को बढ़ा दी गई और इन पर भार इस समय लोड क्षमता के नीचे है।
4.	मंदोला, शीशवाला,खेड़ी बत्र	इस समय लोड क्षमता के नीचे होने के कारण इन उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि करने की अवश्यकता नहीं है।
5.	रुदरौल	10 एम.वी.ए. की स्थापित क्षमता सहित खुडाना में एक नया 33 केवी उपकेन्द्र निर्माणाधीन है, जो दिनांक 30-6-2010 तक पूरा होना संभावित है। इस उपकेन्द्र के बनने पर 33 केवी उपकेन्द्र रुदरौल का कुछ लोड इस पर शिफ्ट कर दिया जायेगा जिससे रुदरौल उपकेन्द्र को राहत मिलेगी।

Regularization of Illegal Colonies

***94 Shri Krishan Pal Gurjar :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to regularize the illegal colonies of Faridabad; and

(b) if so, the time by which the aforesaid illegal colonies are likely to be regularized ?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) :

(क) सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य की पालिका सीमाओं के भीतर स्थित अनाधिकृत कालोनियों (जहां 50 प्रतिशत से अधिक प्लाटों पर निर्माण व पर्याप्त विकास कार्य किए हुए हैं) को नियमितीकरण के लिये विचारा जाएगा।

(ख) उपरोक्त को नीति के अनुसार विचारा जाएगा।

Repair of Roads

***168. Shri Ghanshyam Saraf :** Will the PWD (B& R) Minister be pleased to state whether the roads of Bhiwani Constituency are in very bad condition, if so, the time by which these roads are likely to be repaired ?

लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : नहीं, श्रीमान् जी।

Monitoring Committee

***104. Shri Krishan Lal Panwar :** Will the Chief Minister be pleased to state ---

(a) whether there is monitoring committee/agency to oversee the implementation of NREGA in the State/districts; if so, the name(s) thereof, togetherwith the number of cases detected in the State, district-wise, from the year 2005 till January 2010, where the funds earmarked for NREGA have been misused or siphoned off ; and

(b) the details of the amount involved in such cases alongwith the steps taken to stop the misuse and siphoning of the funds ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान् जी, एक विवरणी सदन के पटल पर रखी गई है।

विवरणी

(क) राज्य स्तर पर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम (एमजीनरेगा) के क्रियान्वयन की देख रेख हेतु मुख्यमन्त्री के नेतृत्व में हरियाणा राज्य रोजगार गारन्टी परिषद् का गठन किया गया है। हरियाणा राज्य रोजगार गारन्टी परिषद् की रचना अनुबन्ध "क" पर है। जिला स्तर पर भारत सरकार द्वारा मनोनीत संसद सदस्य के नेतृत्व में चौकसी तथा निगरानी समितियाँ गठित की गई हैं। जिला स्तरीय चौकसी तथा निगरानी समितियों की रचना अनुबन्ध "ख" पर तथा समितियों के अध्यक्ष/सह-अध्यक्ष की सूची अनुबन्ध "ग" पर है। वर्ष 2005 से जनवरी, 2010 तक जिला पानीपत तथा अम्बाला में स्कीम के अन्तर्गत राशि के आरोपित दुरूपयोग के तीन मामले जिला प्रशासन के ध्यान में आये हैं।

(ख) (i) जिला पानीपत की ग्राम पंचायत सिमला मोलाना में एक तालाब की खुदाई के निरक्षण के दौरान सरपंच द्वारा 83,444/- रुपये की अधिक राशि का भुगतान किया पाया गया। जिला प्रशासन, पानीपत द्वारा अतिरिक्त खण्ड कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम पंचायत के सरपंच, ग्राम सचिव तथा सम्बन्धित ग्राम रोजगार सहायक के विरुद्ध प्राथमिकी रिपोर्ट संख्या 82, दिनांक 12-3-2010 दर्ज करवाई गई है।

जिला अम्बाला में दिनांक 2-3-2010 को अतिरिक्त उपायुक्त, अम्बाला द्वारा प्रेषित निरीक्षण रिपोर्ट में वन विभाग द्वारा करवाये गये कार्यों के सम्बन्ध में कुछ अनियमितताएँ तथा स्कीम की दिशा-निर्देशिका की उल्लंघना दर्शायी गई है। उपायुक्त, अम्बाला ने आरोपित अनियमितताओं तथा उल्लंघना की जांच हेतु एक कमेटी का गठन किया है।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

उप-मण्डल न्यायधीश (सिविल), नारायणगढ़, जिला अम्बाला द्वारा की गई एक जाँच में यह पाया गया है कि सरपंच, ग्राम पंचायत, गाजीपुर, खण्ड शहजादपुर ने फर्जी मस्टर रोल बनाकर स्कीम के 91,765/- रुपयों की राशि का दुरूपयोग किया था। उक्त सरपंच दिनांक 13-5-2009 को निलम्बित किया जा चुका है तथा आगामी कार्यवाही जारी है।

(ii) धनराशि के दुरूपयोग को नियन्त्रित करने हेतु वर्ष में दो बार ग्राम पंचायत क्षेत्रों में सामाजिक आडिट करवाने के अतिरिक्त, जिला तथा खण्ड स्तरीय कर्मचारियों द्वारा कार्यों की नियमित जाँच की जा रही है। श्रम के पूरे भुगतान की सुनिश्चितता तथा अधिक पारदर्शिता लाने हेतु श्रमिकों को भुगतान उनके बैंक/डाकघरों लेखों के माध्यम से किया जा रहा है। जन परिवेदना के निवारण हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक ओम्बड्समैन की नियुक्ति की जा रही है।

अनुबन्ध--"क"

हरियाणा राज्य रोजगार गारन्टी परिषद् (एच.एस.ई.जी.सी.)

सरकारी सदस्य

1.	मुख्यमंत्री हरियाणा (ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में)	अध्यक्ष
2.	वित्त मंत्री	सदस्य
3.	योजना मंत्री	सदस्य
4.	कृषि मंत्री	सदस्य
5.	लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री	सदस्य
6.	वन मंत्री	सदस्य
7.	सिंचाई मंत्री	सदस्य
8.	मुख्य संसदीय सचिव/संसदीय सचिव, ग्रामीण विकास	सदस्य
9.	वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, ग्रामीण विकास	सदस्य सचिव
10.	वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग	सदस्य
11.	वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, योजना विभाग	सदस्य
12.	वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि विभाग	सदस्य
13.	वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग	सदस्य
14.	वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, सिंचाई विभाग	सदस्य
15.	निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा	सदस्य
16.	निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा	सदस्य
17.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा	सदस्य

18.	मण्डल आयुक्त, अम्बाला	सदस्य
19.	मण्डल आयुक्त, हिसार	सदस्य
20.	मण्डल आयुक्त, रोहतक	सदस्य
21.	मण्डल आयुक्त, गुड़गांव	सदस्य
	गैर सरकारी सदस्य	15

अनुबन्ध-- "ख"

जिला स्तरीय चौकसी एवं निगरानी समितियाँ

रचना

I. **अध्यक्ष :** ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा नामांकित जिला से निर्वाचित सांसद (लोक सभा) या एक मंत्री जिला स्तरीय चौकसी एवं निगरानी समिति का अध्यक्ष होता है।

II. **सदस्य सचिव :** उपायुक्त जिला स्तरीय चौकसी एवं निगरानी समिति का सदस्य सचिव होता है।

III. **सदस्य :** समिति के अन्य सदस्य निम्न होंगे :

(i) जिले के सभी सांसद (लोक सभा) सहअध्यक्ष पदनामित होंगे।

(ii) राज्य का एक प्रतिनिधि सांसद (राज्य सभा) और (प्राथमिकता के आधार पर) उस जिले की जिला स्तरीय समिति का सह-अध्यक्ष नामित होगा।

(iii) जिले से सम्बन्धित राज्य विधान सभा के सभी सदस्य।

(iv) राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि।

(v) जिला पंचायत का अध्यक्ष।

(vi) सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष।

(vii) जिला पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

(viii) अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डी.आर.डी.ए.।

(ix) समिति के अध्यक्ष द्वारा अन्य सांसदों की सहमति से नामांकित प्रसिद्ध गैर सरकारी संस्था से एक सदस्य।

(x) जिला कलैक्टर द्वारा मनोनित सामाजिक विज्ञान व सामाजिक कार्य के क्षेत्र से सम्बन्धित एक व्यवसायिक।

(xi) समिति के अध्यक्ष द्वारा अन्य सांसदों की सहमति से मनोनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति और महिलाओं का एक-एक प्रतिनिधि।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

अनुबन्ध-- "ग"

हरियाणा राज्य की जिला चौकसी तथा निगरानी समितियों के लिए मनोनीत अध्यक्ष/सह अध्यक्ष संसद सदस्य (15वीं लोकसभा)

अम्बाला	कुमारी सैलजा, अध्यक्ष
भिवानी	श्री भजन लाल, अध्यक्ष
फतेहाबाद	श्री अशोक तंवर, अध्यक्ष
फरीदाबाद	श्री अवतार सिंह भड़ाना, अध्यक्ष
गुड़गांव	श्री इन्द्रजीत सिंह राव, अध्यक्ष
हिसार	श्री भजन लाल, अध्यक्ष
झज्जर	श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा, अध्यक्ष
जींद	श्री जितेन्द्र सिंह मलिक, अध्यक्ष
	श्री अशोक तंवर, सह-अध्यक्ष
कैथल	श्री नवीन जिंदल, अध्यक्ष
करनाल	डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा, अध्यक्ष
कुरुक्षेत्र	श्री नवीन जिंदल, अध्यक्ष
महेन्द्रगढ़	श्रीमती श्रुति चौधरी, अध्यक्ष
मेवात	श्री इन्द्रजीत सिंह राव, अध्यक्ष
पंचकुला	कुमारी सैलजा, अध्यक्ष
पानीपत	डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा, अध्यक्ष
रिवाड़ी	श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा, अध्यक्ष
	श्रीमती श्रुति चौधरी, सह-अध्यक्ष
रोहतक	श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा, अध्यक्ष
सिरसा	श्री अशोक तंवर, अध्यक्ष
सोनीपत	श्री जितेन्द्र सिंह मलिक, अध्यक्ष
यमुनानगर	कुमारी शैलजा, अध्यक्ष

Beautification of Hodal City

***161. Shri Jagdish Nayar :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state —

(a) the amount sanctioned by the Government for the beautification of Hodal city; and

(b) Whether it is a fact that there is no proper arrangement for the drainage of rainy water in Hodal city; if so, the steps being taken by the Government for the proper drainage of rain water ?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) :

(क) किसी भी शहर के सौंदर्यकरण के लिए कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है। खर्चा सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदानों तथा नगरपालिकाओं के संसाधनों से किया जाता है।

(ख) पहले से स्थापित सिवरेज सिस्टम द्वारा वर्षा के अधिकांश पानी की निकासी की जाती है, जिसे अन्ततः पम्पिंग के माध्यम से उजीना डाईवर्शन ड्रेन में निष्पादित किया जाता है।

Shortage of Buses

***6. Shri Ram Pal Majra :** Will the Transport Minister be pleased to state whether there is shortage of buses in the State; if so, the number of buses required to meet out the shortage togetherwith the time by which the transmigration of these buses will be started ?

परिवहन मंत्री (श्री ओम प्रकाश जैन) : हाँ, श्रीमान् जी।

हरियाणा राज्य परिवहन में अधिकृत बसों के बेड़े की तुलना में 295 बसों की कमी है। परिवहन विभाग, हरियाणा ने विभिन्न श्रेणियों की 616 बसें खरीदने के आदेश जारी किये हुए हैं, जोकि जल्द ही हरियाणा राज्य परिवहन के आगारों में आवागमन हेतु प्राप्त हो जावेंगी।

Construction of Road

***179. Shri Phool Singh Kheri :** Will the P.W.D. (B & R) Minister be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the road has not been constructed from Shadipur to Mehmoodpur in Guhla Constituency ; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the above stated road; if so, the time by which the said road is likely to be constructed ?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता

Allotment of Plots

***182. Shri Devender Kumar Bansal :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether the hundreds inhabitants of Indira Colony, Rajiv Colony and Azad Colony, at Panchkula have deposited approximately Rs. 10,000/- each for allotment of plots to them; and

(b) Whether approximately 2100 flats are ready for allotment to the inhabitants of above said colonies; if so, the time by which these flates will be allotted or plots are likely to be given to resident of these colonies ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) हां श्रीमान् जी, 2072 फ्लैट "आशियाना स्कीम" के तहत पंचकुला में बनाये गये हैं। यह आबंटन के लिए तैयार हैं उक्त स्कीम के शर्तें पूर्ण करने वाले योग्य व्यक्तियों को ये फ्लैट आंबटन किये जायेंगे।

Registration of Property Dealers

***158. Shri Sampat Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there are any rules in the state for the registration of Property Dealers; if so, how many Property Dealers are registered in the State districtwise details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : जी हां श्रीमान्। सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

राज्य में 64 प्रापर्टी डीलरों का हरियाणा सम्पत्ति व्यवहारी तथा परामर्शदाता विनियमन अधिनियम, 2008 तथा इसके अन्तर्गत 2009 में बने नियमों के तहत पंजीकरण किया गया है। जिलावार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

जिला	पंजीकृत प्रापर्टी डीलरों की संख्या
पानीपत	1
हिसार	8
भिवानी	1
सिरसा	10
गुड़गांव	28
नारनौल	15
रिवाड़ी	1
कुल	64

Construction of Judicial Complex

***31. Shri Anil Vij :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Judicial Complex Building for Courts at Ambala Cantt; and

(b) if so, the time by which the said building is likely to be constructed ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Acquisition of Land

***74. Shri Ashok Kumar Arora :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is fact that notification for acquisition of land for residential purpose in various Towns in the State have been issued during the period from 1-4-2005 to date;

(b) the details of total hectares of land notified for the purpose mentioned as in (a) above; and

(c) the details of total hectares of land released out of (b) above or by the lapse of notification ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान् जी, स्टेटमैन्ट सदन के पटल पर रखी जाती है।

स्टेटमैन्ट

(क) हां, सरकार द्वारा 57 अधिसूचनाएं जारी की गई।

(ख) 1-4-2005 से आज तक की अवधि में विभिन्न शहरों में भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 के अन्तर्गत रिहायशी उद्देश्य हेतु (कमर्शियल तथा इन्स्टीट्यूशनल उद्देश्य सहित) अधिसूचित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है : --

क्रम. संख्या	कस्बों के नाम	धारा-4 के तहत अधिसूचित भूमि (एकड़ों में)
1.	हांसी	286.57
2.	अग्रोहा	205.21
3.	जीन्द	480.12
4.	सफीदों	559.28

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

5.	उचाना	170.50
6.	फतेहाबाद	1331.64
7.	भिवानी	747.28
8.	दादरी	308.73
9.	सिरसा	350.53
10.	फरीदाबाद	1182.88
11.	पलवल	209.42
12.	नूंह	313.89
13.	रोहतक	2291.75
14.	पानीपत	327.19
15.	सोनीपत	2435.83
16.	खरखौदा	364.59
17.	पिंजौर	1292.89
18.	कैथल	27.66
19.	पेहवा	336.94
20.	जगाधरी	1354.06
21.	पंचकूला	22.97
22.	अम्बाला	598.16
23.	गुड़गांव	2304.305
24.	रेवाड़ी	649.16
25.	महेन्द्रगढ़	263.615
	जोड़	**18415.1705 (7455.535 हैक्टेयर)**

(ग) विवरण निम्न प्रकार से है :--

(i) धारा-5ए की आपत्तियों पर निर्णय के समय छोड़ी गई भूमि	978.5874 हैक्टेयर
(ii) धारा-6 तथा अवार्ड के बीच छोड़ी गई भूमि	392.6343 हैक्टेयर
(iii) अवार्ड के बाद छोड़ी गई भूमि	90.75506 हैक्टेयर
(iv) अधिसूचनाएं लैप्स करते हुए छोड़ी गई भूमि	205.4413 हैक्टेयर
कुल जोड़	**1667.4180 हैक्टेयर**

अनुपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना

15.00 hour. **Mr. Speaker** : Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received a message from Smt. Savitri Jindal, M.L.A. expressing her inability to attend the Sitting of Haryana Vidhan Sabha on 15th and 16th March, 2010 due to personal pre-occupation.

श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के विरूद्ध अभिकथित विशेषाधिकार भंग का प्रश्न

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of Breach of Privilege from Shri Bharat Bhushan Batra, M.L.A. against Shri Om Prakash Chautala, M.L.A. stating that Shri Om Prakash Chautala has made false, misleading and incorrect statement on the floor of the House on 11th March, 2010, willfully, deliberately and knowingly stating that the Haryana Urban Development Authority had not acquired a single acre of land since coming into power of the Congress Government in March, 2005 till date. He has also stated that not even a single sector of HUDA had been floated during this period, whereas the Parliamentary Affairs Minister, Shri Randeep Singh Surjewala has pointed out the correct factual position but Shri Om Prakash Chautala again asserted that neither even a single sector of HUDA was floated nor a single acre of land was acquired by HUDA from March, 2005 till date. By doing so Shri Om Prakash Chautala has tried to mislead the House willfully, knowingly and deliberately which amounts to contempt of the House/Breach of Privilege committed by him. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 11th March, 2010, which involves the question of Breach of Privilege/contempt of the House, be referred to the Committee of Privileges for examination and report by first sitting of the next Session.

I give my consent to the raising of the question by alleged Breach of Privilege and held that the matter proposed to be discussed is in order and I now ask Shri Bharat Bhushan Batra, M.L.A. to rise and ask for leave to raise the question of Breach of Privilege.

Shri Bharat Bhushan Batra : Hon'ble Speaker Sir, kindly allow me the leave to raise the question of Breach of Privilege against Shri Om Prakash Chautala M.L.A.

Mr. Speaker : Now, I request those Members, who are in favour of leave being granted to the motion, to please rise in their seats.

(At this stage, all the ruling party Members present in the House rose in their seats).

Mr. Speaker : As the number of Members who rose in favour of the motion exceeds 15, the leave is granted.

[श्री अध्यक्ष]

Now, Shri Bharat Bhushan Batra, may move his motion to refer the matter to the Committee of Privileges.

Shri Bharat Bhushan Batra : Sir, I beg to move —

> That Shri Om Prakash Chautala has made false, misleading and incorrect statement on the floor of the House on 11th March, 2010, willfully, deliberately and knowingly stating that the Haryana Urban Development Authority had not acquired a single acre of land since coming into power of the Congress Government in March, 2005 till date. He has also stated that not even a single sector of HUDA had been floated during this period, whereas the Parliamentary Affairs Minister, Shri Randeep Singh Surjewala had pointed out the correct factual position but Shri Om Prakash Chautala again asserted that neither even a single sector of HUDA was floated nor a single acre of land was acquired by HUDA from March, 2005 till date. By doing so Shri Om Prakash Chautala has tried to mislead the House willfully, knowingly and deliberately which amounts to contempt of the House/Breach of Privilege committed by him. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 11th March, 2010, which involves the question of Breach of Privilege/contempt of the House, be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved —

> That Shri Om Prakash Chautala has made false, misleading and incorrect statement on the floor of the House on 11th March, 2010, willfully, deliberately and knowingly stating that the Haryana Urban Development Authority had not acquired a single acre of land since coming into power of the Congress Government in March, 2005 till date. He has also stated that not even a single sector of HUDA had been floated during this period, whereas the Parliamentary Affairs Minister, Shri Randeep Singh Surjewala had pointed out the correct factual position but Shri Om Prakash Chautala again asserted that neither even a single sector of HUDA was floated nor a single acre of land was acquired by HUDA from March, 2005 till date. By doing so Shri Om Prakash Chautala has tried to mislead the House willfully, knowingly and deliberately which amounts to contempt of the House/Breach of Privilege committed by him. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 11th March, 2010, which involves the question of Breach of Privilege/contempt of the House, be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of the next Session.

श्री भारत भूषण बत्रा : अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच सालों में कांग्रेस की सरकार ने जमीन का acquisition तो किया ही और हुडा के जो सैक्टर काटे वे इस प्रकार से हैं, सैक्टर 56 और 56-ए फरीदाबाद में, सैक्टर 33 करनाल में, सैक्टर 6 और 7 जींद में, सैक्टर 18 कैथल में, सैक्टर 18 रिवाड़ी में, सैक्टर 3, 4 और 5 हिसार में, सैक्टर 6 झज्जर में, सैक्टर 19 और 20 सिरसा में तथा सैक्टर 3 फरीदाबाद में।

इसके अतिरिक्त भी जो सैक्टर्ज प्लोट हुए हैं वे निम्न प्रकार से हैं ----

1. सैक्टर-27,28 एवं 30 पिन्जौर
2. सैक्टर-22, अम्बाला
3. सैक्टर-9 एवं 10 महेन्द्रगढ़
4. सैक्टर-1, तरावड़ी
5. सैक्टर-75 एवं 80 फरीदाबाद
6. सैक्टर-12, पलवल
7. सैक्टर-8 एवं 9,दादरी
8. सैक्टर- 9 एवं 18, सोनीपत
9. सैक्टर-19, पानीपत
10. सैक्टर-5, रिवाड़ी
11. पटौदी 243 एकड़
12. सैक्टर-17,19 एवं 20, रिवाड़ी
13. सैक्टर-16, सोनीपत
14. सैक्टर-27, रोहतक
15. सैक्टर-21,कैथल
16. सैक्टर-19 एवं 20, कैथल
17. सैक्टर-33, जगाधरी
18. सैक्टर-6 एवं 7, रिवाड़ी
19. सैक्टर-6, एम.डी.सी., पंचकुला
20. सैक्टर-2,एम.डी.सी.,पंचकुला
21. सैक्टर-22,23 एवं 24 जगाधरी
22. सैक्टर-3,5,6 हांसी
23. सैक्टर-9,10,11,11-ए, फतेहाबाद
24. सैक्टर-23, भिवानी
25. सैक्टर-8,19, सोनीपत
26. सैक्टर-26,रोहतक
27. सैक्टर-36-ए,रोहतक
28. सैक्टर-36,रोहतक
29. सैक्टर-31,रोहतक

These lands have been acquired and Sectors have been floated during this regime.

Mr. Speaker : Question is—

> That Shri Om Prakash Chautala has made a false, misleading and incorrect statement on the floor of the House on 11th March, 2010 willfully, deliberately and knowingly stating that Haryana Urban Development Authority had not acquired a single acre of land since coming into power of the Congress Government in March, 2005 till date. He has also stated that not even a single sector of HUDA has been floated during this period, whereas the Parliamentary Affairs Minister, Shri Randeep Singh Surjewala has pointed out the correct factual position but Shri Om Prakash Chautala again asserted that neither even a single sector of HUDA was floated nor a single acre of land acquired by HUDA from March, 2005 till date. By doing so, Shri Om Prakash Chautala has tried to mislead the House willfully, knowingly and deliberately which amounts to contempt of the House/Breach of Privilege committed by him. Thus, the matter of making a false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of House on 11th March, 2010, which involves the question of Breach of Privilege/contempt of the House, be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

Mr. Speaker : This matter is referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of the next Session.

वाक-आउट

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, इस प्रिविलेज मोशन को कमेटी को रैफर करने के विरोध में वाक-आउट करते हैं।

(At this stage, all the Members of the Indian National Lok Dal and Shiromani Akali Dal, present in the House staged a walk-out against referring the matter of alleged Breach of Privilege against Shri Om Prakash Chautala, to the Committee of Privileges.)

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना एक कालिंग अंटेशन मोशन हरियाणा स्टेट की इंडस्ट्रीज को इकोनोमिक पैकेज देने के बारे में आपको दिया था, उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आपका यह मोशन डिसअलाऊ हो गया है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में पुलिस वाले उकैती कर रहे हैं।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़के) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, ये तो सदन छोड़कर चले गए थे। ये जीरो ऑवर में थे ही नहीं। अब तो जीरो ऑवर खत्म हो गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक कालिंग अटैंशन मोशन रोहतक में कम्प्यूटर टीचर्ज पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करने के बारे में था, उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : माजरा साहब, आपने अपना कालिंग अटैंशन मोशन आज 12.30 बजे दिया है और उसे मैंने आज ही गवर्नमैंट के पास कमैंट्स के लिए भेज दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम पाल माजरा : सर, कल छुटटी का दिन था इसलिए अपना कालिंग अटैंशन मोशन मैंने आज दिया है। सर, मैंने और मेरे तीन अन्य साथियों ने एक और कालिंग अटैंशन मोशन प्रदेश में कानून और व्यवस्था की खराब हुई स्थिति के बारे में दिया है, उसका भी मुझे कृपया फेट बताएं।

श्री अध्यक्ष : वह भी गवर्नमैंट के पास कमैंट्स के लिए भेज दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

वर्ष 2010-2011 के लिए बजट पर चर्चा (पुनरारम्भण)

Mr. Speaker : Hon ble Members. Now the general discussion on Budget Estimate will resume.(Noises & Interruptions) All the Members, please take your seats and let proceed the House. (interruptions) मैडम सुमिता सिंह, आप बजट पर बोलिए।

श्रीमती सुमिता सिंह (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। साथ ही यू.पी.ए. की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह द्वारा राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का जो बिल पेश किया गया है, उसके लिए भी उनका धन्यवाद करती हूं। मैं हरियाणा प्रदेश की महिलाओं की ओर से प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह व यू.पी.ए. अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी का धन्यवाद एवं आभार प्रकट करती हूं व उनको बधाई भी देती हूं। मैं चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को भी और वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव जी को भी बधाई देती हूं कि उन्होंने बहुत ही प्रोग्रैसिव व कॉमनमैन के लिए बजट प्रस्तुत किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पिछले पांच वर्षों के अपने शासन काल में प्रदेश को प्रगति की ऊंचाइयों पर ले गए। आज भी हमारी सरकार इसके लिए सिंसियर ऐफर्ट्स कर रही है और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ते हुए जिस गति से प्रदेश को आगे ले जा रही है उससे आने वाले कुछ ही समय में हमारा प्रदेश समृद्ध राज्यों में नंबर वन की पोजीशन पर होगा, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बधाई देती हूं। जो यह बजट सदन में प्रस्तुत किया गया है इसमें हर सैक्टर में बढ़ौतरी रखी गई है चाहे पॉवर सैक्टर है, चाहे हैल्थ है, चाहे सैनीटेशन है, चाहे ऐजूकेशन है। अगर हम पिछले 2000 से 2005 तक और 2005 से 2010 तक के आंकड़ें देखें तो पिछले 5 सालों में 48,849 करोड़ रुपये से भी अधिक के विकास कार्य कराए गए हैं। हमारी सरकार विकास में विश्वास रखती है और इस बजट में जो फिस्कल रेवेन्यू डैफीसिट है वह इसलिए है कि जो छठा वेतन आयोग दिया गया है उसमें सबसे पहले हरियाणा में जो गवर्नमैंट इम्प्लौयीज हैं उनकी पे रिवाइज की गई। छठे वेतन आयोग के तहत इम्प्लौयीज और पैंशनर्ज को नकद एरियर दिया गया,

उसकी वजह से भी फिस्कल रेवेन्यू डैफीसिट है। इसके अलावा हमने आर.बी.आई. से कभी ओवरड्राफ्ट नहीं लिया। हमें इस बात का भी गर्व है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में हमारा प्रदेश बड़े-बड़े राज्यों में नंबर वन की पोजीशन पर है। आज की आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए जितने भी अवेलेबल रिसोर्सिज हैं, चाहे वे गवर्नमैंट में हैं, या नॉन गवर्नमैंट में हैं, चाहे प्राइवेट सैक्टर्स में हैं उन सबको इकट्ठा करके हमारी सरकार ने पी.पी.पी. के तहत हमारे राज्य के फिजीकल और सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देती हूं। यह सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। इस वर्ष के बजट के अंदर कई प्रशंसनीय नीतियां बनाई गई हैं। एक तो महात्मा गांधी स्वावलंबन पैंशन स्कीम लागू की गई है। इससे हमारे बुजुर्गों को पेंशन का लाभ मिलेगा। राजीव गांधी अर्बन डिवैल्पमैंट मिशन स्कीम के तहत अगले 5 साल में हरियाणा के शहरों के अंदर अर्बन हाउसिंग, स्लम डिवैल्पमैंट, सौलिड वेस्ट मैनेजमैंट के लिए ढाई हजार करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी।

हमारी सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। पिछले पांच वर्ष में हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने जिस किसी भी वर्ग के लिए चुनाव से पहले जो भी घोषणाएं की थी, मुझे इस बात के लिए गर्व है कि वे सभी घोषणाएं पूरी की गयी हैं। हमारी सरकार ने और भी कई ऐतिहासिक कदम उठाये हैं, जैसे किसानों के 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ किए हैं जबकि हमारी पार्टी के मैनीफैस्टो में भी यह बात नहीं थी। हमारी सरकार का इस बारे में कोई वायदा भी नहीं था फिर भी बिजली के बिल माफ किए गए। इसके अलावा किसानों के कर्जे भी माफ किए गए। इसके साथ-साथ जो काला कानून था जिसके तहत किसानों की जमीन एक्वायर की जाती थी, उसको भी पूरी तरह से समाप्त किया गया है। पहले किसानों के कोआप्रेटिव बैंक्स के लोन पर 11 प्रतिशत ब्याज वसूला जाता था लेकिन हमारी सरकार ने उस ब्याज को 11 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया है। इसके साथ-साथ किसानों के ट्यूबवैल्ज के लिए इण्डीपैंडैंट ट्रांसफार्मर्ज भी लगाये गये हैं। यह स्कीम हमारे करनाल जिले में तो लागू हो गई है शायद दूसरे जिलों में भी लागू हो गयी होगी।

डॉ. बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। जैसा कि अभी माननीय सदस्या ने भी कहा और वित्त मंत्री जी ने भी अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार ने किसानों को कोआप्रेटिव बैंक्स के लोन का ब्याज 11प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया है।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सात परसैंट नहीं बल्कि चार परसैंट है।

डॉ. बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। जो किसान समय पर अपना लोन भर देते हैं उनका 5 प्रतिशत ब्याज मार्च, 2009 से लागू किया है। स्पीकर सर, मेरे पास प्रूफ है कि यह अभी तक लागू नहीं किया गया है। कोओप्रेटिव बैंकों में लोन की ब्याज की दर 14 से 17 प्रतिशत लगाई जा रही है। चाहे इस बारे में आप इन्क्वायरी करवा लें।

Mr. Speaker : Bishan Lal Saini ji, please take your seat.

लोक निर्माण मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्वायंट रेज किया है उनकी इस बात का कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं है। मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि हरियाणा ही अकेला ऐसा प्रान्त है जहां 7 प्रतिशत से 4 प्रतिशत कोआप्रेटिव लोन का ब्याज हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की सरकार ने किया था। हमने उसके अन्दर 3 प्रतिशत सब्सिडी दी है। (विघ्न) अगर इन्होंने प्रश्न

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY

किया है तो माननीय सदस्य सुनने का मादा भी रखें। हो सकता है इनको मेरी बात सही लगे। सर, हमने कोआप्रेटीव लोन पर 3 प्रतिशत की सब्सिडी दी है। इस बारे में माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है कि जो 7 प्रतिशत से 5 प्रतिशत ब्याज कोआप्रेटिव बैंक्स के लोन पर हुआ है वह देश के वित्त मंत्री जी ने केन्द्रीय बजट में किया है। चौधरी साहब, केन्द्रीय बजट और प्रान्तीय बजट में थोड़ा फर्क है।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में अंग्रेजों के जमाने से घर में रहने के लिए रिहायशी घर पर हाउस टैक्स देना पड़ता था। पिछली सरकार ने उस हाउस टैक्स को 100 गुणा बढ़ा दिया था। पहले यह टैक्स रैंटल वैल्यू पर देते थे लेकिन पिछली सरकार ने इसको कलैक्टर रेट पर कर दिया था। अब हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार ने शहरों के अन्दर घरों में रहने वाले लोगों के उस हाउस टैक्स को पूरी तरह से बिल्कुल माफ कर दिया है। यह भी हमारी सरकार के मैनीफैस्टो में नहीं था। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए भी हमारी सरकार ने बहुत सी स्कीमें लागू की हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा समाज पुरूष प्रधान है और बहुत कम लोग अपनी पत्नी, बहन और बेटी के नाम कोई प्रॉपर्टी करते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए स्टाम्प ड्यूटी में 2 प्रतिशत छूट दी है। इसी प्रकार से हमारी महिलाओं के लिए सोनीपत में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। महिलाओं को टीचर्ज की भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। हमारी विधवा बहनों के लिए पैंशन की राशि 350 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये प्रति माह की गई। इसी प्रकार से हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी पैंशन पहले 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये और फिर 700 रुपये प्रति माह की गई। जिन लोगों की सिर्फ बेटियां ही बेटियां थीं उनकी पैंशन लाडली स्कीम के तहत 500 रुपये की गई। इसी प्रकार से बैकवर्ड क्लास और दलित समाज के जो हमारे भाई हैं उनके लिए बहुत सी योजनाएं हमारी सरकार ने शुरू की हैं। असली मायने में हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार दलितों के मसीहा हैं। हमारे दलित का बच्चा और गरीब का बच्चा जो सुबह उठकर पहले गाय और भैंस चराने के लिए जाया करता था या किसी ढाबे पर काम करता था लेकिन अब हमारी सरकार ने जो स्कोलरशिप योजना शुरू की है उसके बाद आज वही बच्चा सुबह नहा धोकर तैयार होकर हाथ में पुस्तक लेकर पढ़ाई के लिए स्कूल में जाता है। इसी प्रकार से हमारे गरीब लोग जिनके पास बी.पी.एल. कार्ड हैं या अगर कोई दलित है जिसके पास घर नहीं है या बी.पी.एल. कार्ड नहीं है तो भी उनको गांव में 100-100 गज के प्लाट और पानी की टंकियां मुफ्त दी गई हैं। अध्यक्ष महोदय, हैल्थ सैक्टर की मैं बात करना चाहूंगी। हमारी सरकार हैल्थ में रैवोल्यूशन लेकर आई है। कभी भी कोई व्यक्ति यह नहीं सोच सकता था कि अगर वह सरकारी अस्पताल में जाएगा तो उसको फ्री दवाइयां मिलेंगी। आज किसी भी वर्ग का व्यक्ति चाहे वह गरीब हो, चाहे वह अमीर हो या किसी भी बिरादरी का हो अगर वह सिविल हॉस्पिटल में जाता है तो उसको पूरी दवाईयां मुफ्त दी जाती हैं। हमारे हॉस्पिटल्ज में सर्जरी पैकेजिज जो शुरू किए गए हैं उनमें कुछ सर्जरीज ऐसी हैं जो पूरी तरह से फ्री की जाती हैं। अगर किसी महिला की डिलीवरी होनी है और उसका ऑपरेशन होना है तो उसकी सिजेरियन डिलीवरी पूरी तरह से फ्री होगी। कैटरिक ऑपरेशन जो आज के दिन कॉमन है। बहुत से लोगों को कुछ उम्र के बाद यह प्रॉब्लम हो जाती है इसके लिए पूरी तरह फ्री ऑपरेशन सिविल हॉस्पिटल में किया जाता है। स्लम एरियाज में हमारी सरकार द्वारा गरीब लोगों के लिए फ्री डिस्पैंसरीज खोली गई हैं। पॉवर सैक्टर में भी हमारी सरकार ने नए पॉवर प्लांट्स लगाए हैं। पिछली सरकार ने एक भी पॉवर प्लांट नहीं लगाया था। अध्यक्ष महोदय, इसके

[श्रीमती सुमिता सिंह]

साथ-साथ मैं अपने हल्के की कुछ मांगों के बारे में जरूर कहना चाहूंगी। मेरी कांस्टीच्युंसी में ही नहीं बल्कि पूरे जिले की कल्पना चावला नाम से मैडीकल कालेज बनाने की एक बहुत बड़ी मांग थी। मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी इस मांग के लिए पिछले बजट में प्रावधान कर दिया था। जब ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और हमारी सरकार आई तो सबसे पहले मुख्यमंत्री महोदय ने करनाल में कल्पना चावला नाम के मैडीकल कॉलेज को बनाने की घोषणा की जिसके लिए मैं इस सरकार का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे करनाल शहर में बस स्टैण्ड की समस्या है जिसको मैं पिछले काफी समय से उठा रही हूं। शहर के अंदर हमारा जो बस स्टैंड है उसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था बहुत खराब होती है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि बस स्टैंड को शहर से बाहर बनाया जाए। बजट के अंदर नए बस स्टैंड्स बनाने का प्रावधान तो है लेकिन शहरों का नाम नहीं है कि नए बस स्टैंड्स कहां-कहां बनाये जाएंगे इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहूंगी कि करनाल में नया बस स्टैंड अवश्य बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, हमारे शहर में पार्किंग की भी बहुत बड़ी समस्या है। करनाल शहर में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पार्किंग की जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार को एक सुझाव है कि हमारे यहां के म्युनिसिपल काउंसिल ऑफिस को किसी और स्थान पर शिफ्ट कर दें या जब हमारा नया बस स्टैंड बने तो पुराने बस स्टैंड के स्थान पर म्युनिसिपल काउंसिल ऑफिस को शिफ्ट करके उस म्युनिसिपल काउंसिल ऑफिस जगह पर थ्री टायर या फोर टायर की पार्किंग बनाई जाए ताकि करनाल में ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो सके। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सीवरेज लाइनों की भी बहुत समस्या है। हमारे यहां सीवरेज की लाइनें बहुत पुरानी हैं। शुरू-शुरू में बहुत छोटी सीवरेज लाइनें डाली गई थी। आज आबादी बहुत बढ़ गई है, बहुत से नए घर बन गए हैं जिस कारण हर समय करनाल शहर में सीवरेज ब्लॉक रहता है। मेरी मुख्यमंत्री महोदय और सरकार से रिक्वैस्ट है कि करनाल शहर के सीवरेज के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, हुडा और हाउसिंग बोर्ड के जो एरियाज हैं वहां की मेन रोड्ज तो बना दी जाती हैं लेकिन वहां इंट्रनल रोड्स की हालत बहुत बुरी है इसलिए उनको जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए। मैं मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए भी आभार प्रकट करूंगी कि मेरी कांस्टीच्युंसी के अंदर जितने भी किसान हैं उनके इंडीपैंडेंट ट्रांसफार्मर लग गए हैं। अध्यक्ष महोदय, करनाल में बहुत से डेरे हैं, उनकी बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत गांव की बिजली अलग कर दी गई है और डेरों को एग्रीकल्चर सैक्टर्ज की बिजली मिल रही है। डेरों में 4-5 घंटे ही बिजली मिल रही है इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि डेरों की बिजली की समस्या को दूर किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में म्युनिसिपल काउंसिल के जो बाय-लाज हैं, इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट और हुडा के जो बाय-लाज है वे पहले से बने हुए हैं जिनके अनुसार शहर के अंदर ढाई मंजिल तक ही घर बनाने की परमीशन दी जाती है। आज के दिन जमीनें मंहगी हो गई हैं और जमीन की कमी को देखते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि बाय लाज को चेंज करके शहर के अंदर 5-6 मंजिल तक मकान बनाने की परमीशन दी जाए। अध्यक्ष महोदय, अंत में इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए इतना कहना चाहूंगी कि बाकी की समस्याएं मैं लिखकर भेज दूंगी। जिस प्रकार हमारी सरकार फिजीकल और सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है उसके कारण मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं कि अगली सरकार भी हमारी ही होगी, धन्यवाद।

डॉ. अजय सिंह चौटाला (डबवाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे से पूर्व इस सम्मानित सदन के बहुत सारे सम्मानित सदस्यों ने बजट पर अपने खुलकर विचार रखे हैं। मैं उन बातों को पुन: दोहरा करके सदन का कीमती समय जाया नहीं करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब मैं इस महान सदन का सदस्य बना तब मैंने सोचा था कि मुझे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा क्योंकि इस सदन में बहुत सारे तजुर्बेकार सदस्य मौजूद हैं और मेरी सोच भी है कि मैं हर पल कुछ न कुछ नया सीखूं। परंतु टोटल उसके विपरीत हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के लिए कहा जाता था कि देशों में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाणा परंतु मौजूदा सरकार में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हरियाणा नकली दूध और घी का प्रदेश बनता जा रहा है। गुड़गांव, फरीदाबाद, जींद, अंबाला, रिवाड़ी, पानीपत और भिवानी आदि अनेक जिलों में नकली घी और दूध बनाने वाली बातें सामने आई हैं। मौजूदा बजट में हरियाणा प्रदेश के न किसान के लिए, न मजदूर के लिए, न महिलाओं के लिए, न कर्मचारियों के लिए, न व्यापारियों के लिए, न नौजवानों के लिए, न एस.सीज. के लिए और न पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कोई विशेष बजट का प्रावधान किया गया है। सरकार महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण वर्ष मना रही है लेकिन बजट में महिलाओं के लिए भी पैसे का प्रावधान न के बराबर किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व बहुत सारे उधर से बोलने वाले सदस्यों ने सरकार के खूब गुणगान किए और आंकड़े भी प्रस्तुत किए। इण्डस्ट्रीज के बारे में तो उधर से बोलने वाले सदस्यों द्वारा बहुत सारी बातें कही गई हैं कि इतना निवेश आया है और इतनी इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा दिया है जिनमें इतने लोगों को रोज़गार से जोड़ने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास हरियाणा सरकार द्वारा छापी गई पुस्तक है जिसका नाम सांख्यिकी सारांश हरियाणा है। यह हरियाणा प्रदेश की सरकार ने छपवाई है जिसमें बहुत सारे पैसे खर्च किए गए हैं। इस बुक के पेज 386-387 पर उद्योगों के बारे में लिखा हुआ है।

डॉ. रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, ये यह भी बतावें कि यह कौन से साल की बुक है ?

डॉ. अजय सिंह चौटाला : वह आप देख लेना, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़ लेना! (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इनको यह तो बताना चाहिए कि यह बुक कौन से साल की है ?

डॉ. अजय सिंह चौटाला : मैं कम से कम आपसे यह उम्मीद नहीं करता। आप सुनने का माद्दा रखो और मेरी बात सुनो। मैं सारी चीज बता रहा हूं। मैंने सत्ता पक्ष की तरफ से बोलने वाले एक भी सदस्य को डिस्टर्ब नहीं किया और कम से कम मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी मुझे डिस्टर्ब न करके मेरी बात सुनों। यदि मेरी कोई बात काम की लगे तो आप अपने जीवन में धारण कर लेना और नहीं लगे तो आप अनसुनी कर देना। वैसे आपके पास पूरा अधिकार है और मैजोरिटी भी आपके पास है। आप जिस तरीके से अपने अधिकार का प्रयोग विपक्ष के दूसरे सदस्यों पर कर रहे हैं वह मेरे खिलाफ भी कर लेना। (विघ्न)

Mr. Speaker : Please keep silence. अजय जी, आप बोलें। मेरी सभी से प्रार्थना है कि कोई भी सदस्य बीच में कॉमेंट्री न करे।

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है कि बैठे-बैठे कॉमेंट्री करते रहें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योगों को लेकर इस किताब के पेज 386-87 का उल्लेख कर रहा था। इसमें पूरा विवरण दिया गया है कि किस साल में कितने उद्योग हरियाणा प्रदेश में आये और किस साल में कितने उद्योग हरियाणा प्रदेश से पलायन कर गये। स्पीकर सर, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरियाणा प्रदेश की सत्ता सम्भाली थी उस समय हरियाणा प्रदेश में 924 फैक्टरियां लगी हुई थी और उनमें 84702 कर्मचारी काम कर रहे थे। स्पीकर सर, सन् 2005 में फैक्टरियों की संख्या बढ़कर 1445 हो गई और कर्मधारियों की संख्या बढ़कर 139402 तक पहुंच गई यानि वर्ष 2000 से वर्ष 2005 के बीच में 521 नये उद्योग हरियाणा प्रदेश में लगे और 54702 नये कर्मचारियों को रोजगार मिला। स्पीकर सर, जब हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तब से लेकर अर्थात् वर्ष 2005 से 2008 तक का कैलकुलेशन इसमें दिया गया है। इसमें बताया गया है कि फैक्टरियों की संख्या 1445 से घटकर 1257 रह गई यानि कांग्रेस के शासन काल में 198 उद्योग यहां से पलायन कर गये अर्थात् उन्हें भगा दिया गया। स्पीकर सर, सरकार के झूठे दावों की पोल खोलने के लिए इससे बढ़कर दृष्टांत और क्या हो सकता है ? (विघ्न) जो मैं कह रहा हूं वह रिकॉर्ड की बात है। यह सरकार द्वारा लिखकर भी दिया हुआ है। स्पीकर सर, इन सब का भी सभी के सामने बड़े-बड़े बुलंद बाग दावों के साथ वर्णन किया जाता है। क्या ऐसा करके हाउस को मिसलीड नहीं किया जाता ? स्पीकर सर, आज अगर हम विपक्ष के साथी कोई काम की बात भी करते हैं तो हाऊस में उसका भी मजाक उड़ाया जाता है। यह एक अजीब तमाशे के समान है। स्पीकर सर, आज के संदर्भ में प्रदेश में कानून-व्यवस्था की हालत जगजाहिर है। हरियाणा प्रदेश में पूरे तौर पर जंगल-राज कायम है। यह बात अखबार भी बोल रहे हैं। स्पीकर सर, कल ही पानीपत की घटना सभी के सामने घटित हुई। उसको देखकर यही लगता है कि आज रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। आज तो बाड़ ही खेत को खा रही है। स्पीकर सर, पूरे प्रदेश में गदर मचा हुआ है। एस.पी. लैवल के लोग लूट में शामिल हैं और सरकार लीपापोती करने का काम कर रही है। आज अगर कोई मुख्यमंत्री जी के पास फरियाद लेकर जाता है तो वह न्याय की उम्मीद लेकर जाता है लेकिन होता इसके विपरीत है। मुख्यमंत्री जी के पास जब भी किसी वर्ग के लोग इंसाफ की उम्मीद लेकर जाते हैं तो उन्हें लाठियां और गोलियां मिलती हैं। कल की रोहतक की घटना इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि किस प्रकार से शिक्षकों को बुरे तरीके से लाठियों से पीटने का काम किया गया। स्पीकर सर, सिर्फ यह कल की घटना ही नहीं अनेक ऐसी घटनायें हरियाणा प्रदेश में घटी हैं जो इस बात का सबूत हैं कि अगर किसी ने भी प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी जुबान खोलने की कोशिश की तो उसे लाठियों और गोलियों से भूनने का काम किया गया। अगर प्रजातांत्रिक तरीके से चुने हुए जनता के ये नुमाइंदे सरकार के खिलाफ अपनी बात कहना चाहें तो उनकी आवाज को भी दबाने का प्रयास किया जाता है। इन सबके अनेकों उदाहरण हम सभी के सामने मौजूद हैं। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की पिछली सरकार द्वारा मैजोरिटी का फायदा उठाकर पिछले पांच साल तक लगातार इस हाउस में अपोजिशन को *** (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने जो अभी कहा है वह सही नहीं है इसलिए उसे सदन की कार्यवाही से निकलवाया जाये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, इस पार्ट को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

डॉ. अजय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, इस प्रकार से विपक्ष को तरह-तरह की बातें कही गई। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को यह कहना चाहूंगा कि चाहे जोड़-तोड़ करके ही सही उन्हें दोबारा से हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है इसलिए वे कम से कम हरियाणा प्रदेश के लोगों (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। श्री अजय चौटाला मेरे बहुत अजीज हैं। मुझे उम्मीद थी कि ये तथ्यों पर आधारित बात ही बोलेंगे। मैं इनको एक बात क्लीयर करना चाहता हूं कि मैंने जोड़-तोड़ करके सरकार नहीं बनाई है। मैंने पहले Confidence of the House लिया फिर मैजोरिटी प्रूव की और उसके बाद कैबिनेट बनाई इनके पिता श्री ओम प्रकाश चौटाला की तरह मैंने कैबिनेट बनाकर Confidence of the House नहीं लिया।

डॉ. अजय सिंह चौटाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को दोबारा से हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है इसलिए वे इस बार कम से कम कोई नई प्रथा हरियाणा प्रदेश के लिए जरूर शुरू करें। मैं इनसे यही पूछना चाहता हूं कि जो सिलसिला ये पिछले पांच सालों के दौरान चलाते रहे हैं क्या अब भी उसी को ही दोहराने का काम करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये मैजोरिटी का इसी तरीके से इस्तेमाल करते रहेंगे ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता मुख्यमंत्री जी और उनके पीछे बैठे सभी सम्मानित सदस्यों से यह कहना चाहूंगा कि प्रदेश के लोग यह देखते हैं कि हरियाणा प्रदेश की असैम्बली में प्रदेश के लिए कुछ नया होगा परन्तु यहाँ तो वही पुराना ढर्रा दोहराया जाता है। बार-बार उन्हीं बातों को रिपीट करके सदन का समय खराब किया जाता है ***। इससे क्या हासिल होने वाला है, मुझे यह तो बता दें। कुछ नया करके दिखायें।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। माननीय सदस्य बोलें, अपनी बात कहें। इस सदन में किसी सदस्य ने किसी को गालियाँ नहीं निकाली। इसलिए ये शब्द सदन की कार्यवाही से निकाल दिये जायें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, इन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस बजट में एस.वाई.एल. हरियाणा प्रदेश की जीवन रेखा है और जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी लोगों से वादा किया है। मुख्य मंत्री जी बार-बार अनेक लोगों के बीच में कहते हैं कि इसको पूरा करवाएंगे परन्तु वित्त मंत्री जी ने भी एस.वाई.एल. के बारे में न तो कोई समय सीमा निर्धारित की और न ही बजट में इसके लिए कोई पैसा निर्धारित किया है। फिर सरकार इसको कैसे पूरा करेगी इस बात की इस बजट में कोई चर्चा नहीं है ? प्रदेश के लोग जिस उम्मीद के साथ यह सोचते हैं कि एस.वाई.एल. का पानी आयेगा और हमारे खेत भी लहलहायेंगे उस पर तो बजट में कोई चर्चा नहीं की जाती। इस बारे में बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है और बार-बार रबड़ की चप्पलों की बात की जाती है। बार-बार दूसरे मुद्दों की बात की जाती है। एस.ई.जैड़ को लेकर यह सरकार कितनी गम्भीर है यह बात चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी पहले भी बता चुके हैं। मुख्यमंत्री जी अनेक

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[डॉ. अजय सिंह चौटाला]

जनसभाओं में दावे कर चुके हैं कि 10 लाख नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम होगा। हरियाणा प्रदेश उन्नति के रास्ते पर अग्रसर होगा और हरियाणा को नम्बर 1 प्रदेश बना देंगे। लेकिन आज वह एस.ई.जैड. सिर्फ और सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को, बड़े घरानों को जमीन देने का बहाना बन कर रह गया है। इसके अलावा न कोई इण्डस्ट्री लगी और न कोई रोजगार एस.ई.जैड के माध्यम से किसी को मिला है। इसी प्रकार से बिजली को लेकर भी बार-बार बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं। हरियाणा प्रदेश के 25 प्रतिशत लोग आज डेरों में, ढाणियों में, ट्यूबवैल्स पर खेती करते हैं और वहाँ रहते भी हैं। उन लोगों के लिए आज ब्लैक आउट जैसी स्थिति है। भिवानी, महेन्द्रगढ़, हिसार और रेवाड़ी, यह सारे का सारा इलाका आज ब्लैक आउट जैसा है। सिरसा के बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं है। वहाँ पर तो यह सरकार वैसे ही बहुत ज्यादा मेहरबान रहती है। वहाँ तो अगर इनका बस चले तो ये वहां के लोगों को कहीं और ही छोड़ आवें। पिछले दिनों एच.इ.आर.सी. की मीटिंग में मेरे काबिल दोस्त श्री सम्पत सिंह की मौजूदगी में एक सदस्य ने सरकार के बिजली खरीद के मामले को लेकर सीधे-सीधे उंगली उठाने का काम किया था। उसके पीछे क्या है, वह भी एक जाँच का विषय है। मैं तो बार-बार कह चुका हूँ कि सरकार इस पर श्वेत पत्र जारी करे लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तो **** हैं जब भी बोलते हैं कहते हैं कि ऑपोजीशन के पास तो मुद्दा ही नहीं है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मुख्यमंत्री जी के लिये जो शब्द कहे हैं वे सदन की कार्यवाही से निकाल दिये जायें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, इन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी जन आक्रोश यात्रा के दौरान रोजाना एक सवाल इस सरकार से किया था। ये सुनते कम हैं इसलिए मैंने लिखित में भी पूछा। बाकायदा किताब छपवाकर भेजी थी। आज तक कोई जवाब नहीं आया है। अगर हम बोलते हैं तो कहते हैं कि आप सदन को गुमराह करते हैं। कल परसों ही यहाँ पर कहा जा रहा था कि अजय सिंह ने गृह युद्ध की बात कही।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से 14 जनवरी, 2007 का दैनिक ट्रिब्यून जिसमें माननीय सदस्य की फोटो भी है, इसको मैं सदन की टेबल पर रखना चाहूंगा। (विघ्न) इसमें लिखा है कि नई नहर खोदने से आन्तरिक जल युद्ध छिड़ जाएगा। इसके नीचे लिखा है अजय, गोहाना 13, जनवरी। (विघ्न) सर, इसमें इनका फोटो है, यह इनकी न्यूज है, इनकी स्टेटमैंट भी है। (विघ्न)

डॉ. अजय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, ऐसे बहुत से अखबारों के पुलिंदे मेरे पास भी हैं और मैं भी उनको सदन के पटल पर रखूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उन पर भी गौर कर लेना। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार गवर्नमैंट नौकरियों के मामले में जो कुछ भी बोलती है, उन बातों से हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। इन्होंने कहा था कि हम एक घर में से एक नौजवान को नौकरी देंगे। एस.ई.जैड में 10 लाख नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

करेंगे। आज हरियाणा प्रदेश का हर नौजवान अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहा है। हर घर में से एक नौजवान को नौकरी की बात तो दूर रही लेकिन इस सरकार ने 25 हजार नौजवानों का रोज़गार छीनने का काम किया है। सरकार ने रोज़गार देने के नाम पर नौजवानों को सिर्फ धोखा दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले दिनों बकायदा एक लिस्ट जारी करके बताया था कि किन-किन लोगों को नौकरी पर लगाया जाएगा ? बाद में जब हम देखते हैं तो वही के वही लोग ही नौकरी पर लगते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि रोजगार के नाम पर क्यों लोगों को बेफकूफ बनाया जा रहा है ? यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आज हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या हालत है यह सब जानते हैं। आज पूरे हरियाणा प्रदेश का जन-जन इस बात से चिन्तित है। आज ऐसा लगता है कि जैसे हरियाणा प्रदेश में कोई सरकार ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश में हर 8 घंटे में एक कत्ल हो रहा है, और 12 घंटे में एक बलात्कार की घटना होती है और हर 10 घंटे में एक अगवा की घटना घट रही है। सर, आज मुख्यमंत्री जी और इनकी सरकार के लोग कहते हैं कि हरियाणा में अमन, चैन तथा शान्ति है और हमारा हरियाणा नम्बर वन है। क्या यही हरियाणा नम्बर वन है ? अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार के आने से पहले हरियाणा कैसा था यह तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपराधिक आंकड़े बताते हैं कि 2000 में सत्ता संभालने के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने यानि इनेलो सरकार ने ही आपराधिक घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाने का काम किया था (विघ्न) यह रिकॉर्ड की बात है आपको अगर मेरी बात गलत लगे तो आपके पास अधिकार है कि उसे आप न मानें बजाए इसके कि आप बैठे-बैठे कमैंट्री करें या आप प्वायंट आफ आर्डर पर बोलें। अगर स्पीकर साहब, बैठने के लिए कहेंगे तो मैं तुरन्त बैठ जाऊंगा। (विघ्न)

Mr. Speaker : You have already consumed 17 minutes. Please take your seat. (interruptions)

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, 2000 में आई.पी.सी. के तहत पृथक मामलों की संख्या 39 हजार 490 थी और जब कांग्रेस की सरकार ने सत्ता सम्भाली तो यह संख्या 43,000 हो गई थी। अब यह संख्या लगभग 60,000 हो गई है। अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े बता रहे हैं कि कितने अपराध आज हरियाणा में बढ़े हैं। आज थानों में महिलाओं की इज्जत लूटने का काम किया जा रहा है, जिससे महिला पुलिस कर्मचारियों का मनोबल काफी हद तक गिरा है। फरवरी माह के अंत में 17 शस्त्रबंद पुलिस कर्मियों की गौजूदगी में कुछ गुंडे 18 कैदियों को छुड़वाकर भागने में सफल हो गए। क्या यह भी झूठ है ? अध्यक्ष महोदय, जब भी कोई मामला आता है, चाहे आप गुड़गांव के मजदूरों की घटना लेकर देख लें, या किसी और घटना को देख लें मुख्यमंत्री जी हर जगह कहते हैं कि हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। (विघ्न)

Mr. Speaker : Wind-up please.

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी शुरू ही किया है।

श्री अध्यक्ष : क्या ! अभी शुरू ही किया है ? आपको बोलते हुए 19 मिनट हो गए हैं!

डॉ. अजय सिंह चौटाला : सर, मैं गलत बात तो कहूंगा नहीं।

श्री अध्यक्ष : अगर गलत बात नहीं कहोगे तो क्या रात भर बोलोगे। (विघ्न)

डॉ. अजय सिंह चौटाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों से इसी तरह से छठे वेतन आयोग के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कही गई थीं। आज कर्मचारी हितैषी होने का इस सरकार को कोई अधिकार नहीं है। पिछले दिनों कर्मचारी यहां पर आकर जो विरोध प्रकट करके गए हैं वही बहुत काफी है। स्पीकर सर, मैं सदन में यह बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने प्रैस के साथियों के साथ बहुत वायदे किए थे और बहुत बड़ी बड़ी बातें प्रैस के लिए कही गयी थी परन्तु वे सारी की सारी घोषणाएं बनकर रह गयीं। सतपाल सैनी के नाम से एक अवार्ड शुरू किया गया था और राजेन्द्र जी हुड्डा के नाम से भी एक अवार्ड शुरू किया गया था लेकिन यह अवार्ड एक बार ही देकर रह गए। इसके बाद फिर दोबारा घोषणा की गयी कि हम इनको स्टडी टूअर्ज पर भेजेंगे परन्तु वह घोषणा भी आज तक पूरी नहीं हो पायी।

Mr. Speaker: Ajay Ji, thank you very much, you have already consumed twenty minutes.

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश की सड़कें भी टूटी पड़ी हैं।

श्री अध्यक्ष : अजय जी, अब आप बैठें।

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के की बात भी अगर नहीं करूंगा तो यह बहुत बेइन्साफी होगी। डबवाली अग्निकांड के पीड़ितों का क्या हाल रहा यह मैं बताना चाहता हूं। पिछले दिनों मैंने उनकी समस्याओं को लेकर एक धरना दिया था। मैंने जब सरकार से गुजारिश की तो उसके बाद ही सरकार ने उनके लिए एक रिलीफ दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कम से कम उन पीड़ितों के बारे में जो आज बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं, सरकार को सोचना चाहिए। उनकी हालत बहुत बुरी है।

Mr. Speaker : Please take your seat.

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, उन पीड़ितों से जो वायदे किए गए थे उनको सरकार को पूरा करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अजय जी, अब आप बैठें।

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर मैं संवेदनशील बातें करूंगा तो भी आप क्या मुझे नहीं बोलने देंगे ? आप मुझे अपने हल्के की बातें तो करने दें। अध्यक्ष महोदय, मैंने यही कहा है कि सरकार ने उन पीड़ितों से जो वायदे किए हैं कम से कम उनको तो पूरा करने का काम करना चाहिए। जो पीड़ित परिवार हैं सरकार को उनकी दवा दारू की व्यवस्था करनी चाहिए, बर्न्ज सैंटर की व्यवस्था करनी चाहिए,फिजियोथेरेपिस्ट की व्यवस्था करनी चाहिए। उन गरीब लोगों के लिए नौकरियों की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से डबवाली विधान सभा क्षेत्र को पिछले पांच साल से नैगलैक्ट किया गया है। सरकार को कम से कम आखिरी कोने तक एक निगाह से देखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं नम्बर वन हरियाणा की स्थिति बताना चाहता हूं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आपने इनको बैठने के लिए कहा है फिर भी ये नहीं बैठ रहे हैं। This is not the way.

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. अजय सिंह, अब आप बैठें।

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : अजय सिंह जी, अब आप बैठें

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ चार लाईनें कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप चार लाईन बोल लें।

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा नम्बर वन की क्या स्थिति है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। खेत-खेत में खुल गए ठेके, लोग नशे में रहते टन, बच्चों का अपहरण हो रहा, व्यापारियों पर चलती गन, क्या यही है हरियाणा नम्बर वन ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह कविता का समय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठें।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। मेरे अजीज ने एक बात कही। मैं इनको एक ही बात कहूंगा कि बहुत शोर सुना था महफिल में दिल का, अरे चीरकर देखा तो एक कतरा खून का न निकला। शोथा निकला। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं हरियाणा प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव जी को बहुत मुबारिकबाद देता हूं कि सभी विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने बहुत ही अच्छा और सराहनीय बजट पेश किया है आज सारा विश्व रिसेशन के दौर से गुजर रहा है, इन सब के बावजूद भी वर्ष 2010-11 का बहुत ही शानदार बजट यहां प्रस्तुत किया गया है जिसमें सभी सैक्टर्ज का पूरा ध्यान रखा गया है। मैं ज्यादा आंकड़ों की बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने इस बारे में अपने पूरे विचार रखे हैं। डॉक्टर रधूवीर सिंह कादियान साहब ने बोलते हुए सभी पहलुओं को मेटीकुलसली डील किया। मैं इस बारे में डॉक्टर साहब की विशेष रूप से प्रशंसा करूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने गवर्नर साहब के अभिभाषण का जवाब देते हुए जो पंक्तियां कही थी, उन्हें मैं इस हाउस के समक्ष पुन: दोहराना चाहूंगा कि --

विकास की असली उड़ान अभी बाकी है
अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने,
आगे सारा आसमां अभी बाकी है।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2010-11 के बजट में जो इन्फ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज ऑफ अर्बन एरियाज की इम्प्रूवमैंट के बारे में कहा गया है, और इस बारे में जो स्टैप्स लिए गए हैं वे हिस्टोरिकल स्टैप्स हैं। राजीव गांधी अर्बन डिवैल्पमैंट मिशन के बारे में आदरणीय वित्तमंत्री जी ने

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री भारत भूषण बतरा]

अपनी बजट स्पीच के पेज 7 पर दर्शाया है। इस प्रौजैक्ट के तहत 2500 करोड़ रुपये की राशि अगले 5 साल के लिए अर्बन डिवैल्पमैंट के लिए अलॉट की है, इससे पूर्व इतना पैसा कभी भी इस काम के लिए अलॉट नहीं किया गया। It will be a new mile stone in the progress of the State of Haryana. लोकल बॉडीज के तहत आने वाले सिटीजंस के प्रति अब हम और ज्यादा रिसपौंसिबल होंगे। विपक्ष के सभी सदस्य भी इस बात को ऐप्रीशिएट करेंगे कि हमारे अर्बन सैक्टर के अंदर इंटीग्रेटेड सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट के तहत जो घर-घर से वेस्ट उठाया जायेगा, उसकी साइंटिफिक तरीके से ट्रीटमैंट और डिस्पोजल करना भी शामिल है, यह बहुत सराहनीय कदम है कि इस काम के लिए नोडल ऐजेन्सी हरियाणा इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवल्पमैंट बोर्ड के नाम से बनाई गई है। मैं सरकार की इस कदम के लिए बहुत-बहुत सराहना करता हूं। गरीब आदमियों को एफोर्डेबल हाउस, स्वच्छ जल की आपूर्ति, सैनीटेशन, रोड, गलियों की लाइट्स, पार्कस और सुलभ शौचालय की स्कीम इस प्रदेश को बहुत प्रगति की ओर ले जाएगी। हमारे प्रान्त की 28 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रहती है। इस बार जो ट्रैन्ड आया है इससे पूर्व रिवर्स ट्रैन्ड था। अर्बन डिवैल्पमैंट के लिए इतना पैसा इससे पूर्व कभी खर्च नहीं किया गया था और जो वित्तीय हालात खराब थे उनको सुधारने के लिए यह साहसिक कदम सरकार ने उठाया है। वैट के ऊपर जो सरचार्ज लगाया गया है, वह अर्बन डिवैल्पमैंट के लिए लगाया है। इसकी 80 प्रतिशत राशि शहरों में और 20 प्रतिशत राशि गांवों में खर्च होगी। इस सरकार ने पिछले वर्षों में बहुँमुखी विकास किया है और आगे भी विकास के लिए अग्रसर है। विपक्षी दलों को भी मानना होगा कि जितना विकास पिछले 5 सालों में हुआ है उतना विकास आज तक हरियाणा में कभी भी नहीं हुआ था। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने शहरों के विकास के लिए नयी नीति बनाई है उसका फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में जिक्र किया है कि 73 टाउंज के अंदर अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवैल्पमैंट स्कीम तैयार है और इंटीग्रेटेड सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट प्रोजैक्ट सरकार लगाने जा रही है। वह भी अच्छा प्रोजैक्ट है। इस प्रोजैक्ट में रोहतक, करनाल, इन्द्री, यमुनानगर और जगाधरी का एरिया लिया गया है। 16.00 बजे बहादुरगढ़, सांपला, नारनौल और बरखी दादरी में सीवर प्लांट भी लगाये जायेंगे। इस स्कीम को इफैक्टिव करने के लिए पिछले साल हमारी सरकार ने 67 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। इस स्कीम के लिए 164 करोड़ रुपये भारत सरकार से आयेंगे। इस बारे में ज्यादा प्रोग्रैस करने के लिए हमारी सरकार ने और वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2010-11 के बजट में 123 करोड़ रुपये का पहले ही प्रावधान किया और इसको आगे भी आपरेटिव करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जितने भी विधायक यहां पर बैठे हैं उन सभी को पता है कि दिल्ली भारतवर्ष की राजधानी है। इसके तीनों तरफ जो स्ट्रैटजिक लोकेशन हरियाणा की है उसका हरियाणा वासियों को पूरा-पूरा फायदा उठाना चाहिए। ऐसी सोच पहले किसी सरकार की नहीं थी लेकिन इस सरकार की सोच है कि दिल्ली जो हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा शहर है उसके साथ हरियाणा तीन तरफ से जुड़ता है। हरियाणावासियों को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाने के लिए अगर किसी ने स्टैप उठाया है तो सिर्फ चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने उठाया है। इससे पहले किसी ने इस बारे में स्टैप नहीं उठाया है। मैं मुख्यमंत्री जी से सुनिवेदन करूंगा कि वे हमारे प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठायें। हरियाणा की टैरीटरी जो एन.सी.आर. से लगती है उसका मैक्सिमम फायदा लिया जाना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत ज्यादा श्रेय दूंगा कि उन्होंने दिल्ली से गुड़गांव को मैट्रो से कनैक्ट करवाया है और अब फरीदाबाद भी इसी तरह कनैक्ट होने जा रहा है। मानेसर तक मैट्रो

की एक्सटैंशन करने का भी प्रस्ताव पहले से ही है। बहादुरगढ़ तक भी मैट्रो का प्रोजैक्ट आ रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से सविनय प्रार्थना करूंगा कि पानीपत, सोनीपत और रोहतक तक भी इसको एक्सटैंड किया जाए। रोहतक गेट वे ऑफ हरियाणा है। आप चाहे भिवानी जाओ, हिसार जाओ, सिरसा जाओ, दादरी जाओ या जीन्द जाओ रोहतक शहर सबसे पहले आता है। मेरा निवेदन है कि रोहतक तक मैट्रो हर हालत में आनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से सविनय निवेदन करूंगा कि वर्ष 2010-11 के बजट के अन्दर मैट्रो के लिए रोहतक, सोनीपत और पानीपत की सर्वे प्लान के लिए पैसा जरूर सैंक्शन किया जाए क्योंकि जब मैं बजट की किताब पढ़ रहा था उसमें यह आया कि इस प्लान को थोड़े टाईम के लिए डैफर किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि कम से कम इसका सर्वे इस प्लान में जरूर हो जायेगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो मुख्यमंत्री जी का प्रान्त को नई दिशा देने का जो उद्देश्य है, उसकी तरफ अग्रसर वे हो सकेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि हर हालत में मैट्रो को आगे तक बढ़ाना चाहिए। भारत सरकार की तो All India Urban Infrastructure Development Scheme है इसमें यह है कि मुम्बई, मद्रास, कोलकत्ता और दिल्ली के साथ जो सिटीज लगते हैं उनकी भी डिवैल्पमैंट की जाएगी। अब दिल्ली के साथ तो गुड़गांव भी लगता है, फरीदाबाद भी लगता है, रोहतक भी लगता है और सोनीपत भी लगता है। फिर ये कहेंगे कि रोहतक का नाम आ जायेगा। मैं रोहतक से विधायक हूं और स्ट्रैटजिक पोजिशन में रोहतक दिल्ली के साथ ही लगता है इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से सविनय निवेदन करूंगा कि रोहतक की डिवैल्पमैंट भी All India Urban Infrastructure Development Scheme के तहत की जाए। रोहतक को भी गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा की तरह एक सैटेलाईट टाऊन बनाया जाए ताकि जो दिल्ली के अन्दर ट्रैफिक का प्रैशर है वह रोहतक भी बियर कर सके। जिस तरह से बहादुरगढ़ तक मैट्रो लाईन आयेगी तो उसके बाद वह एक सुंदर शहर बन जाएगा। इलैक्ट्रिक लाईन दिल्ली से रोहतक आ रही है। अगर रोहतक में भी मैट्रो आ गयी तो उसी तरह से रोहतक भी एक सुन्दर शहर बन सकता है। हैल्थ मिनिस्टर साहब बैठे हैं इसलिए अब मैं हैल्थ के बारे में कुछ बातें करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इकोनोमिक स्टीमुलस पैकेज के तहत दो नये मैडीकल कॉलेजिज, एक सोनीपत जिले में खानपुर कलां में और दूसरा नलहार मेवात जिले में आये हैं और अब इनका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसके अलावा करनाल के अन्दर भी कल्पना चावला के नाम पर एक मैडीकल कॉलेज बनाने का सरकार ने निर्णय लिया है। सरकार का यह सराहनीय कदम है। रोहतक में पंडित भगवत दयाल पी.जी.आई.एम.एस. को जो ऐम्ज के बराबर दर्जा दिया गया है उसके लिए सरकार ने वर्ष 2010-2011 के बजट में 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं क्योंकि यह एक सराहनीय कदम है। हमारे रोहतक में जो सबसे बड़ी इन्सटीच्यूट है उसके अन्दर सुपर स्पेशलिस्टस की सभी स्कीमें आयें और इस इंस्टीच्यूट का बहुत ज्यादा विकास हो और सभी हरियाणा वासियों को किसी भी बीमारी के इलाज के लिए दिल्ली की तरफ न देखना पड़े। सभी सम्मानित विधायकों से अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि पानी हमारे प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या को दूर करने के लिए सत्ता दल और विपक्ष सभी को मिलकर प्रयत्न करना चाहिए। कल को जो पानी की प्रोब्लम और शोर्टेज हम फेस करने जा रहे हैं उसको दूर करने के लिए हम सभी को साथ होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने एग्रीकल्चर सैक्टर में वर्ष 2010-2011 में 1616.40 करोड़ रूपयों का प्रावधान रखा है जो कि बहुत अच्छा कदम है। पानी का सदुपयोग और उसको बचाने के लिए हमें सारे हरियाणा

[श्री भारत भूषण बतरा]

वासियों को अवेयर करना चाहिए। लैजीस्लेचर होने के नाते हमें अपनी कांस्टीच्युंसी के लोगों को भी अवेयर करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री महोदय और एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी से कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में लिफ्ट इरीगेशन और रेन हारवैस्टिंग को मैक्सीमम बढ़ावा दिया जाए और उसके लिए हमें किसान को 100 परसैंट सब्सिडी भी देनी पड़े तो सरकार को देनी चाहिए। ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन और रेन हारवैस्टिंग को बढ़ाकर भी हम पानी को बचा सकते हैं इससे हमारा प्रदेश समृद्धि की तरफ आगे जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर को डिवैल्प करने के लिए वित्त मंत्री जी ने जो पहल की है उसके लिए भी मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इन्होंने नॉन प्लॉन या प्लान सैक्टर में जो कुछ भी दिखाया है उसको जल्दी से जल्दी क्रियान्वित किया जाए। धन्यवाद। जय हिन्द।

मुख्य संसदीय सचिव (कुमारी शारदा राठौर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। विश्वव्यापी मंदी के चलते हुए और छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद जितना खर्चा हुआ है उसको वहन करने के बाद भी जितना शानदार, प्रगतिशील और संतुलित बजट वित्त मंत्री महोदय जी ने दिया है इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कुशल नेतृत्व को बधाई देना चाहती हूं। जहां एक ओर यू.पी.ए. अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के मार्ग दर्शन और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कुशल नेतृत्व में देश को सामाजिक और आर्थिक विकास के मामले में एक नया मार्ग दर्शन मिला है और एक नई दिशा मिली है, वहीं हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश ने पिछले 5 वर्षों में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं यह उसी कुशल नेतृत्व का नतीजा है कि हमारे यहां घोर मंदी होने के बावजूद भी रिजर्व बैंक के पास 1778 करोड़ रूपये हैं और गोआ के बाद प्रति व्यक्ति आय में हम पहले नम्बर पर हैं। इसी तरह यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि प्रति व्यक्ति निवेश में, गेहूं की उत्पादकता में और दूध की उत्पादकता में हमारा प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। इस प्रगति का लाभ संविधान की मूल भावना के अनुरूप आम व्यक्ति के पास पहुंच सके इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री चौ. भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने अनथक और ईमानदार प्रयास किया है जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि के क्षेत्र की बात करना चाहूंगी। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीड की हड्डी है। हमारे ज्यादातर लोग गांवों में रहते हैं। एग्रो बेस्ड हमारी इकोनोमी है। हमारी सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए, किसानों के हित के लिए अनेक कारगर कदम उठाए हैं। जिसके तहत किसानों की समस्याओं को जानने के लिए और उनके समाधान के लिए किसान आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है जो कि सरकार का सराहनीय कदम है। फसली मुआवजों में भारी बढ़ोतरी की गई है इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री महोदय की आभारी हूं। फसली कर्जों पर ब्याज 11 परसैंट से घटाकर 4 परसैंट किया गया है जिससे किसान को राहत मिली है। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही गलत और अशोभनीय एक कानून हुआ करता था जिसे काला कानून कहते थे जिसमें किसान को कर्जे की अदायगी न करने पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। इस प्रकार से किसान की बेइज्जती की जाती थी और पुलिस की गाड़ी उसको उठा कर ले जाती थी। वह काला कानून भी हमारी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने खत्म किया है जिससे अब किसान को एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का अवसर मिल रहा है। उपाध्यक्ष

महोदय, इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने किसानों की भूमि अधिग्रहण के नियम में भी परिवर्तन किया है उससे किसानों को बड़ी राहत मिली है क्योंकि पिछली सरकार के समय में किसी कार्य के लिए किसानों की जमीन एक्वायर हुआ करती थी तो कौड़ियों के भाव मुआवजा किसानों को दिया जाता था। उस समय किसान मुआवजा लेने के लिए नहीं जाते थे और किसान बेरोजगार हो जाते थे जिससे किसानों में एक रोष पनपता था। अब हमारी सरकार आने के बाद किसानों को शानदार मुआवजे के साथ-साथ 33 साल तक रॉयल्टी देने का भी प्रावधान किया गया है जिससे किसानों को आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा और एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का मौका मिला है। मेरे विधान सभा क्षेत्र बल्लभगढ़ में इण्डस्ट्रीयल मॉडल टाऊन बनाने के लिए सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण की गई थी उसका विरोध करने के लिए जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं जिनमें आई.एन.एल.डी., बी.जे.पी. और ह.ज.कां. आदि सब एक साथ हो गई थी। इन सभी पार्टियों ने निर्णय लिया कि जब किसान मुआवजा लेने जायेंगे उस समय जमीन अधिग्रहण के विरोध में ये मुख्यमंत्री जी का पुतला जलायेंगे। ये लोग वहां आफिस के बाहर पार्क में पुतला लेकर बैठे रहे लेकिन किसानों ने लाईन में लगकर एक-एक करके अपना मुआवजा ले लिया और इनका यह मिशन टांय-टांय फिश हो गया। माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी यहां बैठे हुए हैं। सबको मालूम है कि इनके समय में किसानों को लाठियों से, गोलियों से मारा जाता था जबकि आज माननीय अजय सिंह चौटाला जी बोलते हुए कह रहे थे कि गैस्ट टीचर्स पर लाठियां चलाई गई। मैं कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए गैस्ट टीचर्स की भर्ती की है। हमारे मुख्यमंत्री जी की हमेशा पहल रहती है कि चाहे कर्मचारी हों, किसान हों, मजदूर हों या कोई भी वर्ग आंदोलन कर रहा हो उनकी बातें सुनते हैं और उनकी जायज समस्याओं पर सही निर्णय लेते हैं। इस प्रकार से हमें माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के कुशल नेतृत्व पर गर्व है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमारी सरकार ने किसानों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा नामक ठोस योजना बनाई है जिसका लाभ किसान उठा रहे हैं। इसी तरह से युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए उद्योग धन्धो को बढ़ावा दिया जा रहा है और प्रदेश में बाहरी निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। पहले जब आई.एन.एल.डी. रिजिम्ज था उस समय प्रदेश में भय और आतंक का वातावरण बना हुआ था तथा प्रदेश से उद्योग पलायन करके जा रहे थे। हमारी सरकार के समय में गत पांच वर्षों में 40 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और 90 हजार करोड़ रुपये का निवेश विचाराधीन है। आज के दिन लोगों को सरकार के प्रति विश्वास है और बाहर से लोग हमारे प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आ रहे हैं। आज के दिन हर वर्ग हमारी सरकार की और मुख्यमंत्री जी की कार्य शैली की प्रशंसा कर रहा है और लोगों का सरकार के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जो विपक्ष के भाई एस.ई.जैड और इण्डस्ट्रीयल मॉडल टाऊन का विरोध कर रहे हैं उनको कहना चाहूंगी कि एक अच्छी पहल और शुरूआत के लिए एक अच्छी सोच की जरूरत होती है उसके बाद ही कार्य किया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने एक अच्छी शुरूआत की है और मुख्यमंत्री जी ने ठोस कदम उठाये हैं जिसके कारण प्रदेश में बहुत सारे इण्डस्ट्रियल मॉडल टाऊन बन रहे हैं। रोहतक के अंदर आई.एम.टी. बनकर तैयार हो गया है और बल्लभगढ़ में बन रहा है जिसमें आस-पास के बच्चों को रोजगार मिलेगा और हमारे उद्योगपतियों को उद्योग लगाने का भी अवसर मिलेगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से दिल्ली मुंबई फ्रेट कोरीडोर के साथ-साथ दिल्ली- मुंबई इण्डस्ट्रीयल कोरीडोर की एक शानदार परियोजना विकसित की जा रही है जिसमें

[**कुमारी शारदा राठौर**]
मोडल लोजिस्टिक हब, एग्जीबीशन कम कंवेंशन सैंटर, गुड़गांव से पलवल तक मास रैपिट ट्रांस्पोर्ट सिस्टम की योजना है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ हमारी सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए आवासीय योजना पर विशेष बल दिया जा रहा है जो कि बहुत ही सराहनीय कदम हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली के बारे में चर्चा करना चाहूंगी कि बिजली की समस्या हमें पिछली सरकार से विरासत में मिली थी और विपक्ष के भाई अब बार-बार बिजली के बारे में बात कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों से पूछना चाहती हूं कि ये अपने बारे में बतायें कि इनके शासन काल में कितने पावर प्लांट लगे ? डिप्टी स्पीकर सर, जहां तक हमारी सरकार की बात है तो मुख्यमंत्री जी ने अपने पिछले कार्यकाल में बिजली की समस्या से निजात दिलाने के लिए और प्रदेशवासियों के लिए बिजली की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अनेक नये पावर प्लांटस लगाने का कार्य पूरे जोर-शोर से शुरू करवाया है। (**इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए**) स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश के समस्त उपभोक्ताओं के लिए 5000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली पैदा करने के लिए लगभग सभी पावर प्लांटों पर कार्य युद्धस्तर पर जारी है और हमें विश्वास है कि जब हमारे सभी पावर प्लांट्स कम्पलीट हो जायेंगे तो पूरे हरियाणा प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। स्पीकर सर, हम विपक्ष के नेता के क्षेत्र फतेहाबाद में एक 2800 मेगावाट का न्युक्लिकर पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्पीकर सर, इस पावर प्लांट के बारे में भी गलत ब्यानबाज़ी की जाती है कि इससे फसलें नष्ट हो जायेंगी, प्रदूषण फैलेगा, यह हो जायेगा, वह हो जायेगा। इस प्रकार से इस पावर प्लांट को न लगने देने के लिए भी हमारे विपक्ष के नेताओं की तरफ से बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार किया जा रहा है। स्पीकर सर, सैग्रीगेशन ऑफ फीडर्ज़ का एक बहुत बड़ा फैसला माननीय मुख्यमंत्री के कुशल दिशानिर्देशन में हमारी सरकार द्वारा लिया गया है। स्पीकर सर, इसके अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं और कृषि उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग फीडर्ज़ की शुरूआत की गई है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की उपलब्धता में काफी इजाफा हुआ है। स्पीकर सर, मैं यहां पर यह अवश्य जिक्र करना चाहूंगी कि बिजली सैक्टर के लिए मुख्यमंत्री जी इतने गम्भीर और प्रतिबद्ध हैं कि सबसे ज्यादा धन अर्थात 17408 करोड़ रुपये इस बजट में बिजली सैक्टर के लिए प्रावधान रखा गया है। स्पीकर सर, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इस सैक्टर में इस धनराशि से ज्यादा ही खर्चा होने की उम्मीद है। स्पीकर सर, समाज कल्याण हमारी सरकार की नीतियों का मूल उद्देश्य है जिसमें मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कभी भी पीछे नहीं रही है। चाहे वृद्धावस्था पैंशन की बात हो, विधवा पैंशन में बढ़ौतरी की बात हो, निराश्रितों की बात हो, चाहे विकलांगों, बौनों और किन्नरों की बात हो, और चाहे इंदिरा गांधी विवाह शगुन योजना की बात हो इसके साथ-साथ इन सभी वर्गों की पैंशन में भी भारी बढ़ौतरी की गई है। स्पीकर सर, अगर मैं इस बारे में सारी फीगर्ज़ बताना शुरू करुंगी तो समय कम पड़ जायेगा। स्पीकर सर, इसी प्रकार से एस.सी, बी.सी.ए. और बी.पी.एल. के बेघर लोगों के लिए 100-100 वर्ग गज के प्लाट्स देने की एक अनूठी और अनोखी योजना शुरू की गई है। यह एक ऐसी योजना है जिसकी जितनी भी सराहना की जाये वह कम होगी। इसका लाभ हरियाणा के गरीब से गरीब परिवारों को होगा। स्पीकर सर, अभी तक सरकार की इस योजना का लाभ हरियाणा प्रदेश के 2 लाख 77 हज़ार परिवार उठा चुके हैं। अभी और बहुत सारे गरीब परिवारों को हमारी इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए हमारी सरकार के प्रयास जारी हैं। स्पीकर सर, बजट में सोशल सैक्टर के लिए 6341 करोड़ रुपये रखना अपने आप में एक बहुत

ही प्रशंसनीय कदम है। स्पीकर सर, शिक्षा और स्वास्थ्य हरियाणा सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार दो क्षेत्र हैं क्योंकि इन्हीं से हमारे मानव संसाधनों का विकास सम्भव है। स्पीकर सर, आज का युग विज्ञान का युग है, तकनीकी का युग है और मैं कहना चाहूंगी कि परिवर्तन का भी युग है। स्पीकर सर, हमारी सरकार इसके लिए प्रयासरत है कि हमारे बच्चों को गुणवत्ताएूर्ण और अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके। स्पीकर सर, सरकार ने अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 16162 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में रखा है। स्पीकर सर, मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी शिक्षा को लेकर बहुत सजग और गम्भीर हैं जिसके चलते हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आये हैं और बहुत सारी विशेष योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू हुआ है जिसका परिणाम यह निकल कर सामने आया है कि हरियाणा एजुकेशन हब के रूप में विकसित हो रहा है। स्पीकर सर, सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, गुड़गांव में नैशनल डिफैंस यूनिवर्सिटी, महेन्द्रगढ़ में सैंट्रल यूनिवर्सिटी और सोनीपत में भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी ये बहुत सारी ऐसी शुरूआतें हैं जिनका परिणाम आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ियों के सुखद और उज्जवल भविष्य के रूप में निकलेगा। स्पीकर सर, इसके लिए हमारी आने वाली पीढ़ियों के विद्यार्थी हमेशा ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ऋणी रहेंगे। स्पीकर सर, अब मैं तकनीकी शिक्षा के बारे में बात करना चाहूंगी कि तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने ज़मीनी स्तर पर अनेक कारगर कदम उठाये हैं। स्पीकर सर, वर्ष 2004-05 तक, जब हरियाणा प्रदेश में श्री चौटाला जी की सरकार थी, कुल 154 तकनीकी संस्थान थे। जिनका टोटल इनटेक 27142 था। अब माननीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के प्रयासों के चलते आज हरियाणा प्रदेश में लगभग 546 तकनीकी संस्थान हैं और इनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों का इनटेक 112910 है। स्पीकर सर, यह जो संख्या मैंने बताई है यह भी निरन्तर बढ़ती जा रही है। स्पीकर सर, गुरुग्राम में दीन बंधु सर छोटू राम साईंस एण्ड टेक्नालॉजी संस्थान बना है जिसमें हमारे बहुत सारे बच्चे दाखिला ले रहे हैं। उसमें हमारे द्वारा नये कोर्सिज़ शुरू किये जा रहे हैं। स्पीकर सर, मैंने स्वयं इस यूनिवर्सिटी का विज़िट किया है इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्तमंत्री जी से ये अवश्य कहना चाहूंगी कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम लाने के लिए ये बजट में इस संस्थान के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रावधान रखें ताकि जो उनके भवन निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जा सके और यूनिवर्सिटी का काम सुचारू रूप से चल सके। इसी तरह से वाई.एम.सी. फरीदाबाद को भी अपग्रेड करके साइंस एण्ड टैक्नॉलॉजी यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित किया गया है और इसकी भी एक्सपैन्शन का काम चल रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा गाँव गरनावठी, जिला रोहतक में आई.आई.एम. की स्थापना हो रही है और इसी तरह से हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनैस, गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार में चल रहा है। अभी हमारे भाई अजय सिंह चौटाला बोल रहे थे कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि सभी तकनीकी संस्थानों में 25 प्रतिशत होरिजैन्टल रिजर्वेशन है। मेवात में जो हमारा गवर्नमैंट पॉलिटैक्निक कॉलेज है उसमें 50 प्रतिशत आरक्षण सिर्फ मेवात के बच्चों को तकनीकी शिक्षा देने के लिए हमारी सरकार ने किया है। मैं यहाँ पर एक बात अवश्य कहना चाहूँगी कि जो हमारे एस.सी./एस.टी. के स्टूडैंट्स हैं उनके लिए ट्यूशन फीस में रिइम्बर्समैंट हो रही है। केन्द्र सरकार और हरियाणा सरकार के ज्वाइंट वैंचर से तकनीकी शिक्षा के 6-6 महीने के कोर्सिज़ जो हमारे 10वीं और 12वीं पास बच्चे हैं, उनको दिये जाते हैं ताकि उन्हें रोजगार प्राप्त करने में आसानी हो सके।

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी वाइंड अप कीजिए।

कुमारी शारदा राठौर : सर, मेरी एक सबमिशन सुन लीजिए क्योंकि ऐज ए चीफ पार्लियामैंट्री सैक्रेट्री हम सवाल भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप मुझे दो मिनट का समय और दीजिए। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सरकार ने 3364 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है जो बहुत सराहनीय है। हरियाणा में कई नए मैडीकल कॉलेज खुलने जा रहे हैं। मल्टीस्पैशलिटी होस्पीटल खुल रहे हैं, होस्पिटल्ज़ को अपग्रेड किया जा रहा है। इसी प्रकार से सर्जरी पैकेजिज दिये जा रहे हैं तथा दवाईयाँ भी मुफ्त दी जा रही हैं। इसी तरह से इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना और नेहरू दृष्टि योजना अपने आप में बड़ी अनूठी योजनायें हैं। परिवहन में, पर्यटन में, सूचना प्रोद्योगिकी में और रेलवे से सम्बन्धित सरकार ने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। सड़कों या पुलों के निर्माण की बात करें तो इसके लिए भी हमारे मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मैं आखिर में एक बात और कहना चाहूँगी कि आज के प्रतिकूल हालात में जहाँ पूरा विश्व घोर मंदी के दौर से गुजर रहा है वहाँ अपने आप में अपनी अर्थ व्यवस्था को मजबूत करके कायम रखना यह बहुत बड़ी चुनौती थी और माननीय वित्त मंत्री जी ने यह करके दिखाया है। पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप को अपनाना ही होगा और उसी से हम विकास की गति में आगे बढ़ पायेंगे। हरियाणा इन्फ्रास्ट्रक्टर डिवैल्पमैंट बोर्ड की स्थापना की गई है। ये दो लाईनें हमारे भाई अजय सिंह चौटाला के लिए हैं। आपकी तारीफ में जिस वक्त सब कुछ कह दिया फिर भी दिल कहने लगा बाकी था वो रह गया, धन्यवाद।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक प्रार्थना है कि ज्यादातर सदस्य नये चुन कर आये हैं। इसलिए उनको ज्यादा मौका दिया जाय। यही एक मौका है उसके बाद तो 6 महीने बाद मौका मिलेगा।

श्री शेर सिंह बड़शामी (लाडवा) : अध्यक्ष महोदय, बजट सरकार का आईना होता है जिसमें सभी विभागों का लेखा-जोखा दर्शाया जाता है। बजट में सरकार की योजनाओं का और परियोजनाओं का ब्यौरा दिया जाता है लेकिन जो मौजूदा बजट है उसमें कई अहम भूतों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। कई विभागों पर जितना खर्च होना चाहिए था उतना नहीं दर्शाया गया है। मैं एस.वाई.एल. पर विशेष तौर से चर्चा करना चाहूँगा। कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव में भी अपने मैनिफैस्टो में एस.वाई.एल. के मुद्दे को रखा था और हरियाणा की जनता से वादा किया था कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो हम एस.वाई.एल. कैनाल का निर्माण कार्य पूरा करवायेंगे तथा हरियाणा की प्यासी भूमि को पानी देने का काम करेंगे और इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफैस्टो के अन्दर यह मुद्दा रखा था। स्पीकर सर, 15 जनवरी, 2002 को सर्वोच्च न्यायालय से हरियाणा के हक में फैसला हुआ और सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब की सरकार को इसकी कम्पलीशन के आदेश दिए थे। 20 नवम्बर, 2002 को हरियाणा की सरकार ने एग्जीक्यूशन डाला था। 4 जून, 2004 को फिर सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र की सरकार को आदेश दिए कि इसको दो साल के अन्दर पूरा करवाने का काम करें। उसके बाद 12 जुलाई, 2004 को पंजाब की सरकार ने एक विधेयक पारित किया जिसको टर्मीनेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है। आज मौजूदा सरकार हर मंच से कहती है कि एस.वाई.एल. का मुद्दा न्यायालय के अन्दर विचाराधीन है इसलिए हम इस बारे में कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। मैं इस बारे में खोलकर सदन में बताना चाहता हूँ कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है उस फैसले के ऊपर सारे देश के अन्दर कोई भी पाबन्दी नहीं लगी हुई है। यदि केन्द्र की सरकार की नियत साफ हो तो वह आज भी एस.वाई.एल.

कैनाल के निर्माण कार्य को पूरा करके हरियाणा की प्यासी भूमि को पानी दे सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं मौजूदा सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट के द्वारा दी हुई जजमैंट को कोई प्रादेशिक सरकार रद्द कर सकती है या नहीं कर सकती है ? अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या कोई प्रादेशिक सरकार दूसरी सरकार द्वारा पास किए गए एक्ट को रिपील या रद्द कर सकती है या नहीं कर सकती है। आज महज लोगों को बहकाने का काम किया जा रहा है। किसी पर कोई पाबन्दी भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, (विघ्न)

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : स्पीकर सर, एस.वाई.एल का मामला सब-ज्यूडिश है इसलिए इस बारे में सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, टर्मीनेशन ऑफ एग्रीमैंट की जो बात इन्होंने कही है यह रैफरैंस सब-ज्यूडिश है। (विघ्न)

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, मैं यही क्लीयर कर रहा हूं कि रैफरैंस जो है वह केस नहीं होता है। केस हमेशा बिटविन दि पार्टीज होता है। रैफरैंस अन्डर 143 सुप्रीमकोर्ट से एडवाईस मांगी गई है। अध्यक्ष महोदय, उस पर अमल करने और न करने के लिए कोई सरकार बाध्य नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के आर्टीकल 262 के तहत केन्द्र की सरकार को पूरे अधिकार प्राप्त हैं। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, ऑन ए प्वायंट आफ आर्डर। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मिस्टर बड़शामी, आप प्लीज अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, जो यह बात कह रहे हैं (विघ्न) I just want to say that whatever he has said for that I have already said about it. प्रैजेन्ट रैफरैंस ऑलरेडी यूनियन गवर्नमैंट ने दे रखा है। इस पर बाकायदा हियरिंग लिस्टड है। गवर्नमैंट पर वे हमें सुनेंगे। इस बात पर फैसला हो जाएगा लेकिन यह कहना कि यह मामला किसी भी कोर्ट में नहीं है, यह बिल्कुल गलत बात है। ये हाऊस को मिसलीड कर रहे हैं। यह केस सुप्रीमकोर्ट के अन्दर विचाराधीन है और ये इस बात के लिए हाऊस को मिसलीड न करें। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : हां सुरजेवाला जी बोलें। (विघ्न) let him speak.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मेरे काबिल दोस्त ने यह कहा है कि सरकार ने एस.वाई.एल. के बारे में बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है और कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन नहीं है। मैं चार फैक्टस केवल आपकी अनुमति से इस सदन में बताना चाहूंगा। सर, एस.वाई.एल. पर हरियाणा का हिस्सा स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा बतौर प्रधानमंत्री निर्धारित करके तय किया गया था। जब यह हिस्सा दिया गया था उसके बाद उस समय की जनता पार्टी की सरकार ने उस हिस्से को चुनौती दी थी। (विघ्न) Only four facts and four dates are important. (Interruptions) I am speaking with your permission, Sir. (Interruptions).

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं बड़शामी जी, आपके टाईम को कोई खतरा नहीं है। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, उस समय की जनता पार्टी की सरकार ने श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की कांग्रेस की सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। सर, फाईनली एक ट्राईपर्टाइट एग्रीमैंट हुआ, जिसमें हरियाणा पार्टी है, जिसमें राजस्थान पार्टी है और उस ट्राईपर्टाइट एग्रीमैंट पर प्रधानमंत्री के भी दस्तखत हैं। जिससे 3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी हमें दोबारा से मिल गया। सर, उसके बाद इन्होंने न्याय युद्ध शुरू कर दिया। (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : सर, क्या ये रिप्लाई दे रहे हैं ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सुरजेवाला जी, आप उतनी बात का ही जवाब दें। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं उससे चौटाला साहब जी को डर लग रहा है। (विघ्न) मुझे मालूम है और ये डर रहे हैं क्योंकि उस अगली बात के अन्दर इनकी पोल खुलनी है। (विघ्न) इसलिए इन्होंने मेरी बात सुनने से पहले ही शोर करना शुरू कर दिया है। (विघ्न)

सर, जो इनके लीडर यहां पर बैठे हैं उन्होंने जल युद्ध किया, न्याय युद्ध किया। राजीव गांधी जी ने जो ऐकोर्ड किया था वह राजीव गांधी लोंगोवाल ऐकोर्ड था। इन्होंने उसका बायकाट किया और उसको साईमन कमीशन की संज्ञा दी। स्पीकर सर, कांग्रेस की सरकार ने ही हरियाणा का साढे तीन मिलियन एकड़ फुट पानी का केस जीता था। सर, पंजाब की विधान सभा ने जो वाटर ऐग्रीमैंट टर्मीनेशन ऐक्ट पास किया था उसको इसने ही चुनौती दी थी। उसके बाद यह मैटर प्रैजीडैंशियल रैफरैन्स के लिए गया है।

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, रैफरैन्स में और केस में अंतर होता है। केस जो है that is between the parties और रैफरैन्स जो है वह मात्र एक सलाह होती है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्रपति द्वारा किया गया रैफरैन्स है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। मेहरबानी करके आप मेरी बात सुनें क्योंकि आप हाऊस के कस्टोडियन हैं। बात यह चल रही थी कि यह मामला सब ज्युडिश है या नहीं ? लेकिन इसके ऊपर ये सब चाहे भाषण देना शुरू कर देते हैं। आखिर इससे सदन का समय खराब होता है या नहीं ? अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं एक लॉ ग्रेजूएट हैं इसलिए मैं आपसे यह फैसला लेना चाहूंगा कि क्या रैफरैन्स भी सब ज्युडिश मैटर में आता है ?

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप इस बारे में बताएं क्योंकि आप इरीगेशन मिनिस्टर हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, एक बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरैक्शन दी कि पंजाब एस.वाई.एल.कैनाल को कंस्ट्रक्ट करे। दूसरी बात यह है कि पंजाब ने वाटर ऐग्रीमैंट टर्मीनेशन ऐक्ट पास करके सारे वाटर ऐग्रीमैंट निरस्त कर दिए और तीसरी बात यह है कि गवर्नमैंट ऑफ इंडिया द्वारा एस.वाई.एल. कैनाल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए प्रैजीडैंशियल रैफरैन्स एडवाइज के लिए भेजा गया है कि पंजाब विधान सभा द्वारा जो वाटर ऐग्रीमैंट टर्मीनेशन ऐक्ट पास किया गया है, वह ठीक पास किया गया या नहीं ? सर, हमने यह रैफरैन्स सुप्रीम कोर्ट को दे रखा है। सर, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि that is why we cannot go for contempt against

Punjab Government when the case is sub-judice. He is misleading the House. How can he say that the matter is not in the Court ?

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, मैं हाऊस को मिसलीड नहीं कर रहा हूं। बाकायदा मैं यह किताब दिखा रहा हूं। ये भी पढ़ लें और इसको देख लें। हिन्दुस्तान के संविधान के अनुसार आर्टीकल 262 के तहत केन्द्र की सरकार के लिए कोई पाबंदी नहीं है, वह चाहे तो कुछ भी कर सकती है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इससे आगे मैं अपनी बात बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी का एक बार नहीं बल्कि कई बार ब्यान आया है कि हम हरियाणा का हाई कोर्ट अलग बनाएंगे। केन्द्रीय मंत्री श्री हंसराज भारद्वाज जी का भी ब्यान आया है कि रि-आर्गेनाइजेशन ऐक्ट के तहत हरियाणा का अलग हाई कोर्ट का अधिकार बनता है। अध्यक्ष महोदय, हमने भी हरियाणा का अलग हाई कोर्ट बनाने की मुहिम चलायी थी लेकिन उस समय कोई टैक्नीकल प्रॉब्लम आ गयी थी। 9 तारीख को भी इस बारे में मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे सवाल का जबाव दिया था लेकिन वह भी सरसरी जबाव ही था हालांकि मैं उस दिन सदन से सस्पैंड था। मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है जिस तरह से सैक्रेटेरिएट की बिल्डिंग हमने बांट ली है उसी तरह से हाई कोर्ट की बिल्डिंग भी हम बांट लेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर हरियाणा का अलग से हाई कोर्ट बनेगा तो क्या उसको बनाने के लिए पैसा भी रखा गया है या नहीं रखा है ?

श्री अध्यक्ष : शेर सिंह जी, क्या आप यह बजट पर बोल रहे हैं ?

श्री शेर सिंह बड़शामी : सर, मैं बजट पर ही बोल रहा हूं। * * *

Mr. Speaker : No, this is not to be recorded. No, Barshami Ji, it will not come on record. (interruptions) Barshami Ji, you are going out of track.

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : यह मुद्दा नहीं है बजट है। No, No. I will not allow it.

श्री शेर सिंह बड़शामी : सर,* * *

श्री अध्यक्ष : शेर सिंह जी, मैं तो समझता था कि आप बहुत बढ़िया बात करेंगे, बढ़िया बोलेंगे, बहुत कमाल की बात करेंगे लेकिन आपने तो वाकई बहुत कमाल की बात कर दी। आप तो कहां से कहां चले गए। मैं तो आपको सुनने के लिए दौड़कर आया था।

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि मुख्यमंत्री जी मेरी बात का जबाव दें।

Mr. Speaker : Barshami Ji, your time is running.

श्री शेर सिंह बड़शामी : टाईम तो भाग ही रहा है। सर, मैं कहना चाहता था।

Mr. Speaker : Barshami Ji, you come on the Budget.

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, अब मैं एस.वाई.एल. से जुड़ी हुई बात यहां कहना चाहता हूं। एस.वाई.एल. के बारे में इस बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। मुख्यमंत्री जी ने एक बात को दोहराया कि राजीव लौंगोवाल ऐकोर्ड को यदि चौधरी देवीलाल जी अपोज न करते तो यह जो प्रदेश में पानी का मसला है, यह कभी का हल हो जाता। अध्यक्ष महोदय, राजीव लौंगोवाल ऐकोर्ड की कॉपी मेरे पास है इसकी जो क्लॉज -7 है। (विघ्न)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : It is not the part of the Budget. (interruptions) You come on the Budget. आपको ये बातें बजट पर कहनी चाहिए थी कि ये पैसा ऐसे इस्तेमाल करो, इस स्कीम के लिए इतना पैसा रखा गया है। बजट पर तो आपने कोई बात कही नहीं है सिर्फ भाषण दे रहे है। जलसे की भाषा यहां पर न बोलो। This is not the way. (interruptions) Please leave the matter. आपने तो मेरी सारी उम्मीदें ही खत्म कर दीं। (विघ्न) आप बजट पर बोलें।

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, जब राजीव लौंगोवाल ऐकार्ड हुआ था उस समय रघुबीर सिंह कादयान, धर्मबीर सिंह और आप भी हमारे साथ थे। कैप्टन अजय जी, आपके पिता श्री भी हमारे साथ थे। (शोर एवं व्यवधान)

Capt. Ajay Singh Yadav : My father was never in Lok Dal.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : आप तो लोकदल में थे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : हां मैं था। ऐसे तो चौटाला साहब भी कांग्रेस में रहे हैं।

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, जननायक चौधरी देवी लाल जी ने जल के लिए जो न्याय युद्ध चलाया था उसमें आप सारे के सारे थे और मैं बताना चाहूंगा कि उसी वजह से आज आप यहां हैं। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): आप यह नहीं कह सकते कि सारे के सारे उस समय लोकदल में थे। यह बात आप नहीं कह सकते हैं।

श्री शेर सिंह बड़शामी : मुख्यमंत्री जी, आप नहीं थे आपको छोड़कर सारे के सारे थे।

श्री अध्यक्ष : जो कोई खड़ा हो जाता है उसी को आप कह देते हो कि आप नहीं थे बाकी सारे थे, ये क्या बात हुई!

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि शिक्षा नीति के बारे में सरकार ने बड़ा ढिंढोरा पीटा कि हमने नयी शिक्षा नीति लागू की है और हम हरियाणा में शिक्षा को बढ़ावा देंगे। मैं कहना चाहूंगा कि नयी शिक्षा नीति के नाम पर सरकार द्वारा एजूसैट की परियोजना चलाई गई लेकिन उसके बारे में सरकार ने यह नहीं सोचा कि ये कंप्यूटर कहां रखे जाएंगे, इनके लिए बिजली का बंदोबस्त कैसे होगा, इनको कौन चलाएगा ? यदि बिजली नहीं होगी तो इन कम्प्यूटर्ज को चलाने के लिए क्या बंदोबस्त होंगे ? इन सारी चीजों का बंदोबस्त करने की बजाय केवल मात्र कंप्यूटर्ज खरीदने पर जोर दिया गया। यह बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और मैं मांग करता हूं कि इसके लिए सदन की एक कमेटी बनाकर इसकी इंक्वायरी कराने का काम किया जाए। बी.एड और इंजीनियरिंग के कालेज खोलकर प्रदेश में * * * * * हरियाणा के पैसे को पूरी तरह से बेकार करने का काम किया है। जहां तक राजीव गांधी एजूकेशन सिटी की बात है। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में इंजीनियरिंग, मैडिकल और मैनेजमैंट कॉलेज खोलने का काम कोई बुरा काम नहीं है यह बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि शेर सिंह बड़शामी जी ने जो शिक्षा को * * * * वाला शब्द कहा है उसको कार्यवाही से निकाल

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह * * * * शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इनके जो नेता है उन्होंने खुद इस तरह के कालेजिज खोल रखे हैं, बड़शामी जी उनसे पूछ लें कि वे क्यों शिक्षा को बेचने का काम करते हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बड़शामी जी, आप बैठ जाईये। आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है।

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो तीन सवाल पूछे हैं, वित्त मंत्री जी कृपा करके उनका जवाब दे दें। मैं बैठ जाता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सतपाल सांगवान (चरखी दादरी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सर, जो कप्तान अजय सिंह यादव ने बजट पेश किया है यह बहुत सराहनीय बजट है। बहुत कठिन हालात में कप्तान साहब ने यह बजट पेश किया है। हमारी स्टैम्प ड्यूटी में कमी आ गई, माईन्स रिवेन्यू में कमी आ गई और भगवान ने भी साथ नहीं दिया। बारिश नहीं हुई लेकिन उसके बावजूद भी जितना बढ़िया बजट इन्होंने पेश किया है उतना अच्छा बजट आज तक किसी ने पेश नहीं किया चाहे उधर के भाई कुछ भी बोलते रहें। सर, आप बजट एट ए ग्लांस देखिए। कप्तान साहब ने सबसे ज्यादा पैसा एजूकेशन पर खर्च करने का प्रस्ताव किया है। बजट एट ए ग्लांस बता रहा है कि यह बजट कितना सराहनीय है। सर, एजूकेशन में 16.12 प्रतिशत बजट दिया गया है। बिल्डिंग एण्ड रोड्ज, इरीगेशन और वाटर सप्लाई एण्ड सेनीटेशन जो आज के दिन मेन सैक्टर्ज हैं, इन सब का ध्यान रखते हुए यह बजट बनाया गया है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, ईरीगेशन पर तो बहुत कम पैसा दिया गया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : माजरा साहब, आप बैठ जाईये। (विघ्न)

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, आज की मेन समस्या बिजली की समस्या है। (विघ्न) माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेदड़ और यमुनानगर में जो बिजली के दो प्लांट लगाये हैं वे बहुत ही सराहनीय हैं। अध्यक्ष महोदय, ये लॉ एण्ड ऑर्डर की भी बात करते हैं। इनके शासनकाल में अगर कोई बच्चा नहीं सोया करता था तो लोग कह देते कि मुख्यमंत्री आ गया है इसलिए अब सो जा। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। हमारे घर में मैं और मेरी बीवी रहते हैं। मैं कभी अगर लड़ पड़ता था तो वह तभी चौटाला का नाम ले लिया करती थी और मैं तुरन्त दूर चला जाता था।(शोर एवं व्यवधान) सर, यह सच्चाई है। दादरी में एक मर्डर हुआ और उस मर्डर में मैंने रोला मचा दिया कि पकड़ो यह डिफाल्टर है। (शोर एवं व्यवधान) वे इनके ही आदमी थे लेकिन मेरे को धारा 120 बी. के तहत फंसा दिया गया। यह केस 6 साल तक लटकता रहा और मैं इतने समय तक छिपता रहा। मुझे उस वक्त स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी ने कहा था कि अगर तू पकड़ा गया तो ये * * * * * तूझे ऐसा कर देंगें कि जिंदगी में याद रखेगा। इन्होंने पूरा जोर लगा लिया लेकिन मैं इन द्वारा पकड़ा नहीं गया। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : यह * * * * * लफ्ज काट दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैं हाऊस में बोल रहा हूँ इसमें कोई झूठ बात नहीं है। मैं सच्चाई के साथ कहता हूं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इनको सुनना पड़ेगा। मेरे ये दांत यूं ही नहीं टूटे हैं, ये भी इनके ही तोड़े हुए हैं। मेरा मैडीकल हुआ है। मैंने 2000 रूपये में ये ठीक करवाएं हैं। इन्होंने मेरा दफ्तर भी तोड़ा है, इन्होंने मेरे बेटे का हाथ भी तोड़ा है और आज ये लोग लॉ एण्ड आर्डर की बात करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) इनके समय में गरीब आदमी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। मेरे बड़े भाई ने यह कहा कि हमारी सरकार का प्रशासन बहुत स्वच्छ है। नगीना थाने के अंदर * * * * *

श्री अध्यक्ष : क्या यह प्वांयट आफ आर्डर है ? It is not a point of order. Please take your seat. Noting is to be recorded. (Noise & interruptions).

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, दादरी के थाने की बात तो आप सुन लेते हैं लेकिन नगीना थाने की बात पर आपको एतराज हो जाता है यह कोई बात थोड़े ही है। यह बजट का भाषण है। आप उनकी तो बात सुन लेते हो लेकिन जब हमारा सदस्य बोलता है तो उसकी बात नहीं सुनते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, इनका यह प्वांयट आफ आर्डर नहीं बनता। This is not the way. (Noise & interruptions).

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, जिसको लगती है वहीं जानता है इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। मेरे भी लग रही है इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं 6 साल के बाद आज भगवान की दया से बरी हुआ हूं, यह रिकार्ड की बात है। मुझे यह बताया गया कि मुख्यमंत्री के घर से टेलीफोन आया कि इसको पकड़ो, इसकी जमानत मत होने दो। इनको बताओ कि विधानसभा में यही बोला था। अध्यक्ष महोदय, ये मुझे मारना चाहते थे। मैं जनता से पुकार करता हूं कि इनको ऐसा मौका फिर मत देना नहीं तो ये मेरे जैसे का फिर से कचूमर निकाल देंगें। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरी कांस्टीच्युंसी के लोग बहुत खुश है क्योंकि हमारे इलके की 100 बैड के होस्पिटल की डिमांड बहुत सालों से चली आ रही थी उसको पूरा किया गया है। मैं मुख्यमंत्री महोदय और गीता भुक्कल जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने पहले ही अटैम्पट में हमारे उस होस्पिटल को मंजूर कर दिया है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपने यहां के लोगों की तरफ से इनका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, कोमैंटस तो कोई किसी पर भी कर सकता है। हैल्थ में फ्री मैडीसन और फ्री सर्जरी की सुविधाएं हमारी सरकार ने दी हैं। इससे ज्यादा ये और क्या चाहते हैं ? जब ये हमारा सिर फोड़ा करते थे तब भी हमें ये चीजें फ्री नहीं मिलती थी। (शोर एवं व्यवधान) भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में जो बिजली के 1600 करोड़ रूपये के बिल माफ किए गए हैं इसके लिए मैं उनका आभारी हूं क्योंकि सबसे ज्यादा इफैक्टिड एरिया मेरा जिला था इसमें कोई शक की बात नहीं है because that is a total tubewell irrigated area. ये कह रहे थे कि 21 आदमियों से सरकार बनाई, उसको छोड़ो, बनाई परन्तु फिर इनकी सरकार आई कैसे ? अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये कहते थे कि जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा उस

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

दिन से बिजली पानी के बिल माफ हो जायेंगे मेरे उस पर दस्तखत हो जाएंगे लेकिन इन्होंने लोगों के साथ जगह जगह झगड़े कराए, एजीटेशंज कराए। अध्यक्ष महोदय, वहां एक स्लैब सिस्टम होता था। जो पानी की गहराई के हिसाब से होता था। उस समय 100 गज, 150 गज, 200 गज या उससे अधिक गहराई के स्लैब बने हुए थे। इन्होंने बिजली के बिल माफ करने की बजाय स्लैब सिस्टम को खत्म करके बिजली के बिल फ्लैट रेट पर कर दिए। अध्यक्ष महोदय, अब बरसात भी नहीं हो रही है और नहरी पानी की भी कमी है। हमारे एरिया में जहां पहले साढ़े सात हॉर्स पावर की मोटर लगती थी वहां 15 हॉर्स पावर की मोटर लगानी पड़ रही है और किसान बेचारे मर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े दरियादिल हैं इसलिए मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे एरिया के लिए बिजली के बिलों पर स्लैब सिस्टम लागू किया जाये। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे एरिया में टोटल स्कीम्ज लिफ्ट इरीगेटिड चल रही हैं। मैं इरीगेशन मिनिस्टर से, वित्त मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो हमारे पम्प हाऊसिज हैं उनकी मुरम्मत ठीक ढंग से करवाई जाये।

श्री अध्यक्ष : सांगवान साहब, प्लीज अब आप बैठें।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो बातें अपने हल्के की कह कर बैठता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे दादरी के अंदर सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की एक सीमेंट फैक्ट्री चल रही थी वह अब बंद पड़ी है। उसके बारे में हमारे सदन के एक मैंबर ने जब लोक सभा चुनाव हुए तब कहा था कि अगर मैं एम.पी. बन जाऊंगा तो इस सी.सी.आई. (सीमेन्ट फैक्ट्री) को चलवा दूंगा। मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि उस फैक्ट्री के मकान, बिल्डिंग आदि बेकार हो रहे हैं इसलिए वहां पर कोई दूसरी इण्डस्ट्री का इंतजाम कर दिया जाये तो दादरी की जनता पर बहुत मेहरबानी होगी।

श्री अध्यक्ष : सांगवान साहब, प्लीज अब आप बैठें।

श्री सतपाल सांगवान : सर, मुझे अपने हल्के की एक दो बातें कहनी हैं। अध्यक्ष महोदय, दादरी और भिवानी रोड पर हर रोज 5000 डम्प चलते हैं इसलिए वहां पर एक ट्रोमा सैंटर भी बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वर्तमान वर्ष महिला वर्ष है इसलिए दादरी के अंदर एक महिला कालेज बना दिया जाये ताकि वहां की लड़कियां भी पढ़ सकें। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपका धन्यवाद करता हूं और बजट का समर्थन करता हूं।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह के हालात दुनिया में बने हुए हैं उससे पूरी दुनिया चिंतित है। सभी को मालूम है कि आज मंदी का दौर चल रहा है और बजट पर हर आदमी की निगाह होती हैं। हमें भी बड़ी चिंता थी कि इस मंदी के महौल में हरियाणा प्रदेश का बजट किस प्रकार का आयेगा। मैं माननीय वित्तमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्ग दर्शन में 10 तारीख को बहुत अच्छा बजट मंदी के माहौल के बावजूद हरियाणा की जनता को दिया है। अध्यक्ष महोदय, बोलने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। कोई भी सदस्य सदन में किसी प्रकार का कॉमेंट कर सकता है, इसका हर सदस्य को राईट है। बजट पेश होने के बाद विपक्ष के साथियों ने

[श्री प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा]

बहुत सी बातें कहीं। मैं तो केवल यही कहना चाहूंगा कि किसी के कहने मात्र से कोई बजट बुरा नहीं हो सकता। बजट को पेश हुए पांच दिन हो गये और इसके बीच में दो दिन की छुट्टी भी थी जिनमें सभी विधायक अपने हल्कों में भी होकर आये हैं। सभी आदरणीय साथी अभी सदन में बैठें हुए हैं और सभी को मालूम है कि हरियाणा प्रदेश में बजट को लेकर किसी जगह पर या किसी गांव में कोई विरोध नजर नहीं आता। यदि बजट का कहीं विरोध हो रहा है तो वह इस सदन के थोड़े से एरिया में हो रहा है, बाकी कहीं विरोध नजर नहीं आ रहा। यह इस बात का सबूत है कि हरियाणा की जनता ने बजट पसंद किया है क्योंकि यह आम आदमी का बजट है जिसमें कोई भी सैक्टर नहीं बचा जिस पर वित्तमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने ध्यान न दिया हो। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा बजट सैशन में विपक्ष की तरफ से एक बात यह भी सुनने को मिल रही है कि क्षेत्रवाद की राजनीति हो रही है और मुख्यमंत्री जी जिस विधान सभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं वहां पर ज्यादा विकास हो रहा है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि क्षेत्रवाद की बात में सच्चाई नहीं है क्योंकि मैं इस बारे में कुछ तथ्यों की जानकारी इस सदन में देना चाहूंगा। स्पीकर सर, हरियाणा विधान सभा में एक दड़बाकलां हल्का था जहां से पहले मैं चुनाव भी लड़ता था। यह हल्का सिरसा जिले के साथ-साथ सिरसा पार्लियामैंट्री कांस्टीच्युएंसी का भी हिस्सा था। स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विकास के मामले में सिरसा जिले के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। स्पीकर सर, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि सिरसा जिले का अगर सही मायनो में विकास हुआ है तो वह चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही हुआ है। स्पीकर सर, यह केवल मेरे कहने की बात नहीं है बल्कि यह सब तो आंकड़ें ब्यान कर रहे हैं। स्पीकर सर, आज सभी एजूकेशन की बात कर रहे हैं। एजूकेशन का महत्व भी बहुत ज्यादा है। आज के युग में अगर शिक्षा नहीं है तो यह समझा जाता है कि कुछ भी नहीं है क्योंकि शिक्षा से ही हम सभी प्रकार की प्रगति कर सकते हैं। स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जब ये पहली बार सिरसा गये तो इन्होंने अनेकों घोषणाएं की। स्पीकर सर, हमारे सिरसा जिले के अंदर हमारे बहुत ही सम्मानित नेता चौधरी देवी लाल जी के नाम पर सिरसा में यूनिवर्सिटी बनाई गई है। स्पीकर सर, तत्कालीन सरकार द्वारा वह यूनिवर्सिटी शुरू तो कर दी गई थी लेकिन यह सच्चाई है कि जिस सरकार के समय में यह यूनिवर्सिटी शुरू हुई ये तथ्य सामने हैं कि वह सरकार जब तक रही उस सरकार के शासन काल में उस यूनिवर्सिटी के ऊपर सिर्फ 1642 लाख रुपये ही खर्च हुए थे। स्पीकर सर, आदरणीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने वहां पर उस यूनिवर्सिटी के विकास का ऐलान किया और इनके पिछले साढे चार साल के शासन काल का रिकार्ड है कि इनके शासन काल के दौरान उस यूनिवर्सिटी पर 7459 लाख रुपये यानि 74.59 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। स्पीकर सर, इस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने विपक्ष के साथियों की सरकार से लगभग पांच गुणा ज्यादा धनराशि इस यूनिवर्सिटी के ऊपर विकास के निर्धारित उद्देश्य को हासिल करने के लिए खर्च की। स्पीकर सर, यह माननीय मुख्यमंत्री जी की अच्छी सोच का ही परिणाम है। स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में भी यह बात कही थी कि लोग चाहे कुछ भी कहें यह यूनिवर्सिटी चौधरी देवी लाल जी के नाम पर बनी है इसका यह मतलब नहीं है कि इस यूनिवर्सिटी से कोई भेदभाव किया जायेगा। स्पीकर सर, मैं सिरसा जिले के लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि यह यूनिवर्सिटी इतनी ज्यादा प्रोग्रैस करेगी जितनी ज्यादा प्रोग्रैस हरियाणा प्रांत के अंदर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ और

इंस्टीच्युशंज़ कर रहे हैं। स्पीकर सर, यह एक तथ्य है। स्पीकर सर, अब मैं इरीगेशन सैक्टर के ऊपर बात करना चाहता हूं। स्पीकर सर, आज ओटू वियर का नाम सभी जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि उस ओटू वियर की खुदाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से आज जो व्यवस्था हुई है वह काबिलेतारीफ है। स्पीकर सर, पानी की जो कमी है और जिससे आज पूरा हरियाणा प्रांत जूझ रहा है सिरसा जिला भी उससे अछूता नहीं है। स्पीकर सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इन्होंने ओटू वियर की खुदाई के ऊपर 45 करोड़ रुपये लगाये। ओटू वियर में जो पानी स्टोर हुआ है उसकी वजह से आज सिरसा जिले के अलावा राजस्थान के साथ लगते वैरानी इलाके के किसानों की फसलें पक रही हैं। स्पीकर सर, ओटू वियर का एरिया 1000 एकड़ का है और अभी उसमें अढाई फुट और खुदाई की जा सकती है। स्पीकर सर, इसकी यहां पर प्लान आई हुई है। वह खुदाई जब पूरी हो जायेगी तो मुझे विश्वास है कि सिरसा और फतेहाबाद जिले जिनकी भूमि राजस्थान के साथ लगती है वहां पर उस ओटू वियर नहर से जो पानी झील के अंदर इक्ट्ठा होगा वह पूरे साल किसानों की फसलों की सिंचाई के लिए उपयोग होगा। स्पीकर सर, इससे किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हुआ है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात का आश्वासन चाहूंगा कि वे ओटू वियर में पानी स्टोर करने की कैपेसिटी को बढ़ाने हेतु शीघ्रता से कदम उठाने के आदेश सम्बंधित विभाग को दें। स्पीकर सर, इसी प्रकार से रेलवे पुलों की बात है। सिरसा शहर के लिए एक रेलवे ओवर ब्रिज निहायत आवश्यक था क्योंकि पंजाब और राजस्थान से आने-जाने वाले ट्रैफिक के हिसाब से सिरसा शहर सैंटर में पड़ता है जिस कारण बहुत भारी समस्या थी। इस रेलवे पुल की डिमाण्ड भी बहुत पुरानी थी। इस पुल का कई बार नींव पत्थर भी रखा गया। इस बारे में दूसरे प्रकार की भी बहुत सी बातें की गई लेकिन वास्तव में इस दिशा में कोई भी काम नहीं हुआ, सिवाये ब्यानबाज़ी के। चुनाव आते थे तो जो इस समय विपक्ष में हमारे साथी बैठे हैं वे लोगों को राज़ी करने के लिए एक पत्थर लगा देते थे और उसके बाद कहते थे कि रेलवे पुल बन जायेगा। स्पीकर सर, इसके विपरीत माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां के लोगों को इस रेलवे पुल के निर्माण का भरोसा दिलाने के लिए वहां पर भूमि पूजन किया और उसके बाद इस पुल का निर्माण कार्य 01 जनवरी, 2009 से शुरू हो गया। स्पीकर सर, आज मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस रेलवे ब्रिज का काम 65 प्रतिशत पूरा हो चुका है इसलिए यह कहना गलत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी क्षेत्र विशेष से भेदभाव करते हैं। स्पीकर सर, अभी एक माननीय सदस्य श्री अजय सिंह चौटाला जी ने एक बात कही थी कि कांग्रेस सरकार के पिछले साढ़े चार साल के शासन काल के दौरान कुछ इण्डस्ट्रीज़ हरियाणा प्रांत से पलायन कर गई थी। स्पीकर सर, यह तो मैं नहीं जानता कि कितनी इण्डस्ट्रीज़ पलायन कर गई या उनके इस आरोप में कितनी सच्चाई है लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि हमारे इलाके में कुछ ऐसी इण्डस्ट्रीज लगी थी जो लगने से पहले ही बंद हो गई। अब अगर इस प्रकार से कुछ इण्डस्ट्रीज पलायन कर जावेंगी तो इसमें सरकार का क्या कसूर हो सकता है। स्पीकर सर, हमने अपने यहां पर एक जूट के कारखाने का पत्थर भी देखा था लेकिन वहां पर निर्माण के नाम पर कोई एक ईंट भी नहीं लगाई गई। अध्यक्ष महोदय, अब एक बात मैं बिजली के बारे में भी कहना चाहूंगा। बिजली के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि 2800 मेगावाट का परमाणु बिजली घर जोकि गोरखपुर गांव में बनेगा वह मेरी ही कांस्टीच्युएंसी में है। उस कारखाने का काम बड़ी ही तेजी के साथ शुरू

[श्री प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा]

17.00 बजे हो गया है और प्राइमरी स्टेज पर उसकी सारी की सारी कार्यवाही पूरी कर ली गई है मुझे विश्वास है कि जब वह 2800 मैगावाट का प्लांट चालू हो जायेगा तो हरियाणा बिजली के मामले में न केवल आत्मनिर्भर हो जायेगा बल्कि मुझे विश्वास है कि हरियाणा दूसरे प्रदेशों को भी बिजली देने योग्य हो जायेगा। यह मुख्य मंत्री जी का प्रयास है। यह पहली सरकार है जिसने जिस कारखाने का काम शुरू किया वह पूरा करके छोड़ा। आज बिजली के जितने भी संयंत्र हैं उन पर उम्मीद से ज्यादा तेज गति से काम चल रहा है तथा ऐसी संभावना है कि वे समय से पहले ही बिजली का उत्पादन शुरू कर देंगे जिससे हरियाणा प्रान्त की बिजली की समस्या का हल होगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा दूसरी सभी मदों के लिए भी बजट में पैसा बढ़ाया गया है। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि बजट भाषण में सभी बातें लिखी हुई हैं। मैं एक-दो बातें अपने हल्के के बारे में जरूर कहना चाहूँगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि हमारा फतेहाबाद जिला शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है और फतेहाबाद में भूना के 25 किलोमीटर एरिया तक कोई कॉलेज नहीं है, इसलिए मेरी विनती है कि वहाँ पर एक कॉलेज का निर्माण किया जाये ताकि वहाँ के ग्रामीण इलाके के बच्चे शिक्षित हो सकें। वहाँ पर लड़कियों को भी बहुत परेशानी होती है। दूसरी बात भट्टूकलां में अगर आई.टी.आई. की स्थापना की जाये तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर वहाँ पर एक आई.टी.आई. खोल दी जाये तो हमारे ग्रामीण बच्चे जो आज पढ़-लिख कर बेरोजगार हो जाते हैं वे अपनी आजीविका कमा सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से फतेहाबाद का बाईपास, एक अतिरिक्त मण्डी आदि के बारे में मैं लिख कर बता दूँगा। अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूँ और माननीय मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा बजट उन्होंने हरियाणा प्रदेश के लिए में पेश किया है। विपक्ष चाहे कुछ भी कहे लेकिन मुख्य मंत्री जी के बारे में मैं दो लाईनें अवश्य कहना चाहूँगा :—

सितारों के आगे जहां और भी है, मंजिले इश्क में इम्तिहां और भी है,

तू स्याई है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है।

जयहिन्द।

बैठक का स्थगन

Mr. Speaker : Hon'ble Finance Minister, will give reply.(Noise & interruptions)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हमारे तो 3 आदमी ही बोले हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, आप डिमांडज पर बोल लेना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में 90 सदस्य हैं और 90 सदस्यों में से 12 मैम्बर्ज कांग्रेस पार्टी के बोले हैं और 5 सदस्य ही विपक्ष के बोले हैं। सरकार के पक्ष में 53 हैं और विपक्ष में 36 हैं जिनमें से एक यहां पर है ही नहीं लेकिन फिर भी आपके 36 के हिसाब से विपक्ष को ज्यादा से ज्यादा डेढ़ गुणा टाईम देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, whether you have allowed him to speak on point of order ? (Interruptions)

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने उनको 6 घंटे का समय दिया है और हमारे को 1 घंटा 40 मिनट का समय दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, क्या ये आपकी इजाजत लेकर खड़े हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Chautala Ji, please sit down. ठीक है, आप आगे डिमांड्ज पर बोल लेना। (शोर एवं व्यवधान) हाँ जी, वित्त मंत्री जी अपना जवाब शुरू कीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी का जवाब ऐसे कैसे शुरू हो जायेगा।

Mr. Speaker : This is not the way. (Noise & interruptions)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, (विघ्न). . . . .

श्री अध्यक्ष : माजारा जी, आपकी 9 कट मोशंज हैं आप उन पर बोल लेना। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I will not allow anybody to speak. (Interruptions)

(इस समय इण्डियन नैशनल लोक दल के सदन में उपस्थित सभी सदस्य तथा शिरोमणि अकाली दल के स. चरणजीत सिंह सदन की वैल में आकर अध्यक्ष महोदय से बजट पर बोलने के लिए समय की मांग करने लग गए।)

यहां पर बजट एक घंटे में और दो घंटे में पास हुआ हुआ है। (शोर एवं व्यवधान) मैंने पहले ही बजट पर डिस्कशन के लिए तीन दिन का समय दिया है। (शोर एवं व्यवधान) अब और समय नहीं दिया जाएगा। (शोर एवं व्यवधान) I am not going to grant any time. आप सभी डिमांड्ज पर बोल लेना। (शोर एवं व्यवधान) मैं आपको डिमाण्ड्ज पर बोलने के लिए टाईम दूंगा आप उस पर बोल लेना। (शोर एवं व्यवधान) मैंने आपको कहा है कि बजट पर वित्तमंत्री जी के जवाब के बाद डिमान्ड्ज आनी हैं और उस पर आपने कट मोशंज दिए हुए हैं आप उस पर बोल लेना। (शोर एवं व्यवधान) I would not allow this. (interruptions) I am not going to give even one minute to anybody. यह वही हाऊस है जिसमें बजट एक घंटे में भी पास हुआ है। (शोर एवं व्यावधान) यह वही हाऊस है जिसमें बजट एक दिन में ही पास हुआ है और यह वही हाऊस है जिसमें तीन दिन से बजट पर डिस्कशन हो रही है। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी डिमान्ड्ज पर बोल लेना। (शोर एवं व्यवधान) मैं आपको यही कह रहा हूं कि बजट पर जवाब के बाद ग्रान्ट्स होंगी आप उस पर बोल लेना। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी अपनी सीटों पर जाएं। (शोर एवं व्यवधान) हर बात की हद होती है। Don't cross the border. मैंने आपको बजट पर डिस्कशन के लिए पहले ही तीन दिन दे दिए हैं। यहां पर 1 घंटे में भी बजट पास हुआ है, दो घंटे में भी बजट पास हुआ है। (शोर एवं व्यवधान) ठीक है आप ऐसे ही खड़े रहो। (शोर एवं व्यवधान) I am not going

[श्री अध्यक्ष]
to give even a single minute. आपकी मर्जी है। आपने कट मोशंज दी हुई हैं। आप उस पर बोल लेना। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी मेरी बात सुनो। पहले आप अपनी अपनी सीटों पर जाएं। (शोर एवं व्यवधान) आपने जो भी बात कहनी है वह आप अपनी सीटों पर जाकर कहें। आपने 11 मिनट्स तक शोर मचा लिया है अब आप अपनी सीट पर जाएं। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी अपनी सीटों पर जाएं। I am not governed by you. This is not the way. I have decided it. (शोर एवं व्यवधान) आप सभी अपनी सीटों पर जाएं। रामपाल माजरा जी, अब सभी मैम्बर्ज अपनी सीटों पर चले गए हैं इसलिए आप भी अपनी सीट पर जाएं।(शोर एवं व्यवधान) कप्तान साहब, अब आप बोलें।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि अगर हम अपनी सीटों पर चले जाएंगे तो आप हमें बोलने का मौका देंगे।

Mr. Speaker : I am not going to do, so.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या आपके कहने से ही डिसाइड हो जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रजातंत्र है। आप मेरे से बात न कहलवाएं। आप चाहते हैं कि मैं कुछ बोलूं लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगा। (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी जगह पर चले जाएं।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आप सारे मैम्बर्ज को बोलने का समय दे दें। आप हाऊस के कस्टोडियन हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुने।

श्री अध्यक्ष : यह आपका कोई सही तरीका नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) Please go to your seats. No, I will not give the time. (शोर एवं व्यवधान)

(अध्यक्ष महोदय के बार बार अनुरोध के बावजूद सदस्य वैल में खड़े रहे और लगातार बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष : यदि आप अपनी अपनी सीटों पर नहीं जाते हैं तो मैं 15 मिनट के लिए हाऊस को ऐडजर्न करता हूं। The House is adjourned for 15 minutes.

*17.16 hrs. (The Sabha then *adjourned for 15 minutes and reassembled at 5.31 P.M.)

Mr. Speaker : I will request 3-4 Members from the Opposition Parties including INLD and BJP to come to my Chamber to discuss the matter and find out some wayout for 10 minutes more, the House is again adjourned.

17.31 hrs. (The Sabha then adjourned for 10 minutes and reassembled at 5.41 P.M.)

वर्ष 2010-2011 के लिए बजट पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : अपोजीशन के साथ मेरी डिटेल बात हुई है। पहले जितने भी बजट पेश हुए हैं उनके बारे में भी मैंने उनको बताया है। एक दिन में भी बजट पास हुआ है, दो दिन में भी बजट

पास हुआ है। हमारे इस बजट को चौथा दिन है लेकिन फिर भी इन्होंने यह बात कही कि दो लोकदल के मैम्बर्ज और एक बी.जे.पी. के मैम्बर को बोलने दो और हम 5-5 मिनट बोलेंगें। This has been decided in the meeting.

श्रीमती कविता जैन (सोनीपत) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। वित्त मंत्री महोदय ने वर्ष 2010-2011 का जो बजट पेश किया है वह एक झलक देखने से विकासात्मक दिखाई देता है लेकिन अगर उसका बारीकी से विश्लेषण किया जाए तो यह बजट आर्थिक मंदी के दौर में नीरस और किसी वर्ग को राहत न देने वाला बजट है। इनडायरेक्ट रूप से हर वर्ग पर और भी बोझ लादने वाला यह बजट है। अध्यक्ष महोदय, बजट में कहा गया है कि स्टैम्प ड्यूटी में प्राप्ति की कमी आर्थिक मंदी का कारण है। हकीकत यह है कि स्टाम्प ड्यूटी में जो प्राप्ति की कमी का कारण है वह यह है कि सरकार के द्वारा नगरपालिका को एन.ओ.सी. रिसीव करने का एक मौखिक आदेश दिया गया है। जिसके तहत मकानों और दुकानों की रजिस्ट्री के लिए 120 रुपये प्रति गज के हिसाब से रेट फिक्स किए हुए हैं जिसकी वजह से कोरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अगर 50 रुपये से 75 रुपये रिश्वत दे दी जाए तो रजिस्ट्री हो जाती है इसलिए मेरा सुझाव है कि अगर इस एन.ओ.सी. की शर्त को समाप्त कर दिया जाए तो रवैन्यू में भारी मात्रा में वृद्धि हो सकती है। बजट में सैटेलाइट सिटी बनाने के लिए और उसका इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवैल्प करने के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। मैं इसका खुले दिल से स्वागत करती हूं। इस योजना के तहत सरकार द्वारा बहुत खर्चा किया जा रहा है। जिस तरह गुड़गांव के अंदर जो पुराना शहर है वह बिना डिवैल्प किए हुए रह गया था उसको इस योजना में लिया गया है इसी तरह सोनीपत शहर का जो पुराना हिस्सा है उसके किसी भी भाग को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है इसलिए मेरा सुझाव यह है कि उस पुराने सोनीपत शहर को भी इस योजना में शामिल किया जाए। बजट के अंदर मैट्रो रेल लिंक योजना का जिक्र है जिसके तहत जिन डिस्ट्रिक्ट के पार्ट एन.सी.आर. क्षेत्र के साथ लगते हैं उनको मैट्रो रेल लिंक से जोड़ने का जिक्र है लेकिन आज दैनिक जागरण के अंदर एक न्यूज आई है जिसमें कहा गया है कि डी.एम.आर.सी. से बात-चीत की गई है जिसमें हरियाणा के बहादुरगढ़ और कुण्डली सहित अन्य किसी इलाके में मैट्रो चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही किसी स्तर पर कोई योजना बनी है। इस बारे में मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि दिल्ली जहांगीर पुरी से कुण्डली तक मैट्रो लाने के लिए प्रस्ताव बजट में शामिल किया जाये क्योंकि 30-40 हजार लोग डेली सोनीपत से दिल्ली जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि सोनीपत शहर के अंदर हिंदू कालेज के पास रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज की बहुत सख्त जरूरत है और वहां के लोगों की यह 40 साल पुरानी मांग है। इस रेलवे लाईन की वजह से सोनीपत शहर दो हिस्सों में बंटा हुआ है। वहां पर भीड़ अधिक होने के कारण एक्सीडैंट्स भी बहुत होते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने शुक्रवार को सैशन के दौरान कहा था कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा स्टैंड करती है। मुख्यमंत्री जी ने वहां पर ओवर ब्रिज बनाने के लिए अगस्त, 2009 में घोषणा भी की थी कि प्रस्ताव पास होने के बाद इस ओवर ब्रिज के लिए जल्दी ही आधारशिला रखी जायेगी लेकिन इसको बनाने के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया है। इसलिए मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि यह ओवर ब्रिज जल्दी से जल्दी बनवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त ट्रैफिक जाम की भी सोनीपत शहर में बड़ी समस्या है। वहां पर शहर में गुजरते वक्त एक कि.मी. के सफर में 40 से 45 मिनट का समय लग जाता है। इसमें ज्यादातर व्हीकल्ज जींद, गोहाना और

[श्रीमती कविता जैन]

दिल्ली जाने वाले होते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगी कि खरखौदा जैसे कस्बे के अंदर बाईपास बन सकता है तो सोनीपत शहर में बाईपास बनाने का निर्णय क्यों नहीं लिया गया जो कि जिला हैड क्वार्टर है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगी कि बजट में सोनीपत शहर में भी बाईपास बनाने के लिए प्रोवीजन किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चीफ मिनिस्टर से एक बात कहना चाहूंगी कि मैं रोहतक की बेटी हूं। इस वजह से मुझ पर मेरे हल्के की जनता कटाक्ष करती है कि मैं अपने मायके से अपनी ससुराल के लिए बाई पास का निर्माण करवाऊं ताकि सोनीपत के शहर के लोगों की ट्रैफिक जाम की समस्या दूर हो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरफ विशेष ध्यान दें (इस समय मेजें थप-थपाई गई)। अध्यक्ष महोदय, बजट के अंदर बिजली, पानी, स्वास्थ्य आदि के लिए लम्बी-लम्बी बातें की गई हैं लेकिन सोनीपत के अंदर बिजली और दूसरी सुविधाओं की बहुत खस्ता हालत है। बिजली के बिलों पर सैंडरी चार्जिज और एफ.एस.ए. वसूल किए जाते हैं लेकिन बिजली की हालत बहुत खराब है। इसके अतिरिक्त बिजली के खम्भे और तारें भी सोनीपत शहर में बाबा आदम के जमाने की लगी हुई हैं। कई कालोनीज तो ऐसी हैं जहां पर खम्भे-खम्बे लगे हुए हैं तारें हैं ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : कविता जी, प्लीज आप वाईड-अप करें।

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट का समय और दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा की बात है शिक्षा के लिए भी बजट में बड़ी-बड़ी बातें की गई हैं। मेरे हल्के में बहुत से प्राईमरी स्कूल अब भी मंदिरों और चौपालों में चल रहे हैं तथा उन चौपालों की हालत भी बड़ी जर्जर है इसलिए उनका भी सुधार किया जाये। इसके अतिरिक्त जो लोग झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं उनके जीवन स्तर में भी सुधार करने के लिए बिजली और पानी की व्यवस्था की जाये। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त चुनाव होने से पहले सरकार ने क्लोजिंग स्टॉक्स पर वैट घटाने की बात कही थी और फार्म 38 भी हटाने की घोषणा सरकार ने की थी लेकिन वैट कम करने की बजाय बढ़ा दिया गया और बजट में सरचार्ज भी लगा दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : मैडम, प्लीज अब आप बैठें। आपका समय पूरा हो चुका है। अब प्रदीप चौधरी जी बोलेंगे।

श्री प्रदीप चौधरी (कालका) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सदन में बड़े ताम-झाम से बजट पेश किया गया लेकिन इसको केवल खोखला ढोल पीटने वाला बजट ही कहा जा सकता है। माननीय कविता जी के बोलने से पहले एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस सरकार में क्षेत्रवाद की बात नहीं की जाती है लेकिन हमारे क्षेत्र से निरंतर भेदभाव किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमें गर्व है आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी पर कि उनकी सरकार के समय में हमारे यहां से कांग्रेस का विधायक होने के बावजूद भी उन्होंने बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य करवाये। उस समय हमारे क्षेत्र के साथ नौकरियों में भेदभाव नहीं किया गया और अनेकों पुलों का काम भी करवाया गया। इसके अतिरिक्त पानी के ट्यूबवैल लगवाये गए और सड़कें भी बनवाई गई लेकिन आज बिजली की बात करूं तो बिजली के लिए भी हमारे क्षेत्र के लोग निरंतर तरस रहे हैं। जब अधिकारियों से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि रायपुररानी क्षेत्र के टपरियां और दून क्षेत्र के नानकपुर गांवों में सब-स्टेशन लगा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे किसान बहुत छोट-छोटे हैं और

प्रकृति पर निर्भर करते हैं लेकिन उनको नील गाय आदि जंगली जानवरों से भी अपनी फसल को बचाने का भय बना रहता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां बहुत से ऐसे किसान भी हैं जिनकी अपनी मिलकियत वाली जमीनें हैं जिन पर खैर और चीड़ के पेड़ खड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, ये पेड़ ही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन हैं इसलिए जब उन्हें शादी-विवाह के अवसर पर या फिर मकान वगैरह बनाने के लिए इन पेड़ों को काटने की आवश्यकता होती है तो उन्हें इसके लिए सरकार की ओर से कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है कि वे अपने खर्च चलाने के लिए इन पेड़ों को काट सकें। क्या मुख्यमंत्री जी उनको इसका अधिकार देने के बारे कोई प्रावधान करेंगे। स्पीकर सर, जल ही जीवन है इसलिए अगर पीने के पानी की बात की जाये तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां के निवासियों को मजबूर होकर ऐसी जगहों से पानी पीना पड़ता है जहां से जंगली जानवर पानी पीते हैं। स्पीकर सर, हमारे यहां पर पीने के पानी के ट्यूबवैलों की बहुत ज्यादा कमी है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि एक जांच कमेटी बना दी जाये जिसको मैं यह दिखा सके कि कुछ गांवों के लोग 3-3 और 4-4 किलोमीटर दूर से बरसात और बावड़ियों का पानी लाकर पीने को मजबूर हैं। स्पीकर सर, इसी प्रकार से अगर स्वास्थ्य का जिक्र किया जाये तो मेरे कालका विधान सभा क्षेत्र के रायपुररानी ब्लॉक और पंचकुला विधान सभा क्षेत्र के बरवाला ब्लॉक के लोगों को साल के तकरीबन 7-8 महीने मक्खियों के प्रकोप का शिकार होकर नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। चाहे शादी-विवाह की बात हो अथवा खाने-पीने की बात हो हरेक अवसर पर मक्खियों की भरमार रहती है। हमारे यहां शादी-विवाह के समय खाना खाने के समय लोगों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके साथ-साथ घरों में मक्खियों की वजह से पशुओं को भी परेशानी होती है। स्पीकर सर, अगर मैं सरकारी हॉस्पिटल्ज़ की बात करूं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में मोरनी जोकि एक पहाड़ी क्षेत्र है वहां के सरकारी हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी है। स्पीकर सर, इसके अलावा अगर मैं कालका नगरपालिका की बात करूं तो सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि कालका नगरपालिका में पिछले दो साल से स्ट्रीट लाईटें बंद पड़ी हैं। इसके बावजूद भी लोगों को बिजली के बिलों का भुगतान करना पड़ रहा है। जहां तक सीवरेज का सवाल है। वहां पर सीवरेज की व्यवस्था भी पूरी तरह से ठप्प पड़ी है क्योंकि वहां पर सैनिट्री स्टाफ की कोई व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से अगर शिक्षा की बात की जाये तो हमारे क्षेत्र में पिंजौर और मोरनी ब्लॉक ऐसे ब्लॉक हैं जहां 3-3 और 4-4 किलोमीटर तक प्राईमरी स्कूल के बच्चों को जंगलों के रास्ते से नदियां पार करके प्राईमरी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता है। स्पीकर सर, इसी प्रकार से हमारे यहां जे.बी.टी. का संस्थान पिंजौर में कालका एट बिटना है। इस संस्थान को खुले हुए दो साल हो गये हैं लेकिन आज भी वहां पर प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं हुई थी। मेरे द्वारा विधान सभा में प्रश्न लगाने के बाद 08 मार्च, 2010 को वहां प्रधानाचार्य की नियुक्ति की गई है लेकिन निदेशकों के पद वहां पर अभी भी खाली पड़े हैं। स्पीकर सर, अगर सरकार सड़क तंत्र को सुदृढ करने के लिए वचनबद्ध है तो हमें इस बात का फख्र है कि आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने शासन काल के समय में कालका विधान सभा क्षेत्र के लिए कुछ सड़कें मंजूर की थी जिनमें से एक मांदरना से बड़ीशेर रोड़ है जोकि एक कच्चा रास्ता है उस पर एक पुल को भी सैंक्शन किया गया था लेकिन उस कच्ची सड़क के साथ-साथ वह पुल भी उस कच्ची सड़क पर नहीं बना है। इसी प्रकार से एक सड़क दमदमा से भवाना मंजूर की गई थी, एक भवाना से जैथल और एक टोरड़ी से धारड़ी भी मंजूर हो चुकी थी। स्पीकर सर, ये कच्ची सड़कें

[श्री प्रदीप चौधरी]

हमारी सरकार के समय में मंजूर की गई थी। मौजूदा सरकार के शासन काल में नई सड़कें बनाना तो दूर की बात जो पुरानी कच्ची सड़कें थी उनको भी पक्का नहीं किया जा सका है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से अगर हमारे क्षेत्र में उद्योगों की बात की जाये तो कांग्रेस सरकार ने हमारे साथ हमेशा ही बदनीयती की है। हमारे यहां भूपेन्द्र सीमेंट वर्क का ए.सी.सी. सीमेंट का कारखाना होता था जो कि अब बंद हो गया है। इसके अलावा आज एच.एम.टी. भी बंद होने के कगार पर है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमारे क्षेत्र में आज भी बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जैसे ढकरोई और बकारनी गांव जो कि पिंजौर ब्लॉक में पड़ते हैं, इन गांवों के बच्चों को बसों में ठुंस-ठुंस कर स्कूल जाना पड़ता है। स्पीकर सर, इस प्रकार के और भी बहुत से गांव हैं जहां पर आज भी रोड़वेज़ की बसें नहीं जाती और बस-स्टैण्डों पर भी बसें नहीं आती जिसके कारण स्कूल में जाने वाले बच्चों और दूसरी सवारियों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। स्पीकर सर, मुझे आशा है कि अपने विधान सभा क्षेत्र की जो मांगे मैंने आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाई हैं उन पर सरकार के लैवल पर विचार करके शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जायेगी। स्पीकर सर, इसके साथ ही आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

डॉ. बिशन लाल सैनी (रादौर) : स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने का जो समय दिया है इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। स्पीकर सर, जो वित्त मंत्री महोदय ने सदन में अपना बजट पढ़कर सुनाया है उसके बारे में सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि वित्तमंत्री महोदय को पता नहीं यमुनानगर जिले से क्या कोई ईर्ष्या है जो उन्होंने किसी भी प्रोजैक्ट के लिए और दूसरे विकास कार्य के लिए यमुनानगर का पूरी किताब में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। स्पीकर सर, इसके अलावा कुछेक बातें तो ऐसी हैं जिनका जिक्र करना वित्तमंत्री बिलकुल ही भूल गये। स्पीकर सर, हमारे जिले यमुनानगर में से यमुना नदी निकलती है और यमुना नदी में पिछले पांच सालों में दो बार भयंकर बाढ़ आ चुकी है। सितम्बर, 2008 के अंदर जब किसानों की फसलें पूरी तरह से तैयार खड़ी थी तब हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा बारिश हो गई जिसकी वजह से रात में यमुना नदी में बहुत भयंकर बाढ़ आ गई। बाढ़ के पानी की वजह से हमारे उधर के जठलाना, गुमथला, उनहेड़ी, मॉडल टाऊन, करेहड़ा, बागवाली तथा लाल छप्पर आदि गाँवों की सारी की सारी फसलें बर्बाद हो गई, पानी में डूब गई। अगले दिन जब हमें पता चला तो हम भी किसानों की फसलें देखने के लिए और किसानों को सांत्वना देने के लिए वहाँ पर गये। वहाँ पर कुछ हमारे पार्टी के नेता भी थे। हमारे जाने से पहले ही वहाँ पर कांग्रेस के भी एक नेता जो अबकी बार बदकिस्मती से नहीं आ पाये, वे भी वहाँ पर पहुंचे हुए थे। उपायुक्त महोदय भी वहाँ पर पहुंचे हुए थे। वे सब लोग किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। हमने सोचा कि शायद मुख्य मंत्री जी को पता चल गया होगा और वे यहाँ पर आ रहे होंगे। थोड़ी देर बाद हमें आसमान में एक हैलीकॉप्टर दिखाई दिया तथा उसने आ कर तीन-चार चक्कर लगा कर पूरे गाँव का और पानी का जायजा लिया। उसके बाद हैलीकॉप्टर वहाँ उतार दिया जिसमें से हमारे माननीय एम.पी. साहब उतरे। उन्होंने सबको बुलाया और बातचीत की। उपायुक्त महोदय ने ऐलान कर दिया कि मेरी माननीय मुख्य मंत्री महोदय से बात हो गई है। वे बहुत ही दरियादिल हैं, वे किसानों के हितैषी हैं और वे कह रहे हैं कि किसानों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी हम स्पैशल गिरदावरी करवायेंगे और किसानों को राहत दी जायेगी। उनको उनके नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जायेगा। उसके बाद पटवारी लोग आये और पटवारियों ने स्पीकर सर, किसानों से नीचे ही नीचे रेट तय कर लिए कि अगर पूरे किले

की खराबी लिखवानी है तो इतना पैसा लगेगा, एक एकड़ का नुकसान लिखवाना है तो इतना पैसा लगेगा और अगर दो एकड़ का नुकसान लिखवाना है तो इतना पैसा लगेगा। किसानों ने भी अपने हिसाब से पैसे दे देकर खूब स्पैशल गिरदावरी करवाई और उसके बाद एक साल तक लोग इंतजार करते रहे लेकिन उन लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला। अगले साल सितम्बर, 2009 में जब पूरे प्रदेश में अकाल पड़ा हुआ था और हिमाचल में बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से यमुना नदी में बाढ़ आ गई। अध्यक्ष महोदय, इस बार तो पिछली बार से भी ज्यादा बाढ़ आई। हम किसानों से मिलने के लिए वहाँ पर फिर पहुंचे लेकिन अबकी बार वहाँ पर कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं था। (विघ्न) वहाँ पर दूसरी पार्टियों के लोग तो थे लेकिन कांग्रेस का कोई नेता नहीं था। वहाँ पर हमने देखा कि गाँव वालों के हाथों में डंडे थे। हमने उनसे पूछा कि आप लोगों ने डंडे किसलिए लिए हुए हैं तो उन्होंने कहा कि अगर कोई कांग्रेस का एम.पी. या एम.एल.ए. आ गया तो उसकी गाड़ी को तोड़ेंगे और अगर कोई हैलिकॉप्टर से आयेगा तो हम उसका हैलिकॉप्टर भी तोड़ डालेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है इस बजट में बाढ़ की रोकथाम के लिए पैसे की कोई व्यवस्था नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, यह जो बार-बार बाढ़ आ जाती है उसका कारण मैं बताना चाहूँगा। यमुना नदी के साथ यू.पी. की जमीनें लगती हैं। हमारी सरकार से अच्छी तो यू.पी. की मायावती सरकार निकली। (विघ्न) यू.पी. गवर्नमैंट ने यमुना नदी के साथ-साथ पटड़ी बाँधने का काम कर दिया है जिसको स्टड्स कहते हैं। वे स्टडस उन्होंने करनाल तक लगा दिये हैं जिसकी वजह से पानी का रूख हरियाणा की तरफ हो गया यानि जब भी बाढ़ आयेगी वह यू.पी. की तरफ कम नुकसान करेगी और हमारे हरियाणा प्रदेश में ज्यादा नुकसान करेगी।

श्री अध्यक्ष : सैनी साहब, आपको बोलने के लिए 5 मिनट का समय दिया गया था और आप 7 मिनट का समय ले गये। (विघ्न) आप मायावती के पास पहुंच गये लेकिन अपने हल्के की बात नहीं बता सके। अब आपका समय समाप्त हुआ। धन्यवाद।

डॉ. बिशन लाल सैनी : स्पीकर सर, वर्षा के समय में किसानों की जमीन दरिया को सुपुर्द हो जाती है। अगर किसी किसान की जमीन 4 एकड़ है और वह दरिया में चली गई तो वह तो बर्बाद हो जाता है उसकी कमाई का कोई साधन नहीं रहता है। सर, सरकार जब उस जमीन का रेत के लिए ठेका देती है तो उसमें उसको काफी मुनाफा होता है लेकिन किसान को कुछ नहीं मिलता। अगर किसान को वहां से एक ट्राली रेता की जरूरत होती है तो वह भी उसको नहीं मिलती है। वहां पर ठेकेदार के आदमी लाठियां लिए बैठे रहते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वहां पर जब रेत का ठेका दिया जाता है तो वहां पर उस किसान को भी हिस्सा मिलना चाहिए जिसकी जमीन दरियाए सुपुर्द हो जाती है। उसमें उस किसान को भी फायदा मिलना चाहिए। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए।

18.00 बजे

Mr. Speaker : Thank you very much. Now the Finance Minister will give the reply.

वित्तमंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : स्पीकर सर, मैं सभी माननीय सदस्यों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने बजट पर खुल कर अपने विचार रखे। उन सभी ने बोलते हुए अपने अपने बहुमूल्य विचार प्रकट किए हैं। मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि "मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया।" मैं सभी साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिसमें विपक्ष के साथी श्री ओम प्रकाश चौटाला, श्री अशोक कुमार अरोड़ा, श्री राम पाल

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

माजरा, श्री अनिल विज आदि ने बजट पर बोलते हुए अपना विरोधी रूप भी दिखाया और अपनी भावनाएं भी व्यक्त की। उन्होंने बजट में छिपी विकास की बात को नहीं समझा। स्पीकर सर, मैं कहना चाहूंगा कि "ऐसी वैसी कहने से अच्छा है, खामोश रहो। वर्ना ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो।" श्री ओम प्रकाश चौटाला जी जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री और बहुत ही सीनियर लीडर हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे आलोचना करते, लेकिन मुझे तो लगता है कि इन्होंने बजट की किताब पढ़ी ही नहीं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, बजट पर बोलते हुए सत्ता पक्ष के भाईयों और बहनों ने भी अपने विचार रखे। इसमें भाई रधुवीर सिंह कादियान जी हैं, हमारी साथी सुमिता सिंह जी, शारदा राठौर जी हैं, श्रीमती किरण चौधरी जी हैं, सम्मानित सदस्य सम्पत सिंह जी हैं और दूसरे साथी भी हैं जिन्होंने बजट के बारे में अपने विचार रखे। इन्होंने अपने हल्कों की समस्याओं के बारे में भी बातें की। अध्यक्ष महोदय, मुझे खासतौर पर उस समय बहुत निराशा हुई जब विपक्ष के साथी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपनी बात कही। जब वे बोल रहे थे तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे ऐसा भाषण दे रहे हैं जो जमीन से सम्बन्धित हो। जैसे किसी प्रापर्टी डीलर का भाषण हो। मुझे ऐसा लगा कि उनके हाथ से कोई जमीन निकल गई हो। (शोर एवं व्यवधान) मेरे कहने का मतलब है कि आज लैवल ऑफ डिबेट गिर गई है। मैं लगातार 21 साल से विधान सभा में जीत कर आ रहा हूं और लगातार छठी बार जीत कर आया हूं। मुझे दुःख है कि आज किस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। यह ठीक है कि मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं और न ही अर्थशास्त्र का छात्र रहा हूं लेकिन मुझे इस बात के लिए फख्र है कि मैंने विश्व की बेहतरीन सेना में अधिकारी का काम किया है। सर, मैं इनको कहना चाहता हूं कि :—

"आलोचना जनाब करें आप शौक से,
लेकिन किताब आपने शायद पढ़ी नहीं।"

उसके बाद अपने पिता स्वर्गीय राव अभय सिंह के कहने पर मैं राजनीति में आया। सरकारें आयी और गयीं लेकिन मुझे इस बात का फख्र है कि मुझे रेवाड़ी की जनता ने लगातार 6 दफा जिताकर विधान सभा में भेजा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने आम व्यक्ति के बारे में सोचने की कोशिश की है। यू.पी.ए. की चेयरपर्सन माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे वित्त विभाग सौंपा है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि भले ही मैं अर्थशास्त्र का छात्र नहीं रहा हूं लेकिन मेरी पूर्ण कोशिश होगी कि मैं अपने मंत्री साथियों के साथ मिलकर हरियाणा को विकास के पथ पर आगे ले जाऊं। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय विपक्ष के नेता ने एक बात कही कि हमने नमक पर भी वैट लगा दिया है। यहां तक कि उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी नाम अपने असत्य भाषण में जोड़ दिया जोकि एक शर्मनाक बात है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जहां तक वैट पर सरचार्ज बढ़ाने का सवाल है हिमाचल में हमारे भाई अनिल विज की बी.जे.पी.की सरकार है उन्होंने भी वैट चार से पांच परसैंट तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा उन्होंने अपने यहां पर एंट्री टैक्स भी लगा दिया है। वहां पर इनकी ही पार्टी की सरकार है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हमें अपने स्टेट को देखना है। ये दूसरों को क्यों देखते हैं ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हमने जो सरचार्ज लगाया है, हमारी कोशिश है कि हम चवन्नी लेकर जनता को 50 रूपये देने का काम करेंगे। चाहे वह

नगरपालिका की वित्तीय हालत सुधारने का मामला हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन को बढ़ाने की बात हो, हम हर तरफ पूरा ध्यान देंगे। अध्यक्ष महोदय, इनके समय में बुढ़ापा पैंशन 200 रुपये थी जिसको ये 300 रुपये करके चले गए थे लेकिन हमारी सरकार ने आने के बाद ही उसके एरियर्ज दिए थे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने फिर रिपीट किया है कि इन्होंने वैट पर सरचार्ज लगाया है। इनको यह तो बताना चाहिए कि इन्होंने कितना सरचार्ज लगाया है ? ये यहां पर इस बारे में नहीं बताते बल्कि प्रैस में जाकर बताते हैं जो कि एक गलत परम्परा है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के नेता की पूरी तसल्ली करके एक एक बात बताऊंगा। मैं यह कहना चाह रहा था कि इनके समय में बुढ़ापा पैंशन 200 रुपये थी जिसको ये 300 रुपये करके चले गए थे। हमारी सरकार ने आने के बाद इनके समय के बुढ़ापा पैंशन के एरियर्ज दिए हैं। उसके बाद हमारी सरकार ने ही बुढ़ापा पेंशन 500 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये की है। इसके अलावा विधवा पेंशन भी हमारी सरकार दे रही है। 1300 करोड़ रुपये का इसकी वजह से आर्थिक बर्डन पड़ रहा है। इसी तरह से हमारी सरकार 314 करोड़ रुपयों के एस.सीज.और बी.सीज. के बच्चों को वजीफे भी दे रही है। ये हमें बता दें कि हम लोगों को ये वजीफे दें या नहीं, बुढ़ापा पेंशन दें या नही, नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति मजबूत करें या नहीं ? मैं बताना चाहूंगा कि इनके लिए हमने सरचार्ज लगाया है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने एक बात और कही कि हमने अपने घोषणा पत्र में यह कहा था कि हम वैट लागू नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं अपने घोषणा पत्र का अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूं। हमारे घोषणा पत्र में बाकायदा दिया हुआ था कि Congress party will also ensure that all taxes on raw material and finished products will be at par with other States, which will give relief to trading community. The Chautala government has cheated the trading community of Haryana by the manner it has implemented VAT. The Congress party will ensure that harassment and extortion of the trading community in the name of VAT will immediately be stopped. अध्यक्ष महोदय, हमारा कहने का तात्पर्य यह था कि हम कोई भी काम आइसोलेशन में नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने वैट चार से पांच परसैंट बढ़ाया है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2005 में जब हमारी सरकार आयी उस वक्त तकरीबन 45 आईटम्ज ऐसी थीं जिन पर वैट ओम प्रकाश चौटाला जी के समय 12.5 परसैंट था लेकिन हमने इसको घटाकर चार परसैंट किया। (थम्पिंग) वे क्या चीजें थी, मैडीसिन, ड्रग्स, कैरोसिन ऑयल, एडीबल ऑयलस, पेपर्ज, हारवैस्टर्स , ट्रैक्टर्स, ये कमोडिटीज किसान से आम व्यक्तियों से जुड़ी हुई थीं उनमें हमने वैट 12.5 परसैंट से घटाकर 4 परसैंट कर दिया और 21 कमोडिटीज ऐसी थीं जिनमें हमने फुल ऐग्जैम्पशन दी। ये अभी कह रहे थे कि महिलाओं के लिए इस बजट में कुछ नहीं किया गया। एल.पी.जी. जो घर में महिलाएं इस्तेमाल करती हैं, डौमैस्टिक यूज में जो एल.पी.जी.इस्तेमाल होती है, इसके अलावा गुड़, पेस्टीसाइड्स, वीडीसाइड्स, इंसैक्टिसाइड्स और किसानों को जो व्हीट की पेमेन्ट मिलती थी उस पर भी 12 परसैंट वैट होता था उसको 12 परसैंट से कम करके 8.8 परसैंट किया गया। कैमिकल फर्टिलाइजर्स में जिप्सम के ऊपर, ऐग्रीकल्चर इंप्लीमैंट्स जैसे डीजल आदि पर वैट 12 प्रतिशत से घटाकर 8.8 परसैंट किया है और उसकी वजह से हम आज के दिन 400 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रहे है। यह फैसला भी हमने किसान हित में किया है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : राइस पर आपने कितना बोनस दिया है, यह बताएं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। मैं इनको सब कुछ बताऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इस बजट में हमने अर्बन एरियाज पर विशेष ध्यान दिया है उसके लिए आउटले 1447.14 करोड़ रुपया रखा गया है जिसमें 26.50 परसैंट की वृद्धि है। विपक्ष के नेता ने यह कह दिया कि ये गवर्नमैंट माइनोरिटी में है। अध्यक्ष महोदय, हमारे 45 आदमी यहां पर हैं इसके अलावा 7 इंडिपैंडैंट हैं और एक बी.एस.पी. का हमारा साथी हमें सपोर्ट कर रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं या तो मुझे अर्थमैटिक नहीं आती या क्या बात है कि इनके 21-22 एम.एल.ए. की सरकार नैतिक थी या हमारी है। हमने 5 सदस्य अलग पार्टी बनाकर अपनी पार्टी में मर्ज किए हैं। हमने पहले विश्वास मत प्राप्त किया था, इन्होंने बाद में किया था। 40 हम हैं, 7 हमारे इंडिपैंडैंट हैं एक बी.एस.पी. का था तब हमने विश्वासमत लिया था और अब लगाएं तो 45+7+1 बी.एस.पी. तो किस प्रकार से माइनोरिटी की हमारी गवर्नमैंट हुई। जब 21-22 सदस्यों से इन्होंने सरकार बनाई थी तो उस समय क्या इन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई थी?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में ये बहुत अहम् बात कही है। चौटाला जी ने जो माइनोरिटी गवर्नमैंट की बात कही है वह तथ्य से बहुत दूर है। हमने चुनाव के बाद सबसे पहले विश्वास मत प्राप्त किया है सिर्फ मैंने ओथ ली थी। इन्होंने तो पहले कैबिनेट बनाई और बाद में हाउस का विश्वास मत प्राप्त करने आये थे। ये तो प्रजातंत्र है हाउस की मैजोरिटी मैजोरिटी रहेगी। अगर ये ऐसा कहते हैं तो आज आप वोट डलवा लें, हम आज भी तैयार हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र में मैजोरिटी वह मानी जाती है जो सिम्बल पर जीतकर आये।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, चश्मे की सिंबल पर कितने सदस्य जीतकर आए है। आप बताएं कि हमारे 40 ज्यादा हैं या इनके 31-32 ज्यादा हैं।(शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला जी ने यह आरोप लगाया कि नौकरियां नहीं दी गई। मैं बताना चाहता हूं कि इनकी सरकार के समय में इन्होंने हरियाणा हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के 141 कर्मचारियों को रिट्रैंच किया, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के 451, एम.आई.टी.सी. के 3845 कर्मचारी, एच.एस.आई.डी.सी. के 36, हरियाणा वीवर अपैक्स सोसायटी, पानीपत के 58, एच.एम.एल. के 838, कान्फेड के 683 कर्मचारियों की इन्होंने रिट्रैंचमैंट की। इसके अलावा नई नियुक्तियों पर इन्होंने प्रतिबन्ध लगा रखा था लेकिन हमारे समय में पिछले वर्ष 2005 से 2010 तक 60 हजार लोगों को नौकरियां दी गई। इसके अलावा इस दौरान कर्मचारियों की कोई छंटनी भी नहीं की गई जबकि अगर ये उसी प्रकार से सत्ता में बैठे होते तो न जाने कितने कर्मचारियों की छंटनी कर देते। लोगों ने तो इनकी छंटनी कर दी। ये कहते हैं कि सरचार्ज क्यों लगा दिया ? कर्मचारियों को जो एरियर्स दिया है उससे ही 4120 करोड़ रुपये का सरकार पर अतिरिक्त बर्डन पड़ा है जो पे कमीशन की रिपोर्ट लागू की है उससे करीब 2600 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। माननीय ओमप्रकाश चौटाला जी सरचार्ज लगाने की बात कर रहे हैं। ये अकाली दल के को-पार्टनर हैं जो

कहते हैं कि हम हरियाणा को एस.वाई.एल, नहर के पानी की एक बूंद भी नहीं देंगे। पंजाब में तो केवल वैट पर ही 4-5 प्रतिशत सरचार्ज नहीं लगा रहे हैं बल्कि कर्ज पर भी 10 प्रतिशत सरचार्ज लगा रहे हैं। इनके कोआर्डीनेट पार्टनर अकाली दल के एक विधायक भी इनके साथ यहां पर हैं। वे भी एस.वाई.एल का विरोध करते हैं।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : माननीय मुख्यमंत्री जी अगर जवाब देना चाहेंगे तो शायद इनको इस बात का भी ध्यान रहा होगा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने पानी के बारे में सारे फैसले रद्द कर दिए थे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. नहर के पानी से संबंधित सभी फैसले रद्द करने के बारे में ये बात करते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमने इस बात का डटकर विरोध किया था। चौटाला साहब ने कर्ज लेने की बात भी कही है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2005 तक जब चौटाला साहब की सरकार थी तब इन्होंने 26073 करोड़ रुपये के कर्ज लिये थे जबकि इनका प्लान-आउट-ले कभी तो 2200 करोड़ रुपये का होता था कभी 1800 करोड़ रुपये का होता था और कभी 1700 करोड़ रुपये का होता था। हमारा प्लान-आउट-ले 10500 करोड़ रुपये का है और इसने वर्ष 2005 से 2010 तक 19199 करोड़ रुपये का ही लोन लिया है। जो कर्जे इनके समय में लिए गये वे 93.6 प्रतिशत थे और हमारे समय में 63.6 प्रतिशत हैं।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से वित्त मंत्री जी गलत ब्यानी न करें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, ये इस प्रकार बीच में बोलने लग गये हैं जब कि वित्त मंत्री जी इनकी एक-एक बात का जवाब दे रहे हैं।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी गलत ब्यानी न करें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने इसी प्रकार से गलतब्यानी करके सदन में असत्य बोलकर अपना भाषण खत्म किया है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी को शायद ज्ञान नहीं है कि वे अनपार्लियामैंट्री शब्द बोल रहे हैं। इन्होंने लोन तो लिया है लेकिन एक नया पैसा भी अदा नहीं किया है। तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। 5-7 दिन पहले इण्डियन एक्सप्रैस अखबार में यह खबर थी कि सरकार कर्जा ले रही है।

श्री अध्यक्ष : आप इस तरह बीच में न बोलें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता सारी बातें गलत बयानी करके बोलते रहे और हम सुनते रहे लेकिन अब इनको अपनी बातों का जवाब तो सुनना चाहिए। वित्त मंत्री जी हकीकत कह रहे हैं। हमारी सरकार के समय में वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2010 तक एक बार भी हरियाणा सरकार ने ओवरड्राफ्ट नहीं किया जबकि चौटाला साहब की सरकार के समय में कितनी ही बार ओवरड्राफ्ट किया गया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आज भी सरकार 5000 करोड़ रुपये की कर्जदार है।

श्री अध्यक्ष : यह कोई कहने की बात नहीं है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : यह जो एक्सपैंडीचर इनके समय में 8308 करोड़ रुपये था वह हमारे समय में 17817 करोड़ रुपये है। अध्यक्ष महोदय, हमने जो कर्जा लिया है वह इन्फ्रास्ट्रक्चर पर लगाया है, हमने प्रदेश की बेहतरी के लिए लगाया है। इनके समय में टोटल एवरेज एनुवल प्लान साइज ग्रोथ 4.8 परसैंट रही जबकि हमारे समय में यह ग्रोथ रेट 37.83 परसैंट रही। इनका टोटल प्लान एण्ड नॉन प्लान एक्सपैंडीचर 71890 करोड़ रहा जबकि हमारे समय में यह एक्सपैंडीचर एक लाख 20 हजार 739 करोड़ रुपये था। अध्यक्ष महोदय, पावर के अंदर हमारी ग्रोथ 160.7 परसैंट, एजूकेशन में 111.9 परसैंट, इरीगेशन में 145.9 परसैंट, हैल्थ में 97.1 परसैंट, सोशल सैक्टर में 137.4 परसैंट, वाटर सप्लाई एण्ड सैनीटेशन में 168.9 परसैंट और पी.डब्लयू.डी. (बी. एण्ड आर.) में 216 परसैंट रही है। भाई अनिल विज और कृष्णपाल गुर्जर जी बी.जे.पी. के साथी है, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि ये हिमाचल सरकार को कहें कि एरियर दे दें क्योंकि हिमाचल में कर्मचारियों को अभी तक एरियर्ज नहीं दिए गए, वहां एक पैसे का भी एरियर नहीं दिया गया है। पंजाब में एक पैसा भी एरियर का नहीं दिया गया।(विघ्न) हम एरियर का 70 परसैंट दे चुके हैं और 30 परसैंट बाकी बचा है। अध्यक्ष महोदय, असली बात क्या है। (शोर एवं व्यवधान) हमारे विपक्ष के नेता ओम प्रकाश चौटाला जी को पढ़े लिखे आदमी पसंद नहीं है। प्रो. सम्पत सिंह जी इनके साथी होते थे वे इनको छोड़कर चले गए। चौधरी देवी लाल के समय में डॉ. कादियान जी, धीरपाल जी इनकी पार्टी में होते थे वे इनको छोड़कर चले गए, डॉक्टर एम.एल. रंगा जी इनको छोड़कर चले गए। डॉक्टर पुनिया इनके साथ होते थे वे भी इनको छोड़कर चले गए। मेरे कहने का मतलब यह है कि रामपाल माजरा जी , बड़शामी जी और अशोक अरोड़ा जी अब आपका नम्बर है। मैं यह कह रहा था कि ओम प्रकाश चौटाला को पढ़े लिखे लोग पसंद नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के बारे में इन्होंने कह दिया कि 3 -3 महीने के बाद पानी आता है जबकि ऐसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, प्राइज राइस के बारे में हमारी सरकार ने अभी निर्णय लिया है। गरीब लोगों के लिए, बी.पी.एल.और ए.पी.एल. वालों के लिए सस्ती दालें देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। काला चना 27 रुपये प्रति किलो, उड़द 58 रुपये प्रति किलो और साबुत मूंग 54 रुपये प्रति किलो देने का निर्णय लिया गया है। ए.पी.एल. परिवार वालों के लिए 6.86 रुपये प्रति किलो गेहूं देने का हमने निर्णय किया है। वर्ष 2009-2010 के लिए राज्य के बी.पी.एल. परिवारों को जारी किए जा रहे राशन पर 41 करोड़ रुपये की वार्षिक सबसिडी का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में आया है:—

> "In good news for the region, Haryana surpassed forward looking States of Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu and Karnataka by achieving 70% implementation rate of pledged investments during the economic slow-down of 2008-09. Also, the Punjab fared well with implementation rate close to 60%."

It is also written in it:—

> "While implementation rate of pledged investments for Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu and Karnataka were 45%, 40%, 38% and 34-36% respectively."

अध्यक्ष महोदय, इक्नोमिक्स टाइम्स में भी आया है इसको मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिमाचल में किस प्रकार से इन्होंने 5 परसैंट वैट भी लगाया है और सरचार्ज भी लगाया गया है। स्पैशल इकनोमिक जोन के बारे में ओम प्रकाश चौटाला जी ने कह दिया कि आपने कितने प्रपोजल रिसीव किए, कोई कार्य नहीं हुआ और न किसी को एन्यूटी दी गई। हमारे पास टोटल एस.ई.जैड के 100 प्रपोजल आए हैं जिनमें से 46 में गवर्नमैंट आफ इंडिया ने एप्रूवल दी है। 18 में इन प्रिंसिपल एप्रूवल दी है and Number of SEZs notified by the Government of India is 31. जो तीन ओपरेशनल एस.ई.जैड हैं उनमें से एक है मैसर्स डी.एल.एफ. लिमटिड विलेज सिलोखेड़ा, दूसरा मैसर्स गुड़गांव इन्फोस्पेस लिमटिड विलेज ढूंढाहेड़ा, गुड़गांव है और तीसरा मैसर्स साइबर सिटी, सैक्टर 24-25, गुड़गांव है। जो 5-6 एस.ई.जैड अंडर इम्पलीमैंटेशन हैं अगर मैं उनका नाम लूंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, एस.ई.जैड के बारे में मैं यह जरूर बताना चाहूंगा कि एस.ई.जैड के लिए 29 जनवरी, 2003 को सैक्शन-4 के नोटिस इनकी सरकार के समय में नरसिंगपुर, खाण्डसा, मोहम्मदपुर, झाड़सा, हरसरू, आदि गांवों के लिए हुआ था। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से एस.ई.जैड ये लोग भी लगाना चाहते थे और आज ये एस.ई.जैड का विरोध कर रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है कि हम जो यह जमीन एक्वायर कर रहे थे वह सरकारी एस.ई.जैड के लिए एक्वायर कर रहे थे या प्राईवेट लोगों को देने के लिए कर रहे थे इस बारे में भी कैप्टन साहब सदन को बतायें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, प्लीज आप बैठिये।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये लोग तो प्रदेश में कैसीनो लगाने जा रहे थे। हमारी सभ्यता में कैसीनो कहां लग सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनके समय में जो एस.ई.जैड के लिए जमीन एक्वायर की गई थी उसके बारे में चर्चा कर रहा था। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सैक्शन-4 के तहत 29 जनवरी, 2003 को नोटिस हुआ था। उसके बाद 27 जनवरी, 2006 को 1601 एकड़ जमीन का अवार्ड घोषित हुआ और 1383 acres of land was allotted to Reliance Haryana SEZ on 6.12.2006. उसकी कंवेंस डीड 26 अप्रैल 2007 को एग्जीक्यूट हुई। इस 1383 एकड़ लैंड में से 1086 acres of land has been notified for multi service SEZ. Remaining land is either under litigation or contiguous. The farmers or land owners are paid an average compensation of Rs.22.10 lac per acre. अध्यक्ष महोदय, इनके समय में डेढ़ लाख रुपये, दो लाख रुपये मुआवजा दिया जाता था। अध्यक्ष महोदय, यह जमीन एच.एस.आई.आई.डी.सी. to Reliance Haryana SEZ को ट्रांसफर की @ of Rs. 28.90 lac per acre which include the administrative charges. In addition, HSIIDC has given Sweat Equity of 10% in the project as a whole. अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा 8202 एकड़ जमीन रिलायंस हरियाणा कंपनी ने 22 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ऐक्वायर की है जिसमें से 7001 एकड़ जमीन झज्जर में है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, ये सुनते रहें मैं इनको सारी बात बताऊंगा। यह जो प्रोजैक्ट है इससे करीबन चार लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें दो लाख का रोजगार थ्रू डायरैक्ट इम्पलायमैंट होगा और दो लाख का रोजगार इनडायरैक्ट इम्पलायमैंट होगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त विपक्ष के साथियों ने यह भी कहा कि एन्यूटी नहीं दी गई। The Reliance Haryana SEZ has disbursed

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

an amount of Rs.8.38 crore towards annuity to the farmers in respect of this land @ of Rs.30 thousand per acre pe annum. अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से 30 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से रॉयल्टी दी गई है। इसके अतिरिक्त कंपनी वाले स्किल डवैल्पमैंट प्रोग्राम के ट्रेनिंग कैम्प चला रहे हैं और कई सड़कें भी बनवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त खाण्डसा के अंदर कम्यूनिटी सैंटर भी बनाये हैं और झाड़सा के अंदर रैनोवेशन भी करवाई है। इसके अतिरिक्त तकरीबन 47 इन्डीविजुवल सैनीटेशन घड़ी हरसरू में और घड़ोली खुर्द के अंदर लगाये हैं। इसके अतिरिक्त 13 गांवों में कम्यूनिटी सैंटर बनाये हैं जिनमें झाज्जर भी शामिल है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से हम ये कई प्रोग्राम चला रहे हैं जिनके द्वारा शिक्षा और हैल्थ की तरफ ध्यान दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इनके साथ में लैंड एक्वीजेशन का कोई प्रोविजन नहीं था।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के नेता ने बोलते हुए एस.ई.जैड के बारे में दो सवाल उठाये थे। एक तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि जो एच.एस.आई.आई.डी.सी. है इसकी पूरे प्रोजेक्ट में 10 प्रतिशत की इक्विटी है। दूसरा इन्होंने कहा कि एन्यूटी नहीं दी गई। इस बारे में हमारे वित्त मंत्री जी ने भी बताया है कि उन्हीं किसानों को 8.40 करोड़ रुपये की एन्यूटी दे चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त विपक्ष के नेता ने यह कह कर भी सदन को गुमराह किया कि इसी जमीन में से चार एकड़ जमीन 450 करोड़ रुपये में ऑक्शन हुई। अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड की बात है। जो विपक्ष के नेता ने कहा है यह बात बिलकुल तथ्य से परे है। एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने उस जमीन में से कोई जमीन ऑक्शन नहीं की है। विपक्ष के नेता शायद जो जमीन हुडा ने फाईव स्टार होटल के लिए ऑक्शन की थी उसकी बात कर रहे हैं और वह जमीन वहां से कई कि.मी. दूर है लेकिन ये लोग तो सही तथ्य न देकर हाउस को गुमराह करने का काम करते हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है कि मैंने यह कहा था कि उस जमीन के साथ लगता एक चार एकड़ का टुकड़ा एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने 290 करोड़ रुपये में ओपन आक्शन में नीलाम किया था।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 450 करोड़ रुपये कहा था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने 290 करोड़ रुपये कहा था। 450 करोड़ रुपये कभी नहीं कहा था। मैंने यह कहा था कि 290 करोड़ रुपये में चार एकड़ जमीन एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा ओपन आक्शन में दी गई।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जो एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने की है वह आई.एम.टी. मानेसर में की गई है जो कि कामर्शियल लैंड है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि एच.एस.आई.आई.डी.सी. के साथ लगती जमीन थी। मैंने जो बात कही है मैं उसी के ऊपर हूं।

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, फिर वही बात आ गई। (शोर एवं व्यवधान) उसने उसको कहा और उसने उसको कहा। प्लीज आप बैठें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं on the floor of the House कह रहा हूं कि वह जमीन उसके साथ लगती नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा था कि वह जमीन उस जमीन का पार्ट है लेकिन वह जमीन उसका पार्ट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप रिकार्ड निकालकर देख लें। ये सदन में असत्य बात कहकर सदन को गुमराह करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है, जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2010-2011 के लिए बजट पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, श्री चौटाला हर बात पर सदन को गुमराह करते हैं। कभी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के मैनीफैस्टो में कहा गया था कि हम VAT खत्म कर देंगे। स्पीकर सर, यह रहा कांग्रेस पार्टी का मैनीफैस्टो जिसे वित्त मंत्री ने पढ़कर भी सुनाया है। स्पीकर सर, ये मुझे दिखा दें कि इसमें कहां कहा गया है कि हम VAT को खत्म कर देंगे। स्पीकर सर, उस समय आप भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे जिस समय यह मैनीफैस्टो बनाया गया था। स्पीकर सर, इसी प्रकार से ये यमुनानगर के पावर प्लांट के बारे में कह देते हैं कि इसमें खराबी आ गई है इसलिए अब यह 6 महीने तक नहीं चलेगा। स्पीकर सर, विपक्ष के साथियों की जानकारी के लिए मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि यमुनानगर पावर प्लांट की यूनिट नम्बर-II केवल मात्र रिपेयर और मैंटीनैंस के लिए बंद थी और आज सुबह 04.33 बजे इस यूनिट में पावर का जैनरेशन शुरू हो चुका है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। स्पीकर सर, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यमुनानगर पावर प्लांट की जो यूनिट नम्बर-II है वह बहुत जल्दी चालू हो जायेगी। *******

Mr. Speaker : Don't record it. पंवार जी, आप कृपया भाषण न दें। आप कृपा करके अपनी सीट पर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, यहां पर लैंड एक्वीजीशन के बारे में भी एक सवाल उठाया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Panwar Ji, please take your seat. पंवार जी, यह आप भाषण दे रहे हैं या प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोल रहे हैं। आप कृपया बैठ जाईये।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, जैसा कि लेण्ड एक्वीजिशन के बारे में यहां पर चर्चा की गई। स्पीकर सर, इनके समय में 3 लाख से 7 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से गुड़गांव में किसानों को मुआवज़ा दिया गया था जबकि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार आने के बाद गुड़गांव के अर्बन एरियाज़ में 20 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन के रेट और प्लस 30 प्रतिशत सोलेशियम दिया गया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। स्पीकर सर, हमारी सरकार के समय में गुड़गांव में 29 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से भी कम्पनसेशन दिया गया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, आप कृपया बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, जो मैं बता रहा हूं कि इनके समय में 3 लाख से 7 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से गुड़गांव में रेट दिया गया यह रिकार्ड की बात है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्म पाल सिंह : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। स्पीकर सर, इस बारे में मेरे पास एक लिखित रिकार्ड है कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के समय में एक किसान ने 15 करोड़ रुपये में अपनी एक एकड़ ज़मीन अपनी मर्जी से बेची है। स्पीकर सर, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में यह अपनी तरह का एक मात्र उदाहरण होगा कि किसी किसान ने अपनी एक एकड़ ज़मीन 15 करोड़ रुपये में बेची हो। स्पीकर सर, इसके अलावा मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि जब श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी तो उस समय अली, अढ़ाणा, बांस, खुशला में किसानों को ब्याज सहित मात्र 3 लाख 30 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का मुआवज़ा दिया गया था। स्पीकर सर, उस समय उन लोगों के पास रोने के सिवाये और कोई चारा नहीं रह गया था। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Bhupinder Singh Hooda : Speaker Sir, in this regard, I want to put the record straight. अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो सवाल उठाया गया है इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पास इनके समय का रिकार्ड है। स्पीकर सर, जो 135 किलोमीटर लम्बा के.एम.पी. एक्सप्रैस हाईवे बनाया गया है इसके लिए इनकी सरकार के समय में जो अधिगृहीत की गई ज़मीन का कम्पनसेशन आंका गया था वह केवल मात्र 170 करोड़ रुपये था और जब हमारी सरकार आई तो हमने इस कम्पनसेशन को एनहांस करके 630 करोड़ रुपये किसानों को दिये।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, इस बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : ऑन ए प्वायंट ऑफ आर्डर सर। स्पीकर सर, इनकी सरकार ने तो एक-एक किलोमीटर और ज़मीन अधिग्रहण करने का भी मन बना लिया है जिससे 27 गांव प्रभावित हो रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Chautala Ji, please take your seat.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं आपकी अनुमति से केवल एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। स्पीकर सर, अभी तक आपकी अनुमति के बिना 12 बार विपक्ष के नेता वित्त मंत्री जी को उनके रिप्लाई के दौरान डिस्टर्ब कर चुके हैं। स्पीकर सर, हमने श्री चौटाला जी

की किसी रैलेवैंट बात पर ही रोका है यह नहीं कि हर दो मिनट के बाद जैसा कि विपक्ष के नेता बिना आपकी परमिशन के बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, एक बात विपक्ष के नेता ने मानेसर के नज़दीक इण्डस्ट्रियल हाऊसिंग के लिए 950 एकड़ लैंड अधिग्रहण करने के संदर्भ में कही है। स्पीकर सर, इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सरकार द्वारा हरियाणा प्रदेश की सत्ता सम्भालने के बाद सर्वप्रथम 25 करोड़ रुपये एच.एस.आई.आई.डी.सी. को इकोनॉमिक स्टीमुलस पैकेज के तौर पर दिये गये। इसके अलावा हमने आई.एम.टी. मानेसर में इण्डस्ट्रियल वर्कर्ज़ हाऊसिंग कॉम्पलैक्स बनाये हैं। इसमें 192 सिंगल डिवैलिंग यूनिट्स बनाई हैं। इसके अलावा इसमें वर्कर्ज़ के लिए 36 डोरमैट्री यूनिट्स अलग से बनाई हैं। इनका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी 23 मार्च, 2010 को करने वाले हैं। स्पीकर सर, इसके अलावा कुण्डली, बरही, राई, आई.एम.टी., रोहतक, आई.एम.टी., मानेसर (पार्ट-II), आई.एम.टी., फरीदाबाद इत्यादि 6 जगहों पर एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने नई आई.एम.टीज़. बनाई हैं। इन नई बनी आई.एम.टीज़. में सभी प्रकार की फैसेलिटीज़ मुहैया करवाई जायेंगी। इसी प्रकार से वर्ष 2005 से 2010 तक टोटल इनवैस्टमैंट 43500/- करोड़ रही which is more than the total investment attracted since 1966 till March, 2005 यानि जो उस समय तक टोटल इनवैस्टमैंट आई है यह उससे भी ज्यादा है। Similarly, the total Foreign Direct Investment attracted in the State so far is Rs. 12500/- crore of which Rs. 9277/- crore has been materialized during the last five year. अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी हमारे हरियाणा में बहुत सारी यूनिट्स लगी हैं। ये कह रहे थे कि कोई यूनिट नहीं लगी है जबकि बहुत सी यूनिट्स लगी हैं जैसे बावल में, बहादुरगढ़ में तथा कुण्डली में। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं इन सबके नाम पढ़ने लगूँगा तो बहुत समय लगेगा। मारुति सुजूकी, आई.एम.टी. रोहतक में टैस्ट ट्रैक फैसिलिटी आर.एंड डी. सैन्टर और कुछ एनसिलिरी यूनिट्स भी बना रही है। यू.के. बेस बैक ह्यू मैन्यूफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ जे.सी.बी. एट फरीदाबाद लगी है, यह 200 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट है। इसी प्रकार से US based Hollister Plant at Growth Centre, Bawal of Rs. 250 Crore है। इसी प्रकार से एक ओसराम एक्सपैन्शन फैसिलिटी फॉर मैन्यूफैक्चरर ऑफ लाइटिंग इक्विपमैंट एट कुण्डली 100 करोड़ रुपये की लगी है। इसी प्रकार से आई.एम.टी., रोहतक में एशियन पेन्ट्स का लार्जैस्ट प्लांट ऑफ मैन्यूफैक्थरिंग पेन्ट्स 500 करोड़ रुपये का लगा है। अध्यक्ष महोदय, इनका यह कहना कि यहाँ से इण्डस्ट्रीज पलायन कर गई हैं, सरासर गलत है। इनके समय में तो एक लिबर्टी की फैक्ट्री थी उसको भी इन्होंने पलायन करने पर मजबूर कर दिया था तथा उसके आगे इन लोगों ने गड्ढे खोद दिये थे। इन्होंने तो उनको भी नहीं टिकने दिया था। अध्यक्ष महोदय, हमने ऐसे काम नहीं किये बल्कि हमने तो फैक्ट्रियों को स्थापित किया है जिसके कारण यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इनवैस्टमैंट ज्यादा हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं जो बात कह रहा हूँ वह आँकड़ों के आधार पर कह रहा हूँ। हमने किसानों का ख्याल रखा है, इण्डस्ट्रीज के साथियों का ख्याल रखा है। इसके अलावा कृष्णपाल गुर्जर जी ने यह बात रखी कि इनफ्लेशन की वजह से फिस्कल डेफिसिट इनक्रीज हो रहा है यह बिल्कुल गलत बात है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2010-11 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के फलस्वरूप 2600 करोड़ रुपये का भार पड़ा। पैंशनर्स और कर्मचारियों को एरियर्ज देने पर 1570 करोड़ रुपये का बोझ हमारे ऊपर पड़ा है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमने पैसा खर्च किया है। पूरे विश्व में आर्थिक मंदी की मार पड़ी हुई थी। हमारा फिस्कल डेफिसिट भारत

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

सरकार ने 4 परसैंट फिक्स कर रखा है। अगर आप अपने फिस्कल डेफिसिट से ऊपर जाते हैं तो यह गलत संकेत होता है। हमारा जो फिस्कल डेफिसिट फिक्स कर रखा है हम उससे ऊपर नहीं गये और हम विद-इन नॉर्म ही रहे। एक बात यह भी कही गई कि जो हैंडीकैप्ड लोग हैं और ओल्ड ऐज पैंशनर्ज हैं उनके लिए पहले जो फिगर 2190 करोड़ रुपये थी उसको बढ़ाकर 2300 करोड़ रुपये कर दिया है। इस बारे में मेरा कहना है कि ये जो आँकड़े हैं ये गवर्नमैंट इम्पलाईज की पैंशन के हैं। अध्यक्ष महोदय, ओल्ड ऐज पैंशन का वर्ष 2004-05 के बजट में केवल 376 करोड़ रुपये का प्रावधान था उस समय ओमप्रकाश चौटाला जी की सरकार थी लेकिन वर्ष 2009-2010 के बजट में इसके लिए 1415 करोड़ रुपये का प्रावधान है जो कि 276 प्रतिशत ज्यादा है। (इस समय मेजें थपथपाई गई) यह नहीं है कि यहाँ पर जो बात कही गई है वह ऐसे ही कह दी गई है। अनिल विज जी ने एक बात कही थी कि बजट में दिखाई गई इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी मिसलीडिंग है। विज साहब, जैसा मैंने आपको कहा था कि आप इसको ध्यान से देख लो। एक्च्यूअली इस बारे में जो मिसक्लासिफिकेशन है वह ए.जी. हरियाणा की है और वह 106 करोड़ रुपये है। जब आप इस बारे में टोटल देखेंगे तो वह वर्ष 2008-09 में इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी 106.31 लिखी हुई है। यह गलती ए.जी. की थी उन्होंने वहाँ पर 106.31 करोड़ रुपये की जगह 10.61 लिख दिया। अगर आप टोटल देखेंगे तो यह 106.31 करोड़ रुपये है। उसके बाद वर्ष 2009-10 में रिवाइज्ड ऐस्टीमेट्स में यह 124 करोड़ रुपये है और आगे जाकर वर्ष 2010-2011 (बी.ई.) में 134 करोड़ रुपये हो गई है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बात और कह दी कि हमारी ग्रोथ रेट मध्यप्रदेश, गुजरात और बिहार की ग्रोथ रेट से भी कम है और उनकी ग्रोथ रेट हमारे से अधिक है। अध्यक्ष महोदय, ये प्रोजैक्शन 13वें वित्त आयोग के हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि बजट एट ए ग्लांस में कंसोलिडेटिड फंड में वर्ष 2010-11 में जो सेल्ज़ टैक्स दिखाये गये हैं वे 11500 करोड़ रुपये दिखाये गये हैं। जो रिवाईज्ड वर्ष 2009-10 में थे वे 9643 करोड़ रुपये थे यानि कि 1857 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा दिखाये गये हैं। इसका कोई बेसिज नहीं बनता क्योंकि रिवाइज्ड वर्ष 2009-2010 में सी.एस.टी. 403 करोड़ रुपये है। जबकि बजट ऐस्टीमेटस में यह 1450 करोड़ रुपए लिखा गया है। इस बारे में इनको कोई एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। (विघ्न) सर, यह किताब जो बजट के साथ दी जाती है इसको मैमोरैंडम एक्सप्लेनेटरी ऑन दि बजट कहते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : क्या आपने अब यह किताब दोबारा से पढ़नी है। आपने सब कुछ तो पहले ही कह दिया है। (विघ्न)

श्री अनिल विज : सर, इसमें 0040 हैड में लिखा हुआ है कि Rs. 456.34 crore was increased in the receipt is assumed on amount of more collection from CST &VAT. (Interruption).

कैप्टन अजय सिंह यादव : आपने तो यह सब कुछ पहले ही बता दिया है। आप मेरी बात सुनें मैं आपको इस बारे में आगे बताऊंगा। आप सुनते तो है नहीं और बोलने लग जाते हो। आप पहले सुने तो सही। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि जो ग्रोथ रेट है वह बिहार और मध्यप्रदेश का हमारे से ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये जो फिगर्ज हैं ये 13th फाईनांस कमीशन की हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि Haryana's GSDP

growth is the highest. बिहार का GSDP 10.56 % मध्यप्रदेश का GSDP 10.46% है गुजरात का GSDP 13.95 % है यह फिगर्ज 2010-11 के लिए प्रोजैक्टिड है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा का GSDP 13.91% है। हमारी जो पर-कैपिटा इन्कम है वह भी देश में सबसे ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, असल में बात तो यह है कि हेराफेरी हमने कभी नहीं की है। सर, अब मैं आपकी इजाजत से आर्बिट रिजॉर्ट के बारे में कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह एक प्राईवेट लिमिटिड कम्पनी थी। उस कम्पनी को सरदार प्रकाश सिंह बादल और उनकी वाईफ श्रीमती सुरिन्द्र कौर द्वारा मैनेज किया जाता है। स्पीकर सर, ये उनसे 15.10.1988 में एप्लीकेशन लेते हैं। यह एप्लीकेशन एच.एस.आई.डी.सी. को दी जानी चाहिए थी लेकिन अखबार में कोई एडवरटाईजमैंट नहीं दी जाती है और न ही और कोई बात हुई। स्पीकर साहब, इन्होंने सीधी उसकी एप्लीकेशन चीफ सैक्रेटरी के पास ले ली। स्पीकर सर, 25 से 30 एकड़ जमीन उद्योग विहार को अलॉट कर दी गयी। यह जमीन सबसे ज्यादा पॉश एरिया में है। वह जमीन इन्होंने उनको कोड़ियों के भाव अलॉट कर दी थी। स्पीकर साहब, जब यह मैटर सैक्रेटरी, टूरिज्म के पास गया तो उन्होंने इसको ऑन वेरियस ग्राऊंड्ज पर रिजैक्ट कर दिया। स्पीकर सर, उसके बाद इन्होंने एक हाई पॉवर कमेटी बनाई। उस कमेटी के द्वारा इन्होंने वह जमीन उनको अलॉट कर दी उसके बाद वह रिजॉर्ट खोल दिया गया। सर, 1996 में जब बंसी लाल जी की सरकार आई तो उन्होंने इसको रिज्यूम कर लिया और कहा कि यह बहुत गलत बात है। इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। यह जो होटल और रिजार्ट है यह बिल्कुल भी इन्डस्ट्रीज के अन्दर नहीं आता है। स्पीकर सर, एच.एस.आई.आई.डी.सी. का काम है कि हरियाणा में इण्डस्ट्रीज लगाए, होटलों को लगाने का काम उनका नहीं है लेकिन इन्होंने होटल के नाम पर यह जमीन उनको अलॉट कर दी। अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे बड़ी ब्लेयरिंग कमी रही है, HSIIDC as well as the State Govt. challenged the order dated 11.1.1999 by filing SLPs before the Hon'ble Supreme Court. However, although non-implementation of the project over the plot in question was the subject matter of SLPs, but an undertaking was given on behalf of M/s Orbit Resorts during the proceedings before the Hon'ble Supreme Court on 3.12.1999 that payment of the outstanding dues will be made within a period of 6 months and the construction will be completed within 2 years. The offer was not contested on behalf of the State Govt. and SLPs were disposed of by the Hon'ble Supreme Court vide order dated 3.12.1999. इनकी गवर्नमैंट ने उसको कन्टैस्ट नहीं किया। इन्होंने ऐसे व्यक्ति को कौड़ियों के भाव पर एक प्राईम लैंड, जो कि तकरीबन 25 एकड़ है, प्रकाश सिंह बादल जी जो इनके पगड़ी बदल भाई हैं को दे दी। इस तरह का काम ये लोग करते रहे हैं। हम लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। हम लोगों के जो काम होते हैं उसमें बकायदा ट्रांसप्रेंसी होती है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जिस जमीन के टुकड़े का ये जिक्र कर रहे हैं, उस बारे में सर्वोच्च न्यायालय में भी उनके पक्ष में फैसला हो चुका है। हर सरकार हर अदालत में गई, लेकिन हर अदालत में वे जीतते गए हैं। हर अदालत ने उनके पक्ष में फैसला दिया है। क्या आप सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर कोई निर्णय लेने जा रहे हैं ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जब स्टेट गवर्नमैंट ही उस बारे में उनसे दोस्ती कर ले तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है ? (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, उस समय इनकी गवर्नमैंट थी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इसके साथ यह भी कहा है कि प्लान साईज बहुत ही मामूली

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

सा बढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि जो हमारा टोटल प्लान बजट है, वह 10 हजार 500 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा यह सैन्टर स्पोंसर्ड स्कीम के तहत बढ़कर 11 हजार 863 करोड़ रुपए का हो गया है। स्वीकर सर, इसके अलावा 13th फाईनांस कमीशन से हमें और भी पैसा मिलना है। Speaker Sir, on the floor of the House मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो 10 हजार 500 करोड़ रुपए की फिगर है यह बढ़कर कम से कम 1000 करोड़ रुपए और आगे बढ़ेगा। सैंट्रल गवर्नमैंट से हमें और पैसा मिलेगा। इसी प्रकार से गुर्जर साहब और अनिल विज ने एक बात यहां पर कही कि the receipt of Revenue Accounts is Rs. 24540.83 crore of which Tax Revenue Rs.18663.00 crore and Sales Tax figures were Rs.880 crore in 2009-2010 BE, Rs.403.51 crore in 2009-10 RE and Rs.1450 crore in 2010-11 BE. इसमें पहले यह 2009-2010 में 880 करोड़ रुपये हुआ और उसके बाद 403 करोड़ रुपये हो गया। इसका कारण यह था कि देश के वित्त मंत्रियों की जो सैंट्रल इम्पावर्ड कमेटी बनी हुई है उसने यह फैसला किया था। जहां तक जनरल सैल्ज टैक्स लागू करने की बात है उससे सी.एस.टी. तीन से दो परसैंट हो गया और इन हैडस के अंदर जो 403 करोड़ रुपये हैं और हमें जो घाटा हुआ है उसके ऐवज में अंडर हैड-1601 ग्रांटस में हमें 965 करोड़ रुपये और मिले हैं। जो सी.एस.टी. कम हुई है उसका पहले हमने 880 करोड़ रुपये का प्रोवजिन रखा था। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि उसके बाद सी.एस.टी. कम हो गयी जिसकी वजह से यह 403 करोड़ रुपये हो गए। इसकी ऐवज में जो हमें लौस हुआ है उसके तौर पर सैंट्रल गवर्नमैंट ने हमें 965 करोड़ रुपये ग्रांट इन ऐड दिया है। जिसके बाद यह बढ़कर 1358 करोड़ रुपये हो गया है। स्पीकर सर, हमने 880 करोड़ रुपये का जो प्रोविजन रखा था वह बढ़कर 1358 करोड़ रुपये हो गया। 2010-11 के अंदर यह बढ़कर 1450 करोड़ रुपये हो गया। सर, यह इन लियू ऑफ दि सी.एस.टी. है। अध्यक्ष महोदय, यह बात गुजरात के अंदर भी की गयी है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनें।

श्री अध्यक्ष : विज साहब ऐसे डिबेट नहीं चलेगी। यह कोई बात नहीं है। जब एक मंत्री बोल रहे हैं तो आपको उनकी बात को सुनना चाहिए। आप बैठें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक बात और कही। जो रिलायंस की कम्पनी है उसके बारे उन्होंने कहा कि "allowing Reliance to change the BTG collaboration form Dongfang Electric Corporation, China to Shangai Electric Corporation by the Government resulted in a delay of 1 year in commissioning of DCRTPP, Units and there was a loss of 428 crore units. सर, इस मामले में ये लोग हाई कोर्ट गए लेकिन वहां से हार गए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए लेकिन वहां से भी हार गए। सी.डब्ल्यू.पी. नं0 13811 ऑफ 2005 है जिसमें बाकायदा उनके हक में फैसला हो गया। उसके बाद यह काम शंघाई इलैक्ट्रिक कोरपोरेशन को दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि इस प्लांट का पी.एल.एफ.लोड बहुत कम है। सर, जो टोटल पी.एल.एफ.लोड है वह 82.77 परसैंट है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोर्ट में कौन गया। ये गलत ब्यानी कर रहे हैं। कोर्ट में कोई गया होगा, हमें इस बात का सरोकार नहीं है। मैंने यह

कहा था कि जब हमने रिलायंस को यह काम दिया तो उस वक्त एक ऐग्रीमैंट हुआ था। उस ऐग्रीमैंट के तहत आप किसी कम्पनी को नहीं बदल सकते। उन्होंने हमारी सरकार के सामने अपनी दरख्वास्त दी लेकिन हमने वह रिजैक्ट कर दी और उसके बाद इनकी सरकार आयी और इनकी सरकार के सामने भी उन्होंने अपनी दरख्वास्त दी और इनकी सरकार ने भी वह रिजैक्ट कर दी। फिर एक महीने के बाद उसी कम्पनी को कैसे यह काम दे दिया गया, क्यों दिया गया ? इसमें कोई बड़ा चपला हुआ होगा। अध्यक्ष महोदय, उसी का परिणाम यह है कि आज यह यूनिट ठप्प पड़ी है। इस यूनिट से कितना नुकसान हो रहा है ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस कह रहा हूं कि यह यूनिट काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, आज यह यूनिट 4.33 बजे फंक्शन में आ गयी है फिर ये उसको ठप्प क्यों कह रहे हैं?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह तब कहा था जब यह यूनिट बंद थी। इससे पांच करोड़ रुपये रोज का नुकसान हो रहा है। अब यह यूनिट चला दी होगी लेकिन पता नहीं फिर कब यह ठप्प हो जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। (शोर एवं व्यवधान) अच्छी बात है कि यह यूनिट चल जाएगी लेकिन पता नहीं फिर कब बंद हो जाएगी ? जो नकली चीज होगी वह तो नुकसान देगी ही देगी।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, ये यह तो बता दें कि यह प्लांट कितने लोड पर चल रहा है ?

श्री अध्यक्ष : पंवार साहब, आपके लीडर बोल रहे हैं इसलिए आप बैठिए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, वह यूनिट चल गयी है। सुप्रीम कोर्ट तक ये हार गए। It has achieved a PLF of 82.77% till now in 2009-10 against the target PLF of 80% fixed by Haryana Electricity Regulatory Commission. श्रीमान जी, इसका लोड 82.77% है। अध्यक्ष महोदय, यह जो हमारा प्लांट है it has achieved the high level of performance, minimum environmental impact and awareness regarding occupational health and safety of the employees. इन सब चीजों को ये पूरा करता है, अच्छे कार्य के लिए इसको गोल्ड शील्ड दी गई है और ये गोल्ड शील्ड बाकायदा गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने दी है। Govt. of India has awarded HPGCL with a Gold Shield for early commencement of power generation from this plant. हमने एक साल की रिकार्ड अवधि में यह कार्य पूरा किया इसके लिए हमें गोल्ड शील्ड मिली और ये साथी कहते हैं कि इसको बनाने में देरी हुई है।

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि पैनल्टी कितनी लगी है यह भी बता दें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की व माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि दीनबंधु सर छोटू राम थर्मल पॉवर प्लांट-2 नॉर्मल मैंटीनेंस के लिए बंद हुआ था और यह 22 फरवरी, 2010 को बंद हुआ। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप लोग हाउस की कार्यवाही चलने नहीं देना चाहते इसलिए बार बार इंट्रप्ट कर रहे हैं। (विघ्न)

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इन्होंने यमुनानगर थर्मल पॉवर प्लांट का प्लांट लोड फैक्टर 82 प्वाइंट समथिंग बताया है, ये असत्य बता रहे हैं। मैं ऑन रिकार्ड कह रहा हूं कि यह 68.66 है। (विघ्न)

Capt. Ajay Singh Yadav: Speaker Sir, I am saying, on record. ये यहाँ चाहे कुछ भी बोलते रहें। (विघ्न) I am saying on record. जो मैं कह रहा हूँ ऑन रिकार्ड कह रहा हूँ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है विपक्ष के नेता उस दिन ये कह रहे थे कि वर्ष 2005 से 2010 तक एक यूनिट भी बिजली बननी शुरु नहीं हुई और आज ये और इनके साथी कह रहे हैं कि पी.एल.एफ. 82. समथिंग न होकर 66. समथिंग था। इस तरह से ये हाउस को गुमराह न करें और वित्त मंत्री जी को जवाब देने दें वे ऑन दि लैग हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, असल बात ये है कि बजट पर बोलते हुए ऐज लीडर ऑफ अपोजीशन इन्होंने केवल दो बातें कही हैं। एक तो नमक पर वैट के बारे में और दूसरे सरचार्ज के बारे में। इसके अलावा उन्होंने एक भी कोई और बात कही हो तो ये बताएं। सर, मैं बता रहा था कि दीन बंधु थर्मल पॉवर प्लांट-2, 22.2.2010 को नॉर्मल मैंटीनैंस के लिए बंद हुआ था और 15 मार्च, 2010 को पुन: चालू हो चुका है। ये सदन में कह रहे थे कि इसकी एक यूनिट भी नहीं चलती है। एक इन्होंने पूछा है कि three Units of Panipat Thermal Power Station are lying under shut down due to which there is a shortage of power in the State. Speaker Sir, the PLF of four large Units of Panipat (Unit 5, 6, 7 and 8) upto March 2011, is 92.96% और ये श्रीमान कहते हैं कि सारी यूनिटस बन्द पड़ी है। इसके अलावा पानीपत थर्मल पावर स्टेशन-2 की वर्ष 2004-05 में पी.एल.एफ. 79.74 थी और आज के दिन 92.96 परसैंट है और ये श्रीमान जी कहते हैं कि प्लांट बंद पड़ा है। इसके अलावा (विघ्न)

श्री कृष्ण लाल पंवार : पानीपत की पहली और तीसरी यूनिट की पोजीशन भी बता दें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : उनमें अभी रिपेयर का काम चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कहा कि सारी की सारी यूनिट्स बंद पड़ी हैं (विघ्न)

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, पानीपत की तीसरी यूनिट के बारे में भी बताएं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : पानीपत की तीसरी यूनिट के बारे में हमें उम्मीद है कि उसकी जनरेशन आज या कल से शुरु हो जाएगी।

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद के पॉवर प्रोजैक्ट का मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया था उसका क्या हुआ ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : जो टोटल ऐवरेज इस वक्त है वह 907 लाख यूनिट प्रति दिन है। जबकि इनके समय में 578 लाख यूनिट प्रति दिन था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2011-12 में हमने पांच हजार मेगावाट बिजली जनरेट करने का लक्ष्य रखा है जिसमें राजीव गांधी पॉवर प्लांट

खेदड़ में 1200 मेगावाट बिजली बननी शुरु हो जाएगी, ये 600-600 मेगावाट की दो यूनिट बनेंगी जिसमें से एक यूनिट 29.12.09 को शुरु हो चुकी है और दूसरी 600 मेगावाट की यूनिट अप्रैल, 2010 में चालू हो जाएगी। इंदिरा गांधी सुपर ताप बिजली परियोजना, झज्जर जो 1500 मैगावॉट की है उसकी 500 मैगावॉट की पहली यूनिट जुलाई 2010 में चालू हो जायेगी। महात्मा गांधी सुपर ताप बिजली परियोजना, झज्जर की 660 मेगावाट की पहली इकाई is targeted to be commissioned during 2010-11 and another 660 MW Unit-2 will be started by May, 2012. गौरखपुर गांव में 2800 मैगावाट क्षमता का परमाणु बिजली संयंत्र लगाने के लिए एप्रुव हो चुका है। इन्होंने एक बात कही कि लाईन लॉसिज हमारे समय में बहुत ज्यादा हैं। वर्ष 2004-05 में लाईन लॉसिज 32.52 प्रतिशत थे और उसके बाद वर्ष 2008-09 में घटाकर 28.62 प्रतिशत हो गये तथा वर्ष 2009-10 में यह घट कर 25.40 प्रतिशत हो गये हैं। विपक्ष के नेता यहां पर गलत बयानी कर रहे हैं। इसी प्रकार से श्री अशोक अरोड़ा जी ने एक बात कही कि 3200 करोड़ रुपये बिजली के बिलों का बकाया है। मुख्यमंत्री जी ने बिजली के बिल माफ करने की एक नई स्कीम निकाली थी। किसानों पर बिजली के बिलों के 1600 करोड़ रुपये बकाया थे। इस स्कीम के तहत 998 करोड़ रुपये in respect of agriculture tube-wells and rural domestic consumers have been waived off for those consumers who meet the terms and conditions. जिन लोगों ने टर्म्ज और कंडीशंज को फुलफिल किया उनके बिजली के बिल वेव-ऑफ किये गये हैं। डिफाल्टर टाईप के लोग कई बार बिजली के बिल नहीं भरते जिसके कारण ये बिल थोड़ा बढ़ जाते हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अब बिजली के बिलों का कितना एमाऊंट बाकी है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल सही है कि बिजली के बिलों की 3200 करोड़ रुपये की नॉन-पेमेंट बकाया है लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप यह देखिए कि मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से लोगों को सहूलियतें दी हैं। हमने विपक्ष की सरकार के समय की तरह किसानों पर गोलियां नहीं चलाई, किसानों पर अत्याचार नहीं किए। हम तो परश्युएशन से काम कर रहे हैं। इनके समय में कण्डेला में 9 किसानों को गोलियां मारी गई थी। हम तो यह चाह रहे हैं कि परश्युएशन से काम हो, तरीके से काम हो। इसी प्रकार से अरोड़ा जी ने कहा कि डेरों और ढाणियों के अन्दर बिजली की सप्लाई कमर्शियल तौर पर सिर्फ 4 घण्टे तक दी जाती है। ऐसी बात नहीं है कि डोमैस्टिक बिजली डोमैस्टिक आधार पर दी जाती है। अरोड़ा साहब ने यह भी कहा था कि डेरों और ढाणियों के अन्दर चार घण्टे बिजली आती है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि गाँव की लाईट की सप्लाई तो ट्यूबवैल्ज की लाईन से अलग कर दी गई है लेकिन इन डेरों और ढाणियों की लाईट की सप्लाई खेतों के ट्यूबवैल्ज की लाईट से जोड़ी गई है। मेरा कहना यह था कि उन डेरों और ढाणियों को भी बिजली गांव की तर्ज पर दी जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हम सर्वे कर रहे हैं।

डॉ. अजय सिंह चौटाला : मंत्री जी, आपने फरीदाबाद वाले प्लांट के बारे में नहीं बताया। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसे ही हमें गैस अवेलेबल हो जायेगी हम फरीदाबाद के प्लांट को चालू कर देंगे। हम यह मामला समय-समय पर टेक अप करते रहे

[कैप्टन अजय सिंह यादव]
हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, फिर यह कहते हैं कि हमारे खिलाफ प्रिवीलेज मोशन लेकर आते हैं। इन्होंने एक और असत्य बाद सदन में कही कि इस सरकार के कार्यकाल में एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया गया। (विघ्न)

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, पहले मंत्री जी बिजली के बारे में बतायें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये इस प्रकार से बार-बार बीच में खड़े हो जाएंगे तो बात नहीं बनेगी।

श्री अध्यक्ष : कृष्ण लाल जी, यह भाषण देने का वक्त नहीं है। आप बैठ जाईये। वित्त मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। I am not going to hear you. Please be seated.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के कार्यकाल में चार नये हॉस्पिटल्ज कैथल, पलवल, झज्जर और बहादुरगढ़ में बनाये जा रहे हैं और 6 मल्टी स्पैशलिस्ट हॉस्पिटल्ज तीन जिलों में बनने जा रहे हैं।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the Sitting of the House be extended up to half an hour ?

Voices : Yes, yes.

Mr. Speaker : The time of the Sitting of the House is extended for half an hour.

वर्ष 2010-2011 के लिए बजट पर चर्चा (पुनरारम्भण)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, तीन मैडिकल कालेजिज एक खानपुर कलां, एक नलहार मेवात और तीसरा कल्पना चावला के नाम पर करनाल में जिसके बारे में श्रीमती सुमिता सिंह जी ने बात की है, बनने जा रहे हैं। एक मैडिकल कालेज ई.एस.आई.सी. द्वारा फरीदाबाद में स्थापित किया जाएगा। 4 ट्रोमा सैंटर, 19 सी.एच.सीज., 79 पी.एच.सीज., 286 सब सैंटर्ज अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। 1350 डाक्टर्ज हमारी सरकार ने रिक्रूट किए हैं जबकि इनके समय में कुल 815 डाक्टर भर्ती किए गए थे। भाई अशोक कुमार अरोड़ा जी कह रहे थे कि 100 रुपये हॉस्पिटल में चार्ज किए जाते हैं तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि जो बी.पी.एल. परिवार के लोग हैं उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। सर्जरी फ्री की जाती हैं और दवाईयां भी फ्री दी जाती हैं। (विघ्न)

19.00 बजे

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि सिविल हॉस्पिटल में 100 रुपये बैड के पर डे के हिसाब से लिए जाते हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, गरीबी रेखा से नीचे वालों से बैड के कोई 100 रुपये नहीं लिए जाते। जो 100 रुपये लिए जाते हैं उसमें एडमिशन चार्जिज, नर्सिंग चार्जिज, ड्रग्स और ट्रीटमैंट के लिए दिया जाने वाले कंज्यूंऐबल्स वगैरह इनक्लूड हैं। अरोड़ा जी ने कहा कि अवैध कालोनियां नियमित नहीं की गई इस बारे में मैं इनको बताना चाहता हूं कि फरवरी, 2009 को मुख्यमंत्री महोदय ने अनाउंसमैंट की थी कि जितनी भी अवैध कालोनियां हैं अगर उन कालोनियों में 50 परसैंट ड्वैलिंग है तो उन कालोनियों को रैगुलेराइज करेंगे। अगस्त, 2009 में इस पोलिसी को एप्रूवल मिली। अध्यक्ष महोदय, इस पॉलिसी के तहत बाकायदा सर्वे किए गए। फरीदाबाद और गुड़गांव में डी.सी. के थ्रू केस मांगे जा रहे हैं। HARSAC, हिसार और टोप कोन सर्विंग इंडिया प्राइवेट लिमिटिड जो फरीदाबाद में है, को हमने थ्रू सैटेलाइट इमेजरी एंगेज किया है और उसका बाकायदा सर्वे चल रहा है। अवैध कालोनियों को रैगुलेराइज करने के लिए महेन्द्रगढ़, कैथल और सिरसा से केस यहां पर आ गए हैं, बाकी जगह से केस डी.सी. के थ्रू आने हैं। जहां जहां पर अवैध कालोनियां हैं अगर उन कालोनियों में 50 परसैंट ड्वैलिंग हैं तो उनको हमारी सरकार एप्रूव करेगी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने शूगर-केन के बारे में कह दिया कि शूगर-केन के जो मिनीमम प्राइस हैं वे सबसे कम हैं। हरियाणा में जो वैराइटीज वाइज स्टेट एडवाइज्ड प्राइस हैं उनमें बोनस लगाकर 210 रुपये तक हमने दिए हैं। उत्तर प्रदेश में यह प्राइज 205 रुपये है, उत्तराखंड में 215 रुपये हैं लेकिन हम साथ साथ में एडीशनल बोनस भी दे रहे हैं। वे एडीशनल बोनस नहीं दे रहे हैं। पानीपत, करनाल और शाहबाद में हमने एडीशनल बोनस 20, 30 और 40 रुपये दिया है। तमिलनाडू में स्टेट एडवाइज्ड प्राइस 155 रुपये, कर्नाटक में 200 रुपये और पंजाब में 180 रुपये है। हमारी सरकार ने पहली बार महाराष्ट्र की तरह एक पॉलिसी बनाई है जो 31.12.2009 को एप्रूव हुई है कि जो शूगर-केन में प्रॉफिट मिलेगा वह प्रॉफिट किसानों को मिलेगा। इस पॉलिसी के तहत नारायणगढ़, यमुनानगर, इन्द्री शूगर मिलों को प्रॉफिट दिया गया है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, अभी कैप्टन साहब ने अपने आप माना कि कुछ स्टेट्स का गन्ने का मिनीमम प्राइस थोड़ा सा फालतू है परन्तु आदरणीय गवर्नर साहब के एड्रैस में सरकार ने कहा कि हरियाणा प्रदेश ने पूरे देश में सबसे ज्यादा यह रेट दिया है। उसमें क्या इन्होंने झूठ बोला है। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, 210 रुपये के अलावा हमने एडीशनल बोनस दिया है। पानीपत, करनाल और शाहबाद की शूगर मिल को 20, 30 और 40 रुपये एडीशनल बोनस दिया है, तो हमारा रेट फालतू हुआ है या कम हुआ है ? (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो स्टेट एडवाइज्ड प्राइस हैं वे जब हमने फिक्स किए तो हमारे रेट पूरे देश में सबसे ज्यादा थे। दूसरी स्टेट्स ने हमारी स्टेट के रेट फिक्स होने के बाद अपनी स्टेट में ये रेट फिक्स किए हैं। जब हमने रेट फिक्स किए थे तो हमारे रेट सबसे ज्यादा थे। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बात कह दी कि हमने कोई एन्यूटी नहीं दी, हमने किसी को रॉयल्टी नहीं दी। मैं इनको बताना चाहूंगा कि लगभग 5238 नम्बर आफ बैनीफिशरीज ऐसे हैं जिनको हमने एन्यूटी दी है और जिसके तहत 17 करोड़ 21 लाख 41 हजार 455 रुपये टोटल दिए गए हैं। इतनी टोटल एन्यूटी हमने दी है और ये कहते हैं कि हमने एन्यूटी नहीं दी है। अध्यक्ष महोदय, ये हर चीज पर असत्य बोलते हैं। जिस प्रकार कृष्ण पाल गुर्जर जी

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

कह रहे थे कि फरीदाबाद में 1100 एकड़ जमीन प्राइवेट डिवैल्पर्स के लिए एक्वायर की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहता हूं कि यह जमीन जो एक्वायर की जा रही है यह सैक्टर्ज की रोड्स के लिए एक्वायर की जा रही है और will be used by all the residents of Sectors across Agra-Canal in Faridabad. These sector roads are not meant for colonizers alone.

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त विपक्ष के साथियों ने कलैक्टर रेट और हुडा के सैक्टर के बारे में बात की जिसके बारे में बत्रा जी ने पूरी जानकारी दे दी है मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा। (विघ्न)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है कि मंत्री जी ने फरीदाबाद के अंदर सैक्टर रोड्स के लिए 1100 एकड़ जमीन एक्वायर करने की बात कही है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह किसानों की जमीन है और वहां पर जिन किसानों ने ओपन मार्किट में अपनी जमीन बेची है वह दो करोड़ रुपये से लेकर अढ़ाई करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बिकी है। यह बात मैंने पहले भी कही थी और आज भी कह रहा हूं। मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं इसलिए इनसे आश्वासन चाहूंगा कि वहां के किसानों की जमीन अढ़ाई करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से एक्वायर की जाये।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि हुडा के सैक्टर्ज के बारे में बत्रा जी ने पूरी जानकारी सदन में दे दी है इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि हमारी सरकार आने के बाद हुडा के कई सैक्टर काटे गये हैं और विपक्ष के साथियों ने हुडा के सैक्टर न काटने के बारे में असत्य बात इस महान सदन में कही। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा विपक्ष के साथियों की तरफ से कहा गया कि राशन कार्ड के द्वारा किसानों को फर्टीलाईजर दिया जाता है इनकी यह बात बिल्कुल गलत है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में यूरिया की अवेलेबिलिटी 10.3.2010 तक 10.19 लाख मिट्रिक टन थी जिसमें से 9.99 लाख मिट्रिक टन यूरिया फारमर्ज द्वारा यूज किया गया है। The availability of urea was 10.19 Lakh MT upto 10.3.2010, whereas only 9.99 lakh MT was consumed by the farmers in the State. Similarly 4.12 lakh MT of DAP fertilizer was available in the State during Rabi 2009-10 season, whereas only 4.08 lakh MT was actually consumed. जहां तक राशन कार्ड की बात है तो हमने राशन कार्ड नहीं मांगे बल्कि हमने यह किया है कि जो किसान 5 बैग्ज DAP खरीदेगा तो उसको किसान पास बुक लेकर आने पर ही DAP दिया जाएगा है ताकि खाद की ब्लैक मार्केटिंग न हो क्योंकि पीक सीजन में खाद की बहुत दिक्कत आती है। उस समय दूसरे प्रदेश के किसान हमारे यहां आकर डी.ए.पी. खरीदते हैं। किसान पास बुक के लागू करने के बाद दूसरे प्रदेश के किसान हमारे यहां से यूरिया नहीं खरीद सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, इससे तो किसानों का ही फायदा होगा और प्रदेश में कहीं पर खाद की कमी नही होगी। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त पंजाबी भाषा के बारे में भी विपक्ष के साथियों ने सवाल उठाया। इस बारे में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि पंजाबी भाषा को प्रदेश में दूसरी भाषा का दर्जा हमने दिया है और इस बारे में नोटिफिकेशन भी हमने की है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने 1120 टीचर्ज पंजाबी भाषा के लगाये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है कि मंत्री जी कृपया यह बतायें कि पंजाबी भाषा को प्रदेश में दूसरी भाषा का दर्जा देने के लिए बिल कब आया, वह बिल विधान सभा में कब रखा गया, कब पास हुआ और कब उसकी नोटिफिकेशन हुई ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2004 में यह बिल आया। उस समय चुनाव होने वाले थे इसलिए जनता को लॉली पोप देने के लिए यह बिल ये लोग लेकर आये थे लेकिन इसको लागू हमने किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, ये लोग पिछले पांच साल तक क्या करते रहे और उसको आज लागू कर रहे हैं। इन्होंने तो इसको पांच साल तक लटका कर रखा है।

श्री अध्यक्ष : पंजाबी की बात तो आप सारे करते हो लेकिन सदन में पंजाबी बोलता कोई नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, पंजाबी में बोलने पर अरोड़ा साहब को तकलीफ होती है।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा साहब, आपको सदन में पंजाबी में बोलना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) अरोड़ा साहब, आप पंजाबी में भाषण दो।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, अरोड़ा साहब, को पंजाबी में बोलना चाहिए, हम इनको पूरा मौका दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पंजाबी भाषा का पूरा ध्यान रखा है और हम तो हमारे प्रदेश के लिए अलग से गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी बनाना चाहते हैं लेकिन ये लोग अकालियों को बहका देते हैं कि ऐसा मत करो। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं बता रहा था कि हमारी सरकार ने पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए 1120 टीचर पंजाबी भाषा के नियुक्त किए हैं और वे पंजाबी एरियाज में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। विपक्ष के साथियों ने यह गलत बात कही है कि हमने पंजाबी भाषा के टीचर नहीं लगाये। अध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट का समय और लूंगा तथा इसके अतिरिक्त मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के दिन प्रदेश में कहीं पर भी बीजों की कोई कमी नहीं है।

स्पीकर सर, अपने बजट में हमने समाज के प्रत्येक वर्ग का पूरा ध्यान रखने की भरपूर कोशिश की है।

श्री अध्यक्ष : हां जी सम्पत सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, वित्तमंत्री जी ने सभी मैम्बर्ज़ की क्यूरीज़ का काफी अच्छा और डिटेल्ड रिप्लाई दे दिया है लेकिन श्री चौटाला जी ने अभी फिर कहा है कि सरकार द्वारा लोन लिये गये हैं लेकिन उनकी पेमैंट नहीं की गई है। स्पीकर सर, मैं चौटाला जी को बताना चाहता हूं कि Budget at a Glance जो किताब है इसके पेज़ नम्बर 10 पर रिपेमैंट ऑफ लोन्ज़ के बारे में बताया गया है और इसी प्रकार से इसी किताब के पेज़ नम्बर 15 पर पेमैंट ऑफ इंटरेस्ट का जिक्र किया गया है। अगर चौटाला जी इसको पढ़ें तो उनको जवाब मिल जायेगा। स्पीकर सर, इसके मुताबिक पिछले पांच सालों के दौरान सरकार द्वारा 12997 करोड़ रूपये लोन की रिपेमैंट के रूप में अदा किये गये हैं और इसी प्रकार से 9137 करोड़ रूपये पेमैंट ऑफ इंट्रस्ट के रूप में दिये गये हैं। स्पीकर सर, इस प्रकार से सरकार ने लोन की भी पेमैंट की है और इंट्रस्ट की भी इसलिए श्री चौटाला जी का यह कहना पूर्णतया असत्य है कि सरकार द्वारा न तो लोन की रिपेमैंट की गई और न ही इंट्रस्ट की पेमैंट की गई है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि हमने पूर्ण रूप से कोशिश की है कि इस बजट के अंदर जो हमारा आधारभूत ढांचा है उसको मज़बूत करने के लिए कारगर कदम उठाये जायें। स्पीकर सर, चाहे प्रदेश के अंदर कॉरीडोर बनाने का मामला हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात हो और चाहे स्टीमुलस पैकेजिज देने की बात हो हमने सभी को प्राथमिकता के तौर पर लिया है। स्पीकर सर, हमने सिक्स्थ पे-कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के साथ-साथ अपने इम्पलाईज़ को एरियर की पेमैंट भी की है जिससे हमारे स्टेट एक्सचैकर पर 2600 करोड़ रूपये सालाना का अतिरिक्त भार पड़ा। स्पीकर सर, इतनी समस्याएं होने के बावजूद भी हमने प्रदेश के लिए विकासशील बजट प्रस्तुत किया है और प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश की है। स्पीकर सर, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे चुनौतियां पसंद है और मेरा अपना मानना है कि कठिनाईयों के बिना जीवन बेकार हो जाता है। स्पीकर सर, इस पर मैं एक शेयर सुनाना चाहता हूँ :—

"मौज़ें हवादिस अगर आसानियां हों तो जिंदगी दुश्वार हो जाये।"

स्पीकर सर, हम सुनियोजित तरीके से काम करना चाहते हैं। इसके साथ मैं हाऊस के सभी साथियों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे मेरे द्वारा प्रस्तुत बजट को सर्वसम्मति से पास कर दें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, जैसा कि आपने भी देखा है कि विपक्ष के नेता ने लगभग-लगभग प्रत्येक विषय पर हाऊस को गुमशाह करने की कोशिश की है इसलिए मैं इनको एक बात सुनाना चाहता हूँ कि "सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहां पैदल ही जाना है।"

बजट 2010-2011 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Now, the discussion and voting on the Demands for Grants on Budget for the year 2010-2011 will take place.

As per the past practice and in order to save the time of the House, all the demands appearing on the order paper may be deemed to have been read and moved together. Hon'ble Members can discuss any demand but they are requested to indicate the Demand No. on which they wish to raise the discussion.

That a sum not exceeding **Rs. 24,32,13,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 1 — **Vidhan Sabha.**

That a sum not exceeding **Rs. 42,15,70,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 2— **Governor & Council of Ministers.**

That a sum not exceeding **Rs. 116,56,06,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 3 — **General Administration.**

That a sum not exceeding **Rs. 5,91,11,71,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 4— **Revenue.**

That a sum not exceeding **Rs. 1,09,52,34,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 5 — **Excise & Taxation.**

That a sum not exceeding **Rs. 23,39,54,54,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 6— **Finance.**

That a sum not exceeding **Rs. 2,50,00,00,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 7 — **Planning and Statistics.**

That a sum not exceeding **Rs. 8,65,13,10,000 for revenue expenditure** and **Rs. 12,13,07,50,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 8 — **Buildings & Roads.**

That a sum not exceeding **Rs. 57,88,56,56,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 9 — **Education.**

That a sum not exceeding **Rs. 2,39,08,95,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 10 — **Technical Education.**

That a sum not exceeding **Rs. 75,06,59,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 11 — **Sports & Youth Welfare.**

That a sum not exceeding **Rs. 11,92,27,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 12 — **Art & Culture.**

That a sum not exceeding **Rs. 11,17,12,76,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 13 — **Health.**

That a sum not exceeding **Rs. 97,51,57,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 14— **Urban Development.**

That a sum not exceeding **Rs. 7,11,11,16,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 15 — **Local Government.**

That a sum not exceeding **Rs. 29,14,36,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 16— **Labour.**

That a sum not exceeding **Rs. 66,55,47,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 17— **Employment.**

That a sum not exceeding **Rs. 1,18,87,16,000 for revenue expenditure** and **Rs. 25,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 18 – **Industrial Training.**

That a sum not exceeding **Rs. 1,88,46,11,000 for revenue expenditure** and **Rs. 2,65,60,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges what will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 19—**Welfare of SCs & BCs.**

That a sum not exceeding **Rs. 14,41,17,42,000 for revenue expenditure** and **Rs. 2,86,20,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 20 — **Social Security & Welfare.**

That a sum not exceeding **Rs. 4,69,96,04,000 for revenue expenditure** and **Rs. 75,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 21 — **Women & Child Development.**

That a sum not exceeding **Rs. 47,91,39,000 for revenue expenditure** and **Rs. 40,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 22 — **Welfare of Ex-servicemen.**

That a sum not exceeding **Rs. 2,43,41,19,000 for revenue expenditure** and **Rs. 38,16,25,11,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 23 — **Food & Supplies.**

That a sum not exceeding **Rs. 11,05,30,70,000 for revenue expenditure** and **Rs. 4,36,40,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to

defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 24 — **Irrigation.**

That a sum not exceeding **Rs. 69,15,42,000 for revenue expenditure** and **Rs. 50,20,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 25 — **Industries**

That a sum not exceeding **Rs. 14,66,75,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 26— **Mines & Geology.**

That a sum not exceeding **Rs. 5,83,66,68,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 27— **Agriculture.**

That a sum not exceeding **Rs. 2,86,50,97,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 28 — **Animal Husbandry & Dairy Development.**

That a sum not exceeding **Rs. 24,48,47,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 29— **Fisheries.**

That a sum not exceeding **Rs. 1,94,55,12,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-1 1 in respect of charges under Demand No. 30 — **Forests & Wildlife.**

That a sum not exceeding **Rs. 3,40,53,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 31 — **Ecology & Environment.**

That a sum not exceeding **Rs. 946,27,18,000 for revenue exependiture** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 32 — **Rural & Community Development.**

That a sum not exceeding **Rs. 82,25,00,000 for revenue expenditure** and **Rs. 13,22,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 33 — **Co-operation.**

That a sum not exceeding **Rs. 10,61,93,85,000 for revenue expenditure** and Rs. 1,56,02,50,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No.34 — **Transport.**

That a sum not exceeding **Rs. 2,34,63,000 for revenue expenditure and Rs. 18,30,00,000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 35 — **Tourism.**

That a sum not exceeding **Rs. 14,17,26,57,000 for revenue expenditure** and **Rs. 1,30,50,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 36 — **Home.**

That a sum not exceeding **Rs. 30,97,75,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 37— **Elections.**

That a sum not exceeding **Rs. 6,64,19,00,000 for revenue expenditure** and **Rs. 6,49,50,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 38—**Public Health & Water Supply**

That a sum not exceeding **Rs. 51,83,47,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 39—**Information & Publicity.**

That a sum not exceeding **Rs. 29,88,24,27,000 for revenue expenditure** and **Rs. 10,54,77,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No.40 — **Energy & Power.**

That a sum not exceeding **Rs. 19,58,24,000 for revenue expenditure** and **Rs. 1,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 41 — **Electronics & IT.**

That a sum not exceeding **Rs. 1,45,81,45,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 42 — **Administration of Justice.**

That a sum not exceeding **Rs. 74,79,01,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 43 — **Prisons.**

That a sum not exceeding **Rs. 37,04,34,000 for revenue expenditure** and **Rs. 5,60,000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No 44—**Printing & Stationery.**

That a sum not exceeding **Rs. 16,02,39,60,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 45 — **Loans & Advances by State Government.**

Mr. Speaker : I have also received Cut Motions given notice of by Shri Ram Pal Majra, Shri Ashok Kumar Arora and Shri Ajay Singh Chautala and Rao Bahadur Singh on Demand Nos. 3 , 9, 10, 11, 13, 24, 27, 34 and 36 will also be deemed to have been read and moved. However, I shall put the Cut Motions to the vote of the House when the respective demands are put to the vote of the House. Such Members may, however, participate in the discussion.

Demand No. 3

1. Shri Ram Pal Majra;
2. Shri Ashok Kumar Arora and
3. Shri Ajay Singh Chautala, M.L.A.s

That Demand No. 3 of Rs.116,56,06,000/- for revenue expenditure on account of General Administration be reduced by Rs. 1/-.

Demand No.9

1. Shri Ram Pal Majra;
2. Shri Ashok Kumar Arora and
3 Shri Ajay Singh Chautala, M.L.A.s

That Demand No.9 of Rs. 5788,56,56,000/- for revenue expenditure on account of Education be reduced by Rs. 1/-.

Demand No. 10

1. Shri Ram Pal Majra;
2. Shri Ashok Kumar Arora and
3. Shri Ajay Singh Chautala, M.L.A.s

That Demand No.10 of Rs.239,08,95,000/- for revenue expenditure on account of Technical Education be reduced by Rs.1/-.

Demand No. 11

1. Shri Ram Pal Majra;
2. Shri Ashok Kumar Arora and
3. Shri Ajay Singh Chautala, M.L.A.s

That Demand No.11 of Rs.75,06,59,000/- for revenue expenditure on account of Sports & Youth Welfare be reduced by Rs.1/-

Demand No. 13

1. Shri Ram Pal Majra;
2. Shri Ashok Kumar and
3. Shri Ajay Singh Chautala M.L.A.s

That Demand No. 13 of Rs. 1117,12,76,000/- for revenue expenditure on account of Health be reduced by Rs.1/-.

Demand No. 24

1. Shri Ram Pal Majra;
2. Shri Ashok Kumar Arora;
3. Shri Ajay Singh Chautala and
4. Rao Bahadur Singh, M.L.A.s

That Demand No. 24 of Rs. 1105,30,70,000/- for revenue expenditure and Rs. 436,40,00,000/- for capital expenditure on account of Irrigation be reduced by Rs. 1/-.

Demand No. 27

1. Shri Pam Pal Majra;
2. Shri Ashok Kumar Arora and
3. Shri Ajay Singh Chautala, M.L.A.s

That Demand No. 27 of Rs. 583,66,68,000/- for revenue expenditure on account of Agriculture be reduced by Rs. 1/-.

Demand No. 34

1. Shri Ram Pal Majra
2. Shri Ashok Kumar Arora and
3. Shri Ajay Singh Chautala, M.L.A.s

That Demand No. 34 of Rs.1061,93,85,000/- for revenue expenditure and Rs. 156,02,50,000/- for capital expenditure on account of Transport be reduced by Rs. 1/-.

Demand No. 36

1. Shri Ram Pal Majra;
2. Shri Ashok Kumar Arora and
3. Shri Ajay Singh Chautala, M.L.A.s

That Demand No. 36 of Rs.1417,26,57,000/- for revenue expenditure and Rs. 130,50,00,000/- for capital expenditure on account of Home can be reduced by Rs.1/-.

Mr. Speaker : Now, I will put the Cut Motions on the Demands to the vote of the House and then I will put the Demands to the vote of the House.

Demand Nos. 1 & 2

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not **exceeding Rs.24,32,13,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010- 11 in respect of charges under Demand No. 1 —— **Vidhan Sabha.**

That a sum not **exceeding Rs.42,15,70,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 2 —— **Governor & Council of Ministers.**

The motion was carried.

Demand No. 3

Mr. Speaker : Now, I put Cut Motion No. 1 on Demand No. 3 given by Shri Ram Pal Majra, Shri Ashok Kumar Arora and Shri Ajay Singh Chautala, M.L.As. to the vote of the House.

श्री रामपाल माजरा (कलायत) : अध्यक्ष महोदय, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर ज्यादा खर्च इसलिए आया है क्योंकि इसमें फिजूलखर्ची ज्यादा हुई है। फिजूलखर्च कैसे हुआ ? माल आया और फिजूलखर्च कर दिया। इस तरह की स्कीम बना दी जिससे ज्यादा खर्चा हो गया। यह आपके सामने है सर। बी.पी.एल. कार्ड धारकों के घर के आगे इनकी पार्टी के रंग की तीन रंग की पट्टी लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, उससे खर्चा तो बढ़ा ही है। उससे फिजूलखर्च हुआ है। इसी प्रकार एक-एक अधिकारी के घर पर 2-2 या 3-3 गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई हैं जिसकी वजह से उनका खर्च बढ़ना तो स्वाभाविक है। बहुत से अधिकारी इस तरह के हैं जो बॉस की मर्जी के मुताबिक फैसले करते हैं जिसके दम पर वे रिटायरमैंट के बाद फिर से रिइम्पलाइमैंट ले जाते हैं। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके हल्के में भी देखा है। कि बी.पी.एल. कार्ड धारकों के घर के आगे तीन रंग की पट्टियाँ पोत दी गई हैं, उससे फिजूलखर्ची भी बढ़ी और समाज से उनको एक तरह से निकाल दिया गया है। ऐसी स्थिति में अगर कोई रिश्ते वाला आता है तो वह देखते ही समझ जाता है कि यह तो पहले ही गरीबी रेखा से नीचे है और उनके रिश्ते भी नहीं हो पाते हैं। इसी प्रकार से बहुत से अधिकारी रिटायर हो जाते हैं, उनकी उम्र रिटायरमैंट की हो जाती है लेकिन वे अपने बॉस के मुताबिक इस प्रकार के फैसले देते हैं जिससे वह बॉस खुश हो जाये और रिइम्पलाइमैंट ले जाते हैं। जिसकी वजह से फिजूलखर्ची बढ़ रही है। इसी प्रकार से एक-एक अधिकारी के ऑफिस में दो-दो या तीन-तीन गाड़ियाँ दी गई हैं जो उनके बच्चों को स्कूल, कॉलेज में छोड़ने जाती हैं। इसी कारण जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर हैवी एक्सपैंडीचर हो रहा है और इसलिए मैंने कट मोशन दिया है।

Mr. Speaker : Question is—

That Demand No.3 of Rs.116,56,06,000/- for revenue expenditure on account of General Administration be reduced by Rs.1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs.116,56,06,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 3 — General Administration.

The motion was carried.

Demand Nos. 4 to 8

Mr. Speaker : Question is —

That a sum not exceeding Rs.591,11,71,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No.4-Revenue.

That a sum not exceeding Rs.109,52,34,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No.5 - Excise & Taxation.

That a sum not exceeding Rs.2339,54,54,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No.6 - Finance.

That a sum not exceeding Rs.250,00,00,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No.7- Planning and Statistics.

That a sum not exceeding Rs.865,13,10,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No.8 - Buildings & Roads.

The motion was carried.

Demand No. 9

Mr. Speaker : Now, I put cut motion No.2 on Demand No.9 given by Shri Ram Pal Majra, Shri Ashok Kumar Arora and Shri Ajay Singh Chautala, M.L.A.s to the vote of the House.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, सरकार कहती है कि हमने ऐजूकेशन में बहुत सुधार किया है। सर, खर्चा तो ज्यादा होना ही था और जहां तक परिणाम की बात है तो परिणाम आपके सामने है। शिक्षा से सम्बन्धित केन्द्र की बहुत सी स्कीमें आई हैं और इन्होंने भी बहुत कुछ कहा जैसे अंगूठा टेक रहेगा न एक, साक्षर भारत, प्रौढ़ शिक्षा और सर्वशिक्षा अभियान लेकिन आज प्रदेश में शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आज प्रदेश में साक्षरता दर 67.91 प्रतिशत है। इसमें पुरूषों की साक्षरता दर 78.49 प्रतिशत है और महिलाओं की 55.73 प्रतिशत है। अध्यक्ष महोदय,

यह दर एक ऐसा इंडिकेटर है कि किसी प्रदेश का शिक्षा का प्रबन्धन किस प्रकार से हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट आपके सामने है जो कि 21.6 प्रतिशत है। इसी प्रकार से मिड-डे-मील में जिस प्रकार की गुणवत्ता है वह भी सभी जानते हैं। बच्चे अगर मिड-डे-मील में मिलने वाले खाने को खाते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ऐजुसैट प्रणाली के बारे में भी कुछ कहना चाहूँगा। इन्होंने इस प्रणाली का बड़ा ढोल पीटा था लेकिन यह कामयाब नहीं हो पाई। आज कहीं पर कम्प्यूटर्ज को चलाने के लिए बैट्री नहीं है, कहीं पर बिजली का ही प्रबन्ध नहीं है और उनमें से बहुत से कम्प्यूटर्ज चोरी भी हो गये हैं। इनमें से ज्यादातर एजुसैट सैंटर आज बंद पड़े हैं। शिक्षा के मंदिरों में गुरू अपना फर्ज भूल गये और उन्होंने गुरु शिष्य के रिश्तों को तार-तार किया है। कितने जघन्य कांड और न जाने कितने कुकृत्य सामने आये हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से इनसाइक्लोपीडिया में हरियाणा प्रदेश की सारी गौरव गाथा छापी गई है। यह बात आपके सामने ही है कि पहले तो 1 नवम्बर, 2008 को गवर्नर साहब से उस किताब का विमोचन करवाया गया और फिर उसको वापिस ले लिया गया। इस बारे में इनका कहना था कि किताब अभी पूरी नहीं हुई है। सर, उसके बाद इन्होंने क्राफ्ट मेले में उस किताब के थर्ड या सैवन्थ वोल्यूम का उद्घाटन कर दिया। इस किताब में हरियाणा प्रदेश की हिस्ट्री है, हरियाणा प्रदेश के हिस्टोरिकल प्लेसिज़ के बारे में इन्फर्मेशन है और हरियाणा की नहरों और सड़कों के बारे में पूरी जानकारी है। स्पीकर सर, यह किताब जितनी भी छपी है और उसके उतने ही छपने के बाद उसके लिए एक ही टैण्डर किया गया है तथा एक ही पार्टी को वह दिया गया है। स्पीकर सर, आज भी अगर हम उस किताब को किसी दुकानदार या पब्लिशर से लेने के लिए जाएं तो वह किताब मिलती नहीं है क्योंकि यह किताब अभी तक पूरी छपी ही नहीं है। स्पीकर सर, उस किताब के बारे में यह भी कहा गया है कि उसकी कीमत 25 हजार रुपये के करीब होगी। सर, 25 हजार रुपये में कौन सा आदमी हरियाणा के बारे में जानकारी ले सकेगा कि हरियाणा की कौन-कौन सी सम्पत्तियां हैं। स्पीकर सर, आज हरियाणा में 22 लाख बच्चे स्कूलों में जाते हैं और केवल 15 लाख बच्चे गवर्नमैंट स्कूलों में जाते हैं। 15 लाख बच्चे वे हैं जिनको यह सरकार कहती है कि उन बच्चों को ऐड मिलती है। ये शिक्षा के बारे में बड़ी-बड़ी डींगे मारते हैं कि हमने शिक्षा का बहुत अच्छा प्रबन्धन किया है। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सदन में बैठे मेरे माननीय साथियों से और यहां बैठे अधिकारियों से जानना चाहता हूँ कि किन-किन के बच्चे गवर्नमैंट स्कूलों में पढ़ते हैं ? स्पीकर सर, कोई तो ऐसी बात है कि सबके बच्चे प्राईवेट स्कूलों में जाते हैं। आज आप देखते हैं कि सरकारी स्कूलों में हमारे कितने ही मुख्य अध्यापकों और अध्यापकों के पद खाली हैं। आज उन पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा कुछ नहीं किया जाता है। अगर शिक्षक अपनी मांगों के बारे में रोहतक जाएं तो उनको मारा जाता है, अभी पिछले दिनों ही वहां पर राजरानी नाम की शिक्षिका को मार दिया गया। अगर कम्पयूटर टीचर्ज अपनी मांगों के लिए जाते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। क्या शिक्षा का प्रबन्धन ऐसा होता है ? मुझे समझ नहीं आता है कि ये शिक्षा में ज्यादा की डिमान्ड क्यों लेकर आते हैं ?

Mr. Speaker : Question is—

That Demand No. 9 of Rs. 5788,56,56,000/- for revenue expenditure on account of Education be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 5788,56,56,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 9-Education.

The motion was carried.

Demand No. 10

Mr. Speaker : Now, I put cut motion No. 3 on Demand No. 10 given by Shri Ram Pal Majra, Shri Ashok Arora and Shri Ajay Singh Chautala, M.L.As. to the vote of the House.

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, मैं टैक्नीकल एजुकेशन पर बोलना चाहता हूं। स्पीकर सर, मंत्री जी ने बोलते हुए कहा कि हमारी टैक्नीकल एजुकेशन में इतनी सीटस हो गई हैं। स्पीकर सर, टैक्नीकल इन्स्टीच्युशन खुलें, यह हम भी चाहते हैं, परन्तु यह नहीं होना चाहिए कि नार्मज़ को पांव तले रौंद कर और पैसा लेकर इन्स्टीच्युशंज़ को खोल दिया जाए। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगली दफा इसका नतीजा सामने आ जाएगा। अब की बार भी 20 प्रतिशत कम दाखिले हुए हैं और यह संख्या अगली दफा और भी कम हो जाएगी। (विघ्न) स्पीकर सर, जिस प्रकार से इन्होंने खेतों और खलिहानों में एजुकेशन का एक्सपैंशन कर दिया है, यह ठीक है कि ऐसा होना चाहिए लेकिन एजुकेशन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका व्यापारीकरण नहीं करना चाहिए। (विघ्न)

Mr. Speaker : Question is—

That Demand No. 10 of Rs. 239,08,95,000/- for revenue expenditure on account of Technical Education be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 239,08,95,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 10 Technical Education.

The motion was carried.

Demand No. 11

Mr. Speaker : Now, I put cut motion No. 4 on Demand No. 11 given by Shri Ram Pal Majra, Shri Ashok Arora and Shri Ajay Singh Chautala to the vote of the House.

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, मैं केवल एक दो बातें कहना चाहता हूं। मैं भी आपके माध्यम से इस बारे में एक डिमांड कर लूंगा। सर, जब चौटाला साहब की सरकार थी तो उस वक्त आपने स्वयं देखा होगा कि पंचकुला में किस प्रकार का स्पोर्टस का स्टेडियम बना था, किस प्रकार

से फरीदाबाद में स्टेडियम बना था, किस प्रकार से गुड़गांव में बहुत अच्छा स्टेडियम बना था लेकिन अब जो स्टेडियम्ज़ बनाए जा रहे हैं वे उस लैवल के नहीं है जो हमारी सरकार के वक्त में थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कैथल में भी एक स्टेडियम्ज़ बनाया जाए। सर, जो गांवों में या शहरों में स्टेडियम्ज़ बनाए जा रहे हैं उनके रखरखाव के लिए किसी प्रकार का कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता और न ही कोचों को कोई ट्रेनिंग दी जाती है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, इनको कैथल में जाकर देखना चाहिए, वहां पर आधा स्टेडियम तो बन भी गया है।

Mr. Speaker : Question is—

> That Demand No.11 of Rs.75,06,59,000/- for revenue expenditure on account of Sports & Youth Welfare be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

> That a sum not exceeding Rs.75,06,59,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No.11 - Sports & Youth Welfare.

The motion was carried.

Demand No. 12

Mr. Speaker : Question is—

> That a sum not exceeding Rs.11,92,27,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No.12-Art & Culture.

The motion was carried.

Demand No. 13

Mr. Speaker : Now, I put cut motion No.5 on Demand No.13 given by Shri Ram Pal Majra, Shri Ashok Kumar Arora and Shri Ajay Singh Chautala, M.L.As to the vote of the House.

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, यह ठीक है कि प्रदेश स्वस्थ होना चाहिए। ये कहते तो हैं कि हमने स्वास्थ्य में बहुत कुछ कर दिया। स्पीकर सर, महिलाओं में आज भी खून की बहुत ज्यादा कमी है। 15 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की महिलाओं में 43 प्रतिशत तक खून की कमी है। गर्भवती महिलाओं के लिए डिलीवरी हटस बनाए तो गए हैं लेकिन आज भी 46.5 प्रतिशत डिलीवरीज़ घरों में ही होती हैं और लगभग 53.5 प्रतिशत ही इंस्टीच्यूशनल डिलीवरी होती हैं। स्पीकर साहब, छोटे बच्चों की मृत्यु दर एक हजार पर 56 है जबकि कुपोषित बच्चों की मृत्यु दर

[श्री राम पाल माजरा]

वर्तमान में 34.6 प्रतिशत है। इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना जो 26 जनवरी को लांच हुई थी, उसके तहत जब छोटे बच्चों का ऐनीमिया टैस्ट हुआ तो 49 प्रतिशत बच्चों में ऐनीमिया पाया गया। सर, जो सरकारी होस्पीटल्ज में दवाई सप्लाई हो रही है उसके भी बहुत से सैम्पल फेल हो गए हैं लेकिन किसी भी प्रकार का ऐक्शन नहीं हो रहा है। दूध की उपलब्धता तो बहुत है लेकिन जब दूध के 1100 सैम्पल भरे गए तो उसमें से 285 सैम्पल फेल हो गए। आज हरियाणा में दूध की तीस प्रतिशत सप्लाई कम है। अध्यक्ष महोदय, आपको पता ही है कि हैल्थ पर बहुत कम खर्चा किया जा रहा है। सरकार द्वारा लाडली योजना, प्रियदर्शनी योजना के तहत लिंगानुपात बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए गए लेकिन उसके बाद भी हरियाणा में एक हजार पुरूषों के पीछे महिलाओं की संख्या केवल 861 हैं जबकि नैशनल लेवल पर यह संख्या 933 है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

बजट 2010-2011 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भण)

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, नौजवानों को अपनी शादी करने के लिए दूसरे स्टेटस में जैसे कभी हिमाचल जाना पड़ता है, कभी बिहार जाना पड़ता है। स्पीकर सर, आपने देखा होगा कि आजकल कबूतरबाजी के कितने केसिज हुए हैं। आपके इलाके में भी ये केसिज बहुत ज्यादा हैं। कैथल, कुरूक्षेत्र और यमुनाभगर में ये केसिज बहुत ज्यादा हैं। दलाल उनसे बीच में दस-दस, पन्द्रह पन्द्रह लाख रूपये लेकर रख जाते हैं। और वे बेचारे फौरेन में भी नहीं जा सकते। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : क्या इस बात का हैल्थ से कोई लिंक है।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं यूं ही नहीं खड़ा हुआ हूं। मेरे पास राष्ट्र की छपी हुई नैशनल रिपोर्ट की किताब है यह मैं आपको दे दूंगा। ये नैशनल हैल्थ रिपोर्ट है इसके ऊपर सब कुछ चलता है और इसके माध्यम से ही इतनी सारी ग्रांट्स आई हुई हैं। इसका जिक्र महामहिम गवर्नर साहब के ऐड्रस में हुआ था। इसमें यह बात कही गई है कि तीन डॉक्टरों पर एक नर्स है और एक सवाल के जवाब में यहां मंत्री जी ने बताया कि डॉक्टर्ज की कमी है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर्ज तो रीसैंटली सिलैक्ट हुए हैं और 50 डॉक्टर्ज हैड ऑफिस में बैठे हुए हैं और वे सभी स्पैशलिस्ट हैं, उनको क्लर्कों का काम दिया हुआ है। आज आप इंक्वायरी करवा लो ऐट दिस टाइम, 50 डॉक्टरर्ज इम्प्लौयड हैं और वे हैड ऑफिस में बैठे हैं। हैड ऑफिस में डॉक्टरों को क्लर्कों का काम दिया हुआ है। हैड ऑफिस में डॉक्टरों का क्या काम है जबकि उनके लिए ये कंडीशन थी कि तीन साल तक गांव में रहेंगे। वे सभी राजनेताओं के बच्चे हैं इसलिए ये वहां बैठे हैं।

Mr. Speaker : Question is —

That Demand No. 13 of Rs. 11,17,12,76,000/- for revenue expenditure on account of Health be reduced by Re. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is —

That a sum not exceeding Rs. 11,17,12,76,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 13 — Health.

The motion was carried.

Demand Nos. 14 to 23

Mr. Speaker: Question is —

That a sum not exceeding **Rs. 97,51,57,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 14 — **Urban Development**.

That a sum not exceeding **Rs. 7,11,11,16,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 15 — **Local Government.**

That a sum not exceeding **Rs. 29,14,36,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 16 — **Labour**.

That a sum not exceeding **Rs. 66,55,47,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 17 — **Employment.**

That a sum not exceeding **Rs. 1,18,87,16,000 for revenue expenditure** and **Rs. 25,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 18 — **Industrial Training.**

That a sum not exceeding **Rs. 1,88,46,11,000 for revenue expenditure** and **Rs. 2,65,60,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 19 — **Welfare of SCs & BCs.**

That a sum not exceeding **Rs. 14,41,17,42,000 for revenue expenditure** and **Rs. 2,86,20,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 20 — **Social Security & Welfare.**

That a sum not exceeding **Rs. 4,69,96,04,000 for revenue expenditure** and **Rs. 75,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 21 — **Women & Child Development.**

That a sum not exceeding **Rs. 47,91,39,000 for revenue expenditure** and **Rs. 40,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 22 — **Welfare of Ex-servicemen.**

That a sum not exceeding **Rs. 2,43,41,19,000 for revenue expenditure** and **Rs. 3816,25,11,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 23 — **Food & Supplies.**

The motion was carried.

Demand No. 24

Mr. Speaker : Now, I put cut motion No. 6 on Demand No. 24 given by Shri Ram Pal Majra, Shri Ashok Arora, Shri Ajay Singh Chautala and Rao Bahadur Singh, MLAs to the vote of the House.

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश की टेलों पर पानी नहीं है और बहुत सी टेलें शॉर्ट हैं। इस सम्बंध में मेरे एक साथी ने विशेष तौर पर गुडगांव कैनाल के बारे में एक प्रश्न पूछ लिया था। जिसके बारे में सदन में बताया गया कि पानी की सप्लाई क्षमला से कम है। स्पीकर सर, यह सरकार पानी की चोरी को भी रोकने में सक्षम नहीं है। एक विधायक को तो इस बारे में अपने आप रेड करनी पड़ी उस बेचारे की जिंदगी बच गई, मैंने इस बारे में अखबारों में पढा था। सर, सतपाल सांगवान को तो इस बात की कोई फिक्र नहीं है। सर, बी.एम.एल. हांसी बुटाना लिंक ब्रांच का अगर हम 10 जनवरी से 16 जनवरी के दौरान पानी का ऐवरेज डेली डिस्चार्ज देखें तो पाएंगे कि इस अवधि में उसमें 4834 क्यूसिक पानी चला और यदि इसे प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो यह 57 प्रतिशत बनता है यानि इसकी क्षमता में 43 प्रतिशत की कमी रही है। एक तारीख से बी.एम.एल. टोहाना टेल पर पानी का डेली डिस्चार्ज 2542 क्यूसिक रहा जो कि 84.70 प्रतिशत बैठता है। इस प्रकार इसमें भी 15 प्रतिशत पानी कम मिला। इस प्रकार से अगर पानी के डेली डिस्चार्ज में कमी होगी तो टेलों पर पानी कैसे पहुंचेगा ? इसी प्रकार खनौरी हैड की पानी की क्षमता की पोजीशन मैं यहां पर नहीं बताउंगा क्योंकि अगर मैं इस बारे में बताने लगूंगा तो काफी समय लग जायेगा। बरवाला ब्रांच की क्षमता भी 55 प्रतिशत ही पूरी हो सकी और पानी के फुल सप्लाई लैवल में 45 प्रतिशत की कमी रही। यदि सारी नहरों के

बारे में मैं यहां बताऊंगा तो काफी समय लग जाएगा फिर भी बालसमंद सब ब्रांच के बारे में मैं जरूर जिक्र करूंगा कि उसको भी अपनी कैपिसिटी से कम पानी मिला। फतेहाबाद जिले को रतिया ब्रांच से जोड़ दिया गया। रोड़ी ब्रांच कैनाल सिरसा जिले को सींचती है, उसका डिस्चार्ज फ्लक्चुएट हुआ और उसमें 362 क्यूसिक्स पानी मिला जो कि 56 प्रतिशत बनता है यानि उसमें भी 44 प्रतिशत की कमी रही। इसी प्रकार जींद, हिसार, भिवानी और रोहतक जिलों को जोड़ने वाली हांसी ब्रांच में 67 प्रतिशत पानी कम मिला। सर, मेरे कहने का भाव यह है कि इसी प्रकार से सारी नहरों में 25 से लेकर 50 प्रतिशत तक पानी कम मिला है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से कहना है कि रेणुका, किसाऊ और लखवार बान्ध बनाने का काम करवाया जाए। यह ठीक है कि इनको नैशनल प्रोजैक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है परन्तु उनमें हमारी हिस्सेदारी तय नहीं हुई है। अभी हिस्सेदारी तय होनी है। हिस्सा तय करने के लिए स्ट्रॉंगली काम करवाने का काम करें। इस प्रकार न हो कि हम कोलैक्टिव रिसपौंस्बिलिटी को भूल जाएं। स्पीकर सर, आपको याद होगा इन्होंने कहा था कि सन् 1993 में कैबिनेट की मीटिंग में यमुना के पानी के बारे में एम.ओ.यू. किया गया था।

श्री अध्यक्ष : माजरा साहब, आप कहां चले गये ? आप क्या बात करते हो, इरीगेशन के बारे में बोल रहे थे और इरीगेशन से हटकर आप कैबिनेट की मीटिंग में चले गये। आप क्या बात करते हो, आप बैठ जाईये। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य कट मोशन पर बोल रहे हैं? ये भाषण देने लग जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप इनका मोशन वोटिंग के लिए रखो। ये वैसे ही सदन का टाईम वेस्ट कर रहे हैं।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं बांध बनाने के लिए बात कर रहा था जिससे यमुना में पानी ज्यादा मिल सके। स्पीकर सर, इन्होंने अपनी जिद में एक क्षेत्र के लोगों का पानी छीनने के लिए और दूसरे क्षेत्र के लोगों को पानी देने के लिए एक नई नहर 400 करोड़ रुपये खर्च करके बना दी। जो कानूनी औपचारिकताएं पूरी न होने की वजह से आज बीच में अटक कर खड़ी हो गई है। (विघ्न)

Mr. Speaker : Thank you very much.

श्री रामपाल माजरा : सर, प्रदेश के लोगों की गाढ़े खून पसीने की कमाई उस पर लगी हुई है। (विघ्न)

Mr. Speaker : Thank you very much.

Mr. Speaker : Question is—

> That Demand No.24 of Rs.11,05,30,70,000/- for revenue expenditure and Rs.436,40,00,000/- for capital expenditure on account of Irrigation be reduced by Rs.1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

> That a sum not exceeding Rs.11,05,30,70,000/- for revenue expenditure and Rs.436,40,00,000/- for capital expenditure be

granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No.24 - Irrigtion.

The motion was carried.

Demand Nos. 25 & 26

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs.69,15,42,000/- for revenue expenditure and Rs. 50,20,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No.25 - Industries.

That a sum not exceeding Rs.14,66,75,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No.26 - Mines and Geology.

The motion was carried.

Demand No. 27

Mr. Speaker : Now, I put cut motion No.7 on Demand No. 27 given by Shri Ram Pal Majra, Shri Ashok Kumar Arora and Shri Ajay Singh Chautala, M.L.As to the vote of the House.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों कानून में संशोधन करके सहकारिता अधिनियम बनाया गया था जिसमें यह कहा गया था कि किसी किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी। उससे लोन की रिकवरी तो होगी लेकिन उसको अन्दर नहीं किया जायेगा। सर, यह कानून को-आप्रेटिव सैक्टर पर ही लागू है। जबकि इस कानून को सभी बैंकों पर लागू किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं आपसे यह कन्ट्रीब्यूट कर रहा था कि इन्होंने लिखा कि माईक्रो न्यूट्रेन खाद के लिए किसान को दो हैक्टेयर के हिसाब से एक हैक्टेयर पर 500 रुपये सब्सिडी दी जायेगी। इससे आगे यह कहा है कि चूंकि जमीन में फर्टीलिटी नहीं रही है इसलिए बंजर जमीन को फर्टाईल करने के लिए 500 रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से, दिए जायेंगे। उसकी लिमिट दो हैक्टेयर से फालतू नहीं होगी। स्पीकर सर, दो हैक्टेयर का मतलब एक हजार रुपये, मैं यह पूछना चाहूंगा कि एक हजार रुपये में कौन सी बंजर जमीन उपजाऊ बन जायेगी। स्पीकर सर, जब इस बार शाहाबाद, करनाल और पानीपत चीनी मिलों में 40, 30 और 20 रुपये के हिसाब से बोनस दिया गया है तो दूसरी मिलों में बोनस क्यों नहीं दिया गया ? जहां यह बोनस नहीं दिया गया वहां के किसानों का क्या कसूर था ? मैं कहना चाहूंगा कि उन मिलों के किसानों को भी बोनस दिया जाना चाहिए था। हरियाणा की सारी शूगर मिलों के लिए एक ही रेट होना चाहिए था। यह नहीं कि गोहाना शूगर मिलों के लिए एक ही रेट होना चाहिए था। यह नहीं कि गोहाना शूगर मिल का कोई रेट, कैथल शूगर मिल का कोई रेट, शाहाबाद शूगर मिल का कोई रेट हो। अध्यक्ष महोदय, कुछ समय के लिए तो एक विशेष मिल को फायदा पहुंचाने के लिए यह कहकर कि हम इसको आगुमैंट कर रहे हैं उस मिल को बन्द कर दिया गया।

Mr. Speaker : Question is—

That Demand No. 27 of Rs. 5,83,66,68,000/- for revenue expenditure on account of Agriculture be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 5,83,66,68,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 27 — Agriculture.

The motion was carried.

Demand Nos. 28 to 33

Mr. Speaker : Question is —

That a sum not exceeding Rs.2,86,50,97,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 28—Animal Husbandry and Dairy Development.

That a sum not exceeding Rs. 24,48,47,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 29 — Fisheries.

That a sum not exceeding Rs.1,94,55,12,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 30 — Forests and Wildlife.

That a sum not exceeding Rs. 3,40,53,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 31 — Ecology & Environment.

That a sum not exceeding Rs. 9,46,27,18,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 32 — Rural and Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 82,25,00,000/- for revenue expenditure and Rs. 13,22,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No. 33 — Cooperation.

The motion was carried.

Demand No.34

Mr. Speaker : Now, I put cut motion No.8 on Demand No.34 given by Shri Ram Pal Majra, Shri Ashok Kumar Arora and Shri Ajay Singh Chautala, M.L.As to the vote of the House.

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, आज बसिज का बहुत अभाव है। आज रोडवेज में कर्मचारियों की भी बहुत कमी है। अगर ये नई बसिज लेकर आएंगें तो कर्मचारियों की भी रिक्रूटमैंट करनी चाहिए। आज अगर हम देखें तो सड़कों पर जीपों में लोग लटके हुए देखे जा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक्सीडैंटस रेट जो ज्यादा हो रहा है उसका भी कारण बसिज की कमी है। ट्रांसपोर्टेशन के मामले के बारे में कहूं तो ट्रांसपोर्ट के मामले में भी हरियाणा प्रदेश की जनता को ये अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नहीं दे पा रहे हैं। आज जब सड़कों पर बच्चे स्कूल जाने के लिए खड़े होते हैं तो बहुत समय तक बसिज नहीं आती। 20-20, 30-30 किलोमीटर तक बसों के ड्राईवर बसिज नहीं रोकते और इन 20-20, 30-30 किलोमीटर तक के सड़कों के रूटस पर बच्चे स्कूलों में जाने से वंचित रहे जाते हैं इसलिए इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

Mr. Speaker : Question is—

That Demand No.34 of Rs.10,61,93,85,000/- for revenue expenditure and Rs.156,02,50,000/- for capital expenditure on account of Transport be reduced by Rs.1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 10,61,93,85,000/- for revenue expenditure and Rs. 156,02,50,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No.34 — Transport.

The motion was carried.

Demand No. 35

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 2,34,63,000/- for revenue expenditure and Rs.18,30,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No.35-Tourism.

The motion was carried.

Demand No. 36

Mr. Speaker : Now, I put cut motion No.9 on Demand No.36 given by Shri Ram Pal Majra, Shri Ashok Kumar Arora and Shri Ajay Singh Chautala, M.L.As to the vote of the House.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा में कानून और व्यवस्था फेल हो गई। इस सरकार के चलते हुए किस प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति है इस बारे में मैं बताना चाहूंगा। आज हरियाणा में डकैती, कत्ल और फिरौती की घटनाएं आम हो गई हैं। मंदिर लूटे जा रहे हैं। मंदिर तो मंदिर अध्यक्ष महोदय, आपके शहर कुरूक्षेत्र में तो शमशान घाट से अर्थी तक को चोर उठाकर ले गए है। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, पुलिस महकमें के लोगों ने किस प्रकार आर्गेनाइज्ड क्राइम किया, किस प्रकार से फिरौती, डकैती की घटनाएं करवाई ? बाद में एस.टी.एफ. को भी बन्द कर दिया गया। इस मामले में पुलिस विभाग के बहुत अधिकारी और कर्मचारी लिप्त हैं इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए and organized by police crime should be prohibited.

Mr. Speaker: Question is—

That Demand No.36 of Rs.14,17,26,57,000/- for revenue expenditure and Rs.130,50,00,000/- for capital expenditure on account of Home be reduced by Rs.1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs.14,17,26,57,000/- for revenue expenditure and Rs.130,50,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No.36 - Home.

The motion was carried.

Demand Nos. 37 to 45

Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs. 30,97,75,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No.37— Elections.

That a sum not exceeding Rs. 6,64,19,00,000/- for revenue expenditure and Rs.649,50,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No.38— Public Health & Water Supply.

That a sum not exceeding Rs. 51,83,47,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No.39—Information & Publicity.

That a sum not exceeding Rs. 29,88,24,27,000/- for revenue expenditure and Rs.1054,77,00,00 for capital expenditure be

granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No.40- Energy & Power.

That a sum not exceeding Rs. 19,58,24,000/- for revenue expenditure and Rs.1,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No.41- Electronics & IT.

That a sum not exceeding Rs. 1,45,81,45,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No.42- Administration of Justice.

That a sum not exceeding Rs. 74,79,01,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No.43- Prisons.

That a sum not exceeding Rs. 37,04,34,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No.44- Printing & Stationery.

That a sum not exceeding Rs.16,02,39,60,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2010-11 in respect of charges under Demand No.45-Loans & Advances by State Government.

The motion was carried.

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the sitting be extended for 10 minutes?

Voices : Yes, Sir.

Mr. Speaker : The time of the sitting is extended for 10 minutes?

वित्त मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): अध्यक्ष महोदय, कल अशोक अरोड़ा जी शंख के बारे में बात कर रहे थे तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रांत में शंखनाद पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत सरकार ने वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के शिड्यूल 1 में शैल्ज और शंखों

की 9 किस्मों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसी अधिनियम के शिड्यूल 4 में भी 15 और किस्मों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। पूजा के लिए जिन शंखों का प्रयोग होता है सभी इन प्रतिबन्धित शंखों में नहीं आते। वन विभाग हरियाणा द्वारा आदेश जारी किए जा चुके हैं कि केवल प्रतिबन्धित शंखों की बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। अन्य शंख जो पूजा में प्रयोग होते हैं उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 26.11.2009 को दो केस दर्ज हुए हैं, उनको चैक करने के लिए कोची भेजा हुआ है कि वे पूजा की श्रेणी में आते हैं या नहीं। वहां से अगर रिपोर्ट आ गई कि ये शंख पूजा की श्रेणी में नहीं आते तो हम इन केसिज पर कार्यवाही कैंसिल कर देंगे।

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 10.00 AM tomorrow the 16th March, 2010.

*19.46 Hrs. (The Sabha then *adjourned till 10.00 A.M. Tuesday, the 16th March, 2010.)

47258—H.V.S.—H.G.P., Chd.